राष्ट्रीय
सहारा
नई दिल्ली • सोमवार • 21 जुलाई • 2025
www.rashtriyasahara.com

बिखरा विपक्ष, मुद्दे ठोस

संसद सत्र से पहले विपक्ष और सत्ता पक्ष अपनी-अपनी रणनीति बनाते हैं। विपक्ष उन मुद्दों पर हमलावर रहता है जिन पर उसे सरकार से ठोस कार्य की उम्मीद होती है, और सत्ता पक्ष विपक्ष के गुस्से को ठंडा करने के उपाय खोजता है। इस बार विपक्ष के हाथ कुछ ऐसे मुद्दे लगे हैं, जिनसे पार पाना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस (इंडिया) के प्रमुख नेताओं ने शनिवार को ऑनलाइन बैठक करके सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर को अचानक रोके जाने, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता संबंधी दावे, बिहार में जारी विशेष गहन

पुनरीक्षण (एसआईआर) और कई अन्य मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी, सपा के रामगोपाल यादव, शिवसेना (उबाठा) के उद्धव ठाकरे, राजद नेता तेजस्वी यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, भाकपा (माले) लिबरेशन महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और कुछ अन्य नेता शामिल हुए। पहलगाम में आतंकी हमले का मुद्दा प्राथमिकता पर रहा। हमला करने वाले आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर के बावजूद अब तक न्याय के कठघरे में नहीं लाया जा सका है। इस पर सभी दलों के नेताओं ने चिंता नाराजगी जताई। ऑपरेशन सिंदूर को एकाएक रोका जाना और युद्धविराम संबंधी ट्रंप के दावों पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सदन का गर्माना अवश्यंभावी है। इस मामले में ट्रंप की बयानबाजी लगातार जारी है। कांग्रेस इस संबंध में चुप्पी की स्थिति बनाए रखने पर प्रधानमंत्री मोदी से जवाब की मांग करेगी। विपक्षी दल निर्वाचन आयोग की मतदाताओं के विशेष निरीक्षण एसआईआर की कवायद पर भी सदन में सवाल उठाएंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे बड़ी संख्या में मतदाताओं के मताधिकार छिन जाने का खतरा है। देश की विदेश नीति, चीन और गाजा के मामले भी सदन में गर्माएंगे। विपक्ष के मुद्दे कितने भी ठोस हों लेकिन सरकार तभी दबाव में आ सकती है जब इंडिया गठबंधन में एका हो। 'आप' शुक्रवार को ही गठबंधन से दूरी बना कर इसमें पलीता लगा चुकी है। बिखराव से सरकार को विपक्ष पर हो-हल्ला मचाने का आरोप मढ़ने का मौका मिल जाएगा।

ट्रंप के दावों में कितना दम

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत-पाक के दरम्यान हुए सैन्य टकराव के दौरान पांच विमान गिराने का नया दावा किया है। फिर दोहराया है कि सैन्य टकराव उनके हस्तक्षेप से समाप्त हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने आधिकारिक आवास व कार्यालय व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन सांसदों को दिए रात्रिभोज में कहा-वे एक-दूसरे पर हमले कर रहे थे। स्थिति गंभीर होती जा रही थी। हमने कहा-आप शायद परमाणु हथियार से हमले करने वाले हैं। ऐसे में हम व्यापार समझौता नहीं कर पाएंगे। भारत ट्रंप के दावे को खारिज

करता रहा है। उसका कहना है कि सेनाओं के बीच सीधी बातचीत के बाद सैन्य कार्रवाइयां रोकी गईं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था जिसमें दोनों मुल्कों के बीच एक-दूसरे पर हमले किए थे। ट्रंप के बयान के बाद मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से सवाल किया कि चौबीसवीं बार ट्रंप के अपना बयान दोहराने के बावजूद वे खामोश हैं। कांग्रेस के संचार प्रमुख जयराम रमेश का कहना है कि मोदी सदन में स्पष्ट बयान दें। विदेश मंत्री जयशंकर हाल में एक साक्षात्कार में स्पष्ट कर चुके हैं कि संघर्षविराम दुतरफा था। हालांकि ट्रंप के ताजा बयान में साफ नहीं है कि किस देश के पांच विमान मार गिराए गए परंतु इस पर तुरंत कोई टिप्पणी न आना संशय पैदा करता है। पाकिस्तान पहले ही दावा कर चुका है कि उनकी सेना ने भारतीय विमान मार गिराए। इसके कई दिनों बाद भी सैन्य प्रवक्ताओं ने नुकसान की पुष्टि नहीं की। अमेरिका द्वारा पहलगाम हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा समर्थक आतंकवादी समूह द रेजिस्टेंस फ्रंट को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने पर भारत अभी खुश हो ही रहा था कि ट्रंप के बयान ने सारा उल्लास काफूर कर दिया। बेशक, मोदी को बगैर देरी के कड़ाईपूर्वक इस छद्म दुष्प्रचार का खंडन करना चाहिए। रक्षा मंत्री को भी निर्देश देना चाहिए कि वे इस पर सेना का पक्ष स्पष्ट करें। हम एक तरफ अमेरिका की आतंकवादरोधी सहयोगी के तौर पर सराहना कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वह जानबूझकर भारत की सैन्य क्षमताओं पर प्रश्न चिह्न लगाने की कूटनीतिक चाल चल रहा है। लड़ाकू विमानों में कोई तकनीकी दिक्कत है, तो उसे समय रहते दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। न कि मुंहदेखी या लीपा-पोती कर बगलें झांकते रहना।

चिंता/मुनीष भाटिया

अधिकारों की आड़ में अराजकता

हर वर्ष देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक यात्रा, जुलूस, प्रदर्शन, आंदोलन और धरने आयोजित होते हैं। श्रावण माह में उत्तर भारत में निकलने वाली कांवड़ यात्रा लाखों श्रद्धालुओं की गहरी आस्था का प्रतीक है, जो भगवान शिव के प्रति उनके समर्पण को दर्शाती है। परंतु जब यही यात्रा अत्यधिक संख्या, सड़कों पर अव्यवस्था, कानफाड़ू डीजे की तेज आवाजों, और कभी-कभी हिंसक झड़पों में बदल जाती है, तो यह धार्मिकता से कहीं अधिक शक्ति प्रदर्शन का रूप ले लेती है। धर्म का मूल भाव संयम, सेवा, और सह-अस्तित्व है। यह सिखाता है कि हम दूसरों के प्रति संवेदनशील रहें और उनके अधिकारों का भी सम्मान करें। ऐसे में सार्वजनिक सड़कों पर अवरोध उत्पन्न करके की जाने वाली प्रार्थना क्या धर्म के इस मूल संदेश का पालन करती है, या केवल असुविधा का कारण बनती है?

इसी प्रकार, विभिन्न सामाजिक संगठनों और राजनैतिक दलों द्वारा किए गए धरना-प्रदर्शन भी गंभीर चिंता का विषय बन चुके हैं। लोकतंत्र में विरोध-असंतोष व्यक्त करने और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का सशक्त माध्यम है परंतु जब यह विरोध रेलें रोकने, सड़क जाम करने और जनता के जीवन को ठप कर देने तक पहुंच जाए तब यह लोकतंत्र की गरिमा का अपमान बन जाता है। इन सभी परिस्थितियों में सबसे बड़ा नुकसान उस आम नागरिक का होता है, जो ईमानदारी से कर देता है, शांति से अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करता है और समाज की व्यवस्था में विश्वास रखता है। यह नागरिक सरकार से अपेक्षा करता है कि वह उसे बेहतर सड़कें, सुरक्षित रेल सेवा और व्यवस्थित जीवन प्रदान करे। लेकिन जब वही नागरिक अपने टैक्स से बनी सड़क पर चल भी न सके, अपने गंतव्य तक पहुंचने में घंटों जाम में फंसा रहे, तब यह पूरी व्यवस्था पर गहरा कटाक्ष जैसा प्रतीत होता है। यह सिर्फ असुविधा नहीं है, बल्कि यह उस नागरिक के आत्मसम्मान और योगदान का भी अपमान है। समय की मांग है कि हम 'सार्वजनिक संसाधनों पर सबका समान अधिकार' की भावना को व्यवहार में लाएं। सड़क, रेल, अस्पताल-ये सब उन करोड़ों नागरिकों के लिए बनाए गए हैं, जो ईमानदारी से देश को चला रहे हैं, कर दे रहे हैं, और शांतिपूर्वक जीवन जी रहे हैं। लोकतंत्र का आधार ही यही है कि सबको समान अवसर और सुविधा मिलें-चाहे वे किसी भी धर्म, जाति, वर्ग या राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हों।

विकट और विकराल समस्या

बेरोजगारी

विनीत नारायण

पिछले दिनों खबर छपी कि उत्तर प्रदेश में 2 हजार पदों के लिए 29 लाख आवेदन प्राप्त हुए। एक बार ऐसी भी खबर आई कि आईआईटी से पास हुए 38 फीसद युवाओं को रोजगार नहीं मिला। अक्सर देखा जाता है कि जब भी कभी कोई सरकारी पद पर भर्ती खुलती है तो कुछ हजार पदों के लिए लाखों आवेदन आ जाते हैं। फिर वो पद छोटा हो या बड़ा, उस पद की योग्यता से अधिक योग्य आवेदक आवेदन देते हैं। बात बिहार की हो, उत्तर प्रदेश या देश में किसी अन्य राज्य की, जब भी एक पद पर उम्मीद से ज्यादा आवेदन आते हैं, तो स्थिति अनियंत्रित हो जाती है।

आज के दौर में अगर 'मेनस्ट्रीम मीडिया' किन्हीं कारणों से ऐसे सवालों को जनता तक नहीं पहुंचाता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि जनता तक वह सवाल पहुंच नहीं पाएंगे। सोशल मीडिया पर ऐसे सैकड़ों इंटरव्यू देखे जा सकते हैं, जो बेरोजगारी की भयावह समस्या से जूझते युवाओं की हताशा दर्शाते हैं। जब ये युवा रोजगार की मांग लेकर सड़कों पर उतरते हैं, तो इन राज्यों की सरकारें पुलिस से इन पर डंडे बरसाती हैं। अगर युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने की भी उम्मीद नहीं होगी तो हार कर उन्हें निजी क्षेत्र में जाना पड़ेगा और निजी क्षेत्र की मनमानी का सामना करना पड़ेगा।

दिक्कत यह है कि निजी क्षेत्र में भी रोजगार की संभावनाएं बहुत तेजी से घटती जा रही हैं। इससे और हताशा फैल रही है। नौकरी नहीं मिलती तो युवाओं की शादी नहीं होती और उनकी उम्र बढ़ती जाती है। समाजशास्त्रीय शोधकर्ताओं को इस विषय पर शोध करना चाहिए कि करोड़ों बेरोजगार युवाओं की हताशा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? देश के आर्थिक-सामाजिक ढांचे को देखते हुए शहरों में अनौपचारिक रोजगार की मात्रा को क्रमशः घटा कर औपचारिक रोजगार के अवसर बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। देश की सिकुड़ती अर्थव्यवस्था के कारण बेरोजगारी खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। एक शोध के अनुसार भवन निर्माण क्षेत्र में 50%, व्यापार, होटल और अन्य सेवाओं में 47%, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र में 39% और खनन क्षेत्र में 23% बेरोजगारी फैल चुकी है। चिंता की बात यह है कि ये वो क्षेत्र हैं, जो देश को सबसे ज्यादा रोजगार देते हैं। इसलिए इन आंकड़ों का प्रभाव भयावह है। जिस तीव्र गति से ये क्षेत्र सिकुड़ रहे हैं, उससे तो और भी तेजी से बेरोजगारी बढ़ने की स्थितियां पैदा हो रही हैं। दो वक्त की रोटी का भी जुगाड़ न कर पाने की हालत में लाखों मजदूर और अन्य लोग जिस तरह लॉकडाउन शुरू होते ही पैदल ही अपने गांवों की ओर चल पड़े थे, उससे इस स्थिति की भयावहता का पता चलता है। उल्लेखनीय है कि दक्षिण एशिया के देशों में

अनौपचारिक रोजगार के मामले में भारत सबसे ऊपर है, जिसका मतलब हुआ कि देश में करोड़ों मजदूर कम मजदूरी पर मुश्किल हालात में काम करने पर मजबूर हैं, जहां इन्हें अपने बुनियादी हक भी प्राप्त नहीं हैं। इन्हें नौकरी देने वाले जब चाहें रखें, जब चाहें निकाल दें क्योंकि इनका ट्रेड यूनियनों में भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अनुसार भारत में 53.5 करोड़ मजदूरों में से 39.8 करोड़ दयनीय अवस्था में काम करते हैं, जिनकी दैनिक आमदनी 200 रुपये से भी कम होती है। इसलिए मोदी सरकार के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली; शहरों में रोजगार के अवसर कैसे बढ़ाए जाएं क्योंकि पिछले 7 वर्षों में बेरोजगारी का फीसद लगातार बढ़ता गया है। दूसरा; शहरी मजदूरों की आमदनी कैसे बढ़ाएं, जिससे उन्हें अमानवीय स्थिति से बाहर निकाला जा सके। इसके लिए तीन काम करने होंगे। भारत में शहरीकरण का विस्तार देखते हुए शहरी रोजगार बढ़ाने के लिए स्थानीय सरकारों के साथ समन्वय करके नीतियां बनानी होंगी। इससे यह लाभ भी होगा कि शहरीकरण से जो बेतरतीब विकास और गंदी बस्तियों का सृजन होता है, उसको रोका जा सकेगा। इसके लिए स्थानीय शासन को अधिक संसाधन देने होंगे। दूसरा; स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन वाली विकासात्मक नीतियां लागू करनी होंगी। तीसरा; शहरी मूलभूत ढांचे पर ध्यान देना होगा जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था भी सुधरे। चौथा; देखा यह गया है कि विकास के लिए आवंटित धन का लाभ शहरी मजदूरों तक कभी नहीं पहुंच पाता और ऊपर के लोगों में अटक कर रह जाता है। इसलिए नगर पालिकाओं में विकास के नाम पर खरीदी जा रही भारी मशीनों की जगह मानव श्रम आधारित शहरीकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा तो शहरों में रोजगार बढ़ेगा। पांचवां; शहरी रोजगार योजनाओं को स्वास्थ्य और सफाई जैसे क्षेत्र में तेजी से विकास करके बढ़ाया जा सकता है क्योंकि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की यह हालत नहीं है कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार दे सके। होती तो वे गांव छोड़ कर शहर नहीं गए होते।

मौजूदा हालात में यह सोचना कि पढ़े-लिखे युवाओं के लिए ऐसी योजना लानी पड़ेगी जिससे इनको भी रोजगार मिल जाए पर ऐसा करने से करोड़ों बेरोजगारों का छोटा सा अंश ही संभल पाएगा जबकि बेरोजगारों में ज्यादा तादाद उन नौजवानों की है, जो आज बड़ी-बड़ी डिग्रियां लेकर भी बेरोजगार हैं। उनका आक्रोश बढ़ चुका है, और सरकारी तंत्र द्वारा नौकरी की बजाय लाठियों ने आग में घी का काम किया है।

कुछ वर्ष पहले सोशल मीडिया पर एक व्यापक अभियान चला कर बेरोजगार नौजवानों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिन को ही 'बेरोजगारी दिवस' के रूप में मनाया था। उस समय इसी कॉलम में मैंने कहा था कि यह एक खतरनाक शुरुआत है जिसे केवल वादों से नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में शिक्षित रोजगार उपलब्ध करा कर ही रोका जा सकता है। मोदी ने 2014 के अपने चुनाव अभियान के दौरान प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार सृजन का अपना वादा निभाया होता तो आज ये हालात पैदा न होते। यहां यह उल्लेख करना भी जरूरी है कि कोई भी राजनैतिक दल, जो अपने चुनाव अभियान में बेरोजगारी दूर करने का सपना दिखाता है, सत्ता में आने के बाद अपना वादा पूरा नहीं करता। इसलिए सभी राजनैतिक दलों को मिल-बैठ कर इस भयावह समस्या के निदान के लिए एक नई आर्थिक नीति पर सहमत होना पड़ेगा जिसके माध्यम से देश की संपदा चंद हाथों में सीमित होने की बजाय उसका विवेकपूर्ण बंटवारा हो।

(लेख में विचार निजी हैं)

दिक्कत यह है कि निजी क्षेत्र में भी रोजगार की संभावनाएं तेजी से घट रही हैं। इससे और हताशा फैल रही है। नौकरी नहीं मिलती तो युवाओं की शादी नहीं होती और उनकी उम्र बढ़ती जाती है। यह शोध का विषय है कि करोड़ों बेरोजगार युवाओं की हताशा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? देश के आर्थिक-सामाजिक ढांचे को देखते हुए

शहरों में अनौपचारिक रोजगार की मात्रा को क्रमशः घटा कर औपचारिक रोजगार के अवसर बढ़ाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए

जल ब्राह्मी-दिमाग से दिल तक

- आयुर्वेद की दुनिया में जल ब्राह्मी को औषधीय गुणों से भरपूर पौधे के रूप में जाना जाता है। नम स्थानों और पानी के आसपास उगने वाली इस छोटी-सी बूटी को निरब्राह्मी या जल नेवरी भी कहते हैं
- जल ब्राह्मी को सबसे ज्यादा दिमागी शक्ति बढ़ाने के लिए जाना जाता है। आयुष मंत्रालय के मुताबिक, ब्राह्मी एक एडोप्टोजेन है। एडोप्टोजेन्स ऐसे प्राकृतिक पदार्थ हैं, जो शरीर और दिमाग को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से उबरने में मदद कर सकता है

(मीडिया इनपुट्स)

दो दशकों से भी ज्यादा समय से हम देख रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मामलों पर सुनवाई को तब ही तेज कर दिया जाता है, जब उन्हें लगता है कि 1) गांधी परिवार को डराया-धमकाया जाए; और 2) टीवी बहसों की दिशा बदली जाए। यह भी गौर करें कि भारत के इतिहास में सबसे अमीर पार्टी कौन है?

सबा नकवी, लेखिका
@_sabanaqvi

अखाड़ा बनने से बचे संसद

मानसून सत्र | प्रमोद भार्गव

21 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र को गर्माए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी समेत लगभग समूचे विपक्ष ने अपने-अपने हथियार भांज लिए हैं। गोया, यह आशंका कायम है कि विपक्षी दल संसद को ठप बनाए रखने में ही अपना समय जाया करेंगे। इस सत्र में लंबे समय तक चलने वाला हंगामा बिहार में मतदाता सूची के गहन परीक्षण को लेकर हो सकता है।

चुनाव आयोग के इस बड़े प्रयास पर समूचा विपक्ष बड़े राजनीतिक संग्राम की तैयारी में जुटा है। लोक सभा चुनाव की तरह एक बार फिर से इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के दल एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक भी की है। इस हंगामे में मुख्य रूप से कांग्रेस, राजद और टीएमसी कार्यस्थगन प्रस्ताव ला सकते हैं। आशंका है कि बिहार में इस साल के अंत में होने वाले चुनाव को लेकर संसद में गतिरोध बनाए रखने की कोशिश युद्धस्तर पर होगी। सत्ता पक्ष के लिए राहत की बात यह है कि निर्वाचन आयोग के बिहार की मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक नहीं लगाई है, इस मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी।

अतएव इस मुद्दे के न्यायालय में विचाराधीन होने के बहाने को सुरक्षा कवच के रूप में भी इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार ने इस सत्र में 8 नये विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किए हैं। इन विधेयकों में मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक, 2025, सार्वजनिक न्यास प्रणाली (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025, भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक, 2025, पुरातत्व धरोहर स्थल और अवशेष (संरक्षण एवं देखरेख) विधेयक, 2025, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 एवं राष्ट्रीय डोपिंग (कचरा) रोधी संशोधन विधेयक, 2025 शामिल हैं। इन पर सहमति बनाए जाने की चर्चा से पहले विपक्ष चाहेगा कि पहलगाम हमले में गुप्तचर तंत्र की नाकामी, सैन्य ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विदेशी हस्तक्षेप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के दावों के बीच सेना के अभियान को क्यों रोका गया जैसे मुद्दों पर दोनों सदनों में चर्चा हो। विपक्ष की मंशा,

मुद्दों की सच्चाई से कहीं ज्यादा सरकार को घेरना है। सत्तारूढ़ पक्ष इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे बता कर चर्चा से बचने की कोशिश कर सकता है।

इन मुद्दों के अलावा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के निवास में लगी आग के दौरान नकद धन राशि जलने के मामले में महाभियोग लाने की पैरवी करने के साथ ही ओडिशा की छात्रा के साथ अत्याचार जैसे मुद्दे भी गरमा सकते हैं। कांग्रेस और राजद मतदाता सूची को लेकर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं जबकि सत्तारूढ़ दल निर्वाचन आयोग की जानकारी के आधार पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की तैयारी कर रहा है। बावजूद तेलुगू देशम पार्टी द्वारा मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण पर सवाल उठाए जाने से सरकार की चुनौतियां बढ़ी हैं। इधर, मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार का ऐसा बयान आया है, जिसे सरकार ढाल बनाने का काम करेगी। उन्होंने कहा है कि बिहार में एसआईआर के तहत मतदाता सूची को दुरुस्त करने के प्रयास में मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी देखने में आई है। बिहार के 7.9 करोड़ मतदाताओं में से महज 6.85 प्रतिशत मतदाताओं ने अब तक एसआईआर के अंतर्गत गणना फार्म नहीं भरे हैं यानी निर्वाचन आयोग ने अंतिम तिथि से 9 दिन पहले ही 93 फीसद काम पूरा कर लिया है। दरअसल, विपक्ष चिंतित है, क्योंकि पहली बार बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के नाम मतदाता सूचियों से हटाए जाने की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू हुई है।

अतएव प्रस्तावित विधेयकों की बजाय मतदाता सूची पर ज्यादा हंगामा होना तय है। संसद में राजनीतिक गतिरोध बना रहता है और संसद अखाड़े में तब्दील हुई तो उन विधेयकों और अधिनियमों पर बारीकी से बहस संभव न होगी जो देश की जनता की भलाई के लिए कानून बनने हैं। प्रत्येक सांसद का दायित्व बनता है कि विधेयकों के प्रारूप का गंभीरता से अध्ययन करे जिससे यह समझा जा सके कि उनमें शामिल प्रस्ताव देश व जनता के हित से जुड़े हैं अथवा नहीं? लेकिन राज्य सभा और लोक सभा का दुर्भाग्य है कि ज्यादातर सांसद अधिनियम के प्रारूप पर चर्चा करने की बजाय ऐसे मुद्दों को बेवजह बीच में घसीट लाते हैं, जिनसे उनकी क्षेत्रीय राजनीति चमकती रहे। ऐसी स्थिति सत्तारूढ़ सरकार के लिए लाभदायी होती है क्योंकि वह बिना बहस-मुबाहिसे के ही ज्यादातर विधेयक पारित करा लेती है जबकि विपक्ष सार्थक बहस करने की बजाय सरकार को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश में लगा रह कर संसद का समय जाया कर देता है। प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा की दृष्टि से यह स्थित देश हित में नहीं है। लिहाजा, सरकार और सभी दलों का कर्त्तव्य है कि राजनीतिक गतिरोध का समाधान, राजनीतिक तौर-तरीकों से ही निकालें।

युद्धोन्माद | श्रीराम शर्मा आचार्य

युद्धोन्माद का वातावरण बनाने और सरंजाम जुटाने में किसी वर्ग विशेष को लाभ-ही-लाभ सूझा होगा अन्यथा उस आक्रमण-प्रत्याक्रमण के माहौल से असंख्य मनुष्यों की, परिवारों की भयंकर बरबादी सूझ ही न पड़ती, ऐसी बात नहीं है। अपने को सर्वसमर्थ, सर्वसंपन्न बनाने के लिए उभरे उन्माद ने शोषण से लेकर आक्रमण तक के अनेक कुचक्र रचे हैं। इतना दुस्साहस तभी बन पड़ा जब उसने अपनी चेतना को इतना निष्ठुर बना लिया। अन्यान्यों को इस त्रास से भारी कष्ट सहना पड़ सकता है, इसको दरगुजर करने के उपरांत ही अपराधी, आक्रामक एवं आतंकवादी बना जा सकता है। अपनी आर्थिक बरबादी और बच्चों की अनगढ़ जिंदगी के लिए भी अपने को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। दोष-घटनाओं को ही देख कर निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए। सोचना यह भी चाहिए कि अवांछनीयताओं का यह प्रवाह प्रचलन, जिस भावना क्षेत्र की विकृति के कारण उत्पन्न होता है, उस पर रोकथाम के लिए भी कुछ कारगर प्रयत्न किया जाए। संवेदनाओं में करुणा का समावेश होने पर दूसरे भी अपने जैसे दीखने लगते हैं। कोई समझदारी के रहते, अपनों पर आक्रमण नहीं करता, अपनी हानि सहन नहीं करता। इसी प्रकार यदि वह आत्मभाव समूचे समाज तक विस्तृत हो सके तो किसी को भी हानि पहुंचाने, सताने की बात सोचते ही हाथ-पैर कांपने लगेंगे। अपने आपे को दैत्य स्तर का निष्ठुर बनाने के लिए ऐसा कोई व्यक्ति तैयार न होगा, जिसकी छाती में हृदय नाम की कोई चीज है। जिसने अपनी क्रिया को, विचारणा को मात्र मशीन नहीं बनाया होता, वरन उनके साथ उस आत्मसत्ता का भी समावेश किया होता; तो आत्मीयता करुणा, सहकारिता और सेवा-साधना के लिए निरंतर आकुल-व्याकुल रहती। समस्याओं का तात्कालिक समाधान तो नशा पीकर बेसुध हो जाने पर भी हो सकता है। जब होश-हवास ही दुरुस्त नहीं, तो समस्या क्या? और उसका समाधान खोजने का क्या मतलब? पर जब मानवी गरिमा की गहराई तक उतरने की स्थिति बन पड़े तो फिर माता जैसा वात्सल्य हर आत्मा में उभर सकता है, और हित साधना के अतिरिक्त और कुछ सोचते बन ही नहीं पड़ता। तब उन उलझनों में से एक भी बच नहीं सकेगी, जो आज हर किसी को उद्विग्न-आतंकित किए हुए हैं।

रीडर्स मेल

जीवट के पर्याय थे फौजा सिंह

देश और दुनिया के लाखों लोगों की प्रेरणा रहे भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक फौजा सिंह की 114 वर्ष की उम्र में सड़क दुर्घटना में मृत्यु सभी भारतीयों के लिए दुख की घड़ी है। कल्पना से परे है कि 114 वर्ष के फौजा सिंह ने धावक के रूप में अनेक विश्व कीर्तिमान स्थापित किए। 2003 में टोरंटो मैराथन में 52 वर्ष की आयु में ऐतिहासिक दौड़ लगा कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। दुनिया की सुप्रसिद्ध खेल सामग्री बनाने वाली एडिडास ने सुप्रसिद्ध खिलाड़ी डेविड बेकहम और मोहम्मद अली के साथ फौजा सिंह को भी खड़ा किया था ब्रांड एंबेसेडर के रूप में। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने फौजा सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सही मायने में फौजा सिंह का मूल्यांकन करें तो फौजा सिंह जिंदादिल, जुनून, जिद और जीवट के पर्याय थे।

वीरेन्द्र कुमार जाटव, दिल्ली

पीढ़ियों के बीच संवादहीनता घातक

बदलते सामाजिक रिश्तों की त्रासदी गुरुग्राम में टेनिस खिलाड़ी राधिका की पिता द्वारा हत्या के रूप में सामने आई है। यह हत्या पीढ़ियों के बीच संवादहीनता और असहिष्णुता का भयावह परिणाम है। इसमें 'बेटी की कमाई खा रहा है' जैसी टिप्पणियों और राधिका का अपना टेनिस अकादमी चलाना पारिवारिक तनाव का मुख्य कारण बना। इस दर्दनाक घटना से नई पीढ़ी की आजादी और पुरानी पीढ़ी के परंपरागत मूल्यों के बीच गहराते फासलों का पता चलता है। पिता द्वारा बेटी की हत्या की घटना न केवल निंदनीय है, बल्कि यह हमारे समाज में बढ़ते आक्रोश और असुरक्षा की चेतावनी को भी बयां करती है। ऐसी घटनाओं से सबक लेकर परिवार के स्तर पर बेहतर समझ और समर्थन का वातावरण तैयार करना होगा। घटना से स्पष्ट है कि यदि पीढ़ियों के बीच समझदारी और सम्मान का सेतु नहीं बना तो भविष्य और भी भयावह हो सकता है।

अमृतलाल मारू 'रवि', इंदौर

अमेरिका की चिंता का सबब

नाटो प्रमुख मार्क रूटे द्वारा भारत को रूस से तेल आयात जारी रखने पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगा देने का बयान अमेरिका सहित कई यूरोपीय देशों के दोहरे रवैये और वैश्विक जगत में बढ़ती भारत की साख से उत्पन्न हुई चिंता को दर्शाता है। यूरोप के कई देश स्वयं रूस से तेल और गैस का आयात करते हैं, लेकिन वैश्विक प्रतिस्पर्धा में स्वयं को भारत से भविष्य में पिछड़ जाने की चिंता से बौखला गए हैं। उनकी बौखलाहट का सबसे बड़ा कारण भारत सरकार द्वारा 'मेक इन इंडिया' और 'वोकल फॉर लोकल' को बढ़ावा देना है, जिससे स्वदेशी निर्माण इकाइयों को प्रोत्साहन मिले और देश का पैसा देश में ही रहे और साथ ही निर्यात को भी गति प्राप्त हो ताकि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भी वृद्धि हो सके। सरकार की इस पहल का लाभ भी हमें देखने को मिल रहा है। देश रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है जिससे वे देश जो भारत को एक समय में महंगे हथियारों का निर्यात करते थे, भारत के आत्मनिर्भर बन जाने से उनके सामने वैश्विक प्रतिस्पर्धा में योग्य विकल्प खड़ा हो गया है। जिस प्रकार से अमेरिका विश्व के कई देशों को अपनी शर्तों पर उनकी राष्ट्रीय नीतियां बनाने हेतु जोर दे रहा है, उससे यह और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है कि वह समूचे विश्व को एक ध्रुवीय कर शक्ति का केंद्र बने रहना चाहता है, और उसकी इस राह में सबसे बड़ी बाधा रूस और भारत हैं।

पारस जैन, मेरठ

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया काज़ी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3, 4 सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा कक्ष 1209-1210, बाराखम्बा टावर, नजदीक हाउस, 21 के.जी. मार्ग नई दिल्ली से प्रकाशित। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* । दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 011-23352369, 011-23352372, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750

किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके जवाबों से नहीं, बल्कि उसके सवालों से करें। -वोल्टेयर

जमालुद्दीन उर्फ छांगुर के मामले में धर-पकड़ चल ही रही थी कि अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने धर्मांतरण के बड़े गिरोह का भंडाफोड़ कर देश में सुनियोजित ढंग से चल रहे धर्म परिवर्तन को उजागर किया है। सवाल सिर्फ एक छांगुर का नहीं, इसलिए प्रशासन और समाज को इस मामले में निरंतर सतर्क रहने की जरूरत है।

धर्मांतरण और चेतावनी

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के जमालुद्दीन उर्फ छांगुर के मामले में अभी धर-पकड़ चल ही रही थी कि अब प्रदेश पुलिस द्वारा अवैध रूप से धर्मांतरण कराने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश देश में सुनियोजित तरीके से चल रहे धर्म परिवर्तन की गंभीरता की ओर इशारा करता है। छह राज्यों में फैले अवैध धर्मांतरण और कट्टरपंथी नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने मिशन अस्मिता के तहत दस आरोपियों को गिरफ्तार करने की जो कार्रवाई की है, उसकी शुरुआत मार्च में आगरा से दो बहनों के लापता होने से हुई, जिसने एक संगठित और खतरनाक साजिश को उजागर किया है। यह नेटवर्क केवल धर्मांतरण तक सीमित न रहकर, इसके जरिये युवाओं को कट्टरपंथ के लिए उकसाने और उन्हें देशविरोधी एजेंडे से जोड़ने का काम कर रहा था, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी एक बेहद अहम मामला है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इस नेटवर्क का संपर्क लश्कर-ए-ताइबा से भी है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ये मामले तो सामने आ गए, वरना न जाने कितने छांगुर और धर्मांतरण के अवैध नेटवर्क अब भी देश में चल रहे होंगे। दशक भर से ज्यादा समय से छांगुर भी अपने गैर-कानूनी धंधे चला ही रहा था, क्या प्रशासन को इसकी भनक नहीं होगी? मुख्यमंत्री कितने ही बेहतरीन प्रबंधक हों, काम तो उन्हें भी प्रशासनिक अमले से ही कराना है। इसलिए, जरूरी है कि उन अधिकारियों व प्रशासकों पर भी कठोर कार्रवाई हो, जिनकी बदौलत ऐसे नेटवर्कों को पनपने का मौका मिलता है। इन कार्रवाइयों को केवल गिरफ्तारियों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, ये समाज और प्रशासन के लिए एक चेतावनी भी है कि ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए निरंतर सतर्क और समन्वित प्रयास किए जाएं। विशेष चिंता का विषय यह भी है कि इस नेटवर्क द्वारा व्हाट्स एप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और कोड वर्ड्स के जरिये कट्टरपंथी संदेश प्रसारित किए जा रहे थे। लिहाजा केंद्र व राज्य सरकारों को डिजिटल प्लेटफॉर्मों और विदेशी फंडिंग के दुरुपयोग को रोकने के लिए मजबूत तंत्र विकसित करना चाहिए। जिस तरह से छह राज्यों से आरोपी पकड़े गए हैं, उससे यह भी साफ है कि अन्य राज्य सरकारें भी ऐसे संगठनों पर नजर रखें और आपसी सहयोग बढ़ाएं। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों को भी इस नेटवर्क के अंतरराष्ट्रीय पहलुओं की जांच करनी चाहिए, क्योंकि धर्मांतरण और कट्टरपंथ, अक्सर विदेशी फंडिंग और बाहरी एजेंडे से प्रेरित होते हैं। समाज को भी धार्मिक व सामाजिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने की दिशा में काम करना होगा, ताकि ऐसी साजिशों के लिए कोई जगह ही न बचे।

सवाल जो पूछे जाने चाहिए

आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। सांसदों को ऑपरेशन सिंदूर मामले में ट्रंप के दावों, विमान दुर्घटना, मुद्रास्फीति, एमएसएमई के हाल तथा पुलों व गड्ढों के बारे में सार्थक चर्चा करनी चाहिए। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए शासन-व्यवस्था और बुनियादी सेवाओं की खामियों को दूर करना होगा।

शंकर अय्यर
वरिष्ठ पत्रकार

आज से संसद का महत्वपूर्ण मानसून सत्र शुरू हो रहा है। सैद्धांतिक रूप से संसद वह जगह है, जहां सांसद विभिन्न मुद्दों पर चर्चा और बहस करके कानून बनाते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि वे मतदाताओं के बजाय सिर्फ पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं—17वीं लोकसभा में, 15 में से 11 सत्र समय से पहले ही स्थगित कर दिए गए थे। आने वाले हफ्तों में ही पता चलेगा कि क्या इस सत्र में महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाएंगे, या यह राजनीतिक बयानबाजी का अखाड़ा बनेगा। उम्मीद है कि सांसद न सिर्फ सवाल उठाएंगे, बल्कि जवाबों को भी प्रश्नांकित करेंगे! यहां कुछ मुद्दे दिए गए हैं, जिन पर मानसून सत्र में ध्यान देने की जरूरत है।

ऑपरेशन सिंदूर- इस सत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पर मुख्य रूप से चर्चा हो सकती है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह पहला मानसून सत्र है। सरकार से उम्मीद है कि वह खुफिया विफलता, सुरक्षा चूक, आतंकवादी के पकड़े जाने और चार दिनों तक चली मुठभेड़ पर जवाब देगी। युद्धविराम पर सबका ध्यान है। क्या यह युद्धविराम थोपा गया था, जिसको लेकर भारत के इन्कार के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार-बार दावा कर रहे हैं? युद्धविराम का समय महत्वपूर्ण है, लेकिन कब, कैसे और किसने इसमें मध्यस्थता की, इससे परे यह सवाल भी है कि अमेरिका ने हस्तक्षेप क्यों किया। क्या इसका कारण नूर खान एयरबेस पर ब्रह्मोस का हमला ही था? क्या नूर खान एयरबेस स्थित पाकिस्तानी परमाणु स्थल और प्रणालियां अमेरिकी नियंत्रण में हैं, जैसा कि पाकिस्तानी विशेषज्ञों का दावा है और यदि ऐसा है, तो भारत की सुरक्षा के लिए इसका क्या मतलब है?

एयर इंडिया विमान दुर्घटना- अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया विमान दुर्घटना, जिसमें 260 लोगों की जान चली गई, हाल के विमानन इतिहास की सबसे भीषण दुर्घटना है। यह दुर्घटना कैसे और क्यों हुई, यह एयर इंडिया और संकटग्रस्त बोइंग, दोनों के लिए अहम है। इस दुर्घटना की जांच करने वाली भारतीय वायु दुर्घटना जांच ब्यूरो ने एक प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कॉकपिट में हुई बातचीत के अंशों के आधार पर पायलटों पर दोष मढ़ा गया। आखिर पूरी बातचीत क्यों नहीं जारी की गई? क्या गलती के बारे में अनुमान लगाकर प्रारंभिक रिपोर्ट जारी करना और फिर स्पष्टीकरण जारी करना सामान्य बात है? क्या यह रिपोर्ट अमेरिकी मीडिया में लीक हुई, और किसने ऐसा किया? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा एयरलाइनों को ईंधन स्विच की जांच करने के निर्देश का क्या मतलब है? 35 करोड़ से ज्यादा लोग हर साल हवाई यात्रा करते हैं, इसके बारे में वे स्पष्टता और जवाबदेही के हकदार हैं।

मुद्रास्फीति का परिदृश्य- इस सप्ताह के शुरू में, सांख्यिकी मंत्रालय ने जून के लिए खुदरा मुद्रास्फीति दर (2.1 प्रतिशत) जारी की, जिसमें जोर देकर कहा गया, 'यह जनवरी, 2019 के बाद वर्ष-दर-वर्ष सबसे कम मुद्रास्फीति है।' इनसे परे, सवाल यह उठता है कि ऐसा महसूस क्यों नहीं होता! दरअसल, रिजर्व बैंक के घरेलू मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण से पता चलता है कि 80 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि मुद्रास्फीति बढ़ेगी और 54 प्रतिशत से ज्यादा का मानना है कि यह और तेजी से बढ़ेगी। तथ्य यह है कि सेवाओं की लागत बढ़ रही है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में गिरावट मुख्यतः सब्जियों और दालों की कम कीमतों के कारण है। तेल की कीमतें 17.7 प्रतिशत, फलों की कीमतें 12.5 प्रतिशत और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों की कीमतें 14.7 प्रतिशत बढ़ी हैं।

सांसदों को स्पष्ट रूप से पूछना चाहिए कि सरकार ने मुद्रास्फीति को कम करने के लिए क्या किया और इसे कम रखने की क्या योजना है, यदि निश्चित रूप से यह सब आंकड़ों का संयोग न हो।

बजट के वादे- फरवरी में सरकार ने सूक्ष्म उद्यमों को आसानी से कर्ज उपलब्ध कराने के लिए उद्यम क्रेडिट कार्ड की घोषणा की थी। बजट भाषण में कहा गया था कि उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों को पांच लाख रुपये तक का क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा और पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। उद्यम पोर्टल पर 2.7 करोड़ से ज्यादा सूक्ष्म उद्यम पंजीकृत हैं। एमएसएमई का सकल घरेलू उत्पाद में 30 प्रतिशत, विनिर्माण में 45 प्रतिशत और निर्यात में 48 प्रतिशत योगदान है। क्या सांसद पूछ सकते हैं कि अप्रैल से जून के बीच कितने कार्ड जारी किए गए हैं?

जहां एमएसएमई संघर्ष कर रहे हैं, वहीं सरकारी स्वामित्व वाली एमटीएनएल पर लगातार देनदारी बढ़ रही है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, उस पर सात सरकारी बैंकों के 8,585 करोड़ रुपये बकाया हैं। एमटीएनएल और बीएसएनएल को मिलाकर कुल 72,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का घाटा हो चुका है। बजट में विनिवेश के लिए 47,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है। इस मामले में क्या प्रगति हुई है?

पुल और गड्ढे- शायद ही कभी कोई राष्ट्र अपने पुलों और राजमार्गों की हालत देखकर इतना हैरान हुआ हो। इस महीने की शुरुआत में, वडोदरा में एक पुल ढहने से 21 लोगों की मौत हो गई थी। नए बने राष्ट्रीय राजमार्ग बह गए हैं। शहर की सड़कें और एक्सप्रेस-वे गड्ढों से भरे पड़े हैं। लगभग हर शहर हर साल गड्ढों को भरने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च करता है। समस्या की गंभीरता ने इस बारे में पोस्ट और नागरिक सक्रियता की बाढ़ ला दी है।

सांसदों को सबसे पहले पुल ढहने की घटनाओं पर स्थिति रिपोर्ट मांगनी चाहिए-पुलों की स्थिति का आकलन करने और समाप्ति तिथियां निर्धारित करने के मंत्रालय के 2016 के वादे का क्या हुआ? भारत को देश भर में गड्ढों पर किए जाने वाले खर्च पर एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और एक तकनीकी समिति का गठन करना चाहिए, जो घटिया सड़क निर्माण के कारणों की पहचान करे। पुलों, हवाई अड्डों और सड़कों में मौजूद संरचनात्मक खामियों की भयावहता राष्ट्रीय शर्मिंदगी का विषय है।

विकास की पुरानी कहावत कहती है कि जिसे मापा जा सकता है, उसे बेहतर बनाया जा सकता है। विकसित राष्ट्र का दर्जा पाने के लिए भारत को सबसे पहले शासन-व्यवस्था और बुनियादी सेवाओं की आपूर्ति की खामियों को दूर करना होगा।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

जोसेफ मर्फी

आंतरिक मन ही एकमात्र रचनात्मक शक्ति है। बाह्य संसार में आपको जितनी भी चीजें मिलती हैं, ये सभी मन के अंदरूनी संसार की उपज हैं, चाहे आपने यह काम सचेतन रूप से किया हो या अचेतन रूप से।

अंदर की दुनिया से ही बाहर की दुनिया बनती है

कल्पना करें कि आपका अवचेतन मन उपजाऊ मिट्टी है, जो सभी तरह के बीजों को उगने में मदद करेगी, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। अगर आप कांटे बोते हैं, तो क्या आपको अंगूर मिल सकते हैं? अगर आप कंटीली झाड़ियां बोते हैं, तो क्या आपको अंजीर की फसल मिल सकती है? हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण करें। ऐसा करने पर ही इच्छित परिणाम मिल सकते हैं।

इसी समय शांति, खुशी, सही कर्म, सद्भावना और समृद्धि के विचारों के बीज बोना शुरू कर दें। शांति और विश्वास से इन चीजों के बारे में सोचें। अपने चेतन तार्किक मन में इन्हें पूरी तरह स्वीकार करें। इन अद्भुत विचार-बीजों को अपने मस्तिष्क के बगीचे में बोते रहें; आपको बहुत बढ़िया फसल मिलेगी। जब आपका मस्तिष्क सही तरीके से सोचता है, जब आप सच्चाई समझ लेते हैं, जब आपके अवचेतन मन तक पहुंचे विचार सृजनात्मक, सद्भावनापूर्ण और शांतिपूर्ण होते हैं, तो आपके अवचेतन की जादुई कार्यकारी शक्ति प्रतिक्रिया करेगी। यह उस विचार के लिए आवश्यक परिस्थितियों और उचित माहौल का निर्माण कर देगी। अपनी विचार प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के बाद आप किसी भी समस्या या मुश्किल में अपने अवचेतन मन की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। वास्तव में आप जान-बूझकर हुए उस असीमित शक्ति और अटूट नियम के साथ सहयोग कर रहे हैं, जो सभी चीजों पर लागू होता है।

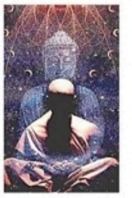

अपने चारों तरफ देखें। आप चाहे जहां रहते हों, आपकी सामाजिक स्थिति चाहे जैसी हो, आप देखेंगे कि अधिकांश लोग बाहर की दुनिया में जीते हैं। जबकि, ज्यादा ज्ञानी लोग अपने अंदर की दुनिया में जीते हैं। उन्हें यह एहसास है-जो आपको भी होगा कि अंदर की दुनिया से ही बाहर की दुनिया उत्पन्न होती है। आपके विचार, भावनाएं और सपने आपके अनुभव के जनक हैं।

आंतरिक मन ही एकमात्र रचनात्मक शक्ति है। बाह्य संसार में आपको जितनी भी चीजें मिलती हैं, वे सभी मन के अंदरूनी संसार की उपज हैं, चाहे आपने यह काम सचेतन रूप से किया हो या अचेतन रूप से। जब आप अपने चेतन और अवचेतन मन की आपसी कार्यविधि के बारे में सच्चाई जान लेंगे, तो अपने जीवन की कायापलट करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप बाहरी स्थितियों को बदलना चाहते हैं, तो आपको उनके कारणों को बदलना होगा।

अधिकांश लोग परिस्थितियों और स्थितियों से संघर्ष करके उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं। यह समय और मेहनत की भयंकर बर्बादी है। वे यह नहीं देख पाते हैं कि ये स्थितियां और परिस्थितियां किसी कारण से उत्पन्न हुई हैं। अपने जीवन से मनमुटाव, दुविधा, कमी और सीमा को दूर करने के लिए आपको उसके मूल कारण को दूर करना होगा। कारण है वह तरीका, जिससे आप अपने चेतन मन का प्रयोग करते हैं; वे विचार और तस्वीरें, जो आप इसमें भरते हैं। कारण को बदल दें, परिणाम अपने आप बदल जाएगा। यह इतना ही आसान है।

सकारात्मक बनें

सूत्र

हमारा अवचेतन मन चेतन विचारों के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। ये चेतन विचार सांचे की तरह काम करते हैं, जिनमें अवचेतन का असीमित ज्ञान, बुद्धि, जीवन-शक्ति और ऊर्जा प्रवाहित होती है। अगर सांचे को सकारात्मक बना दें, तो इस असीमित ऊर्जा से अधिक लाभ हो सकता है।

दूसरा पहलू

छत्तीसगढ़ की श्रीजन कल्याण समाजसेवी संस्था भेदभाव खत्म कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में लगी है।

जहां महिलाएं रच रहीं एक नई इबारत

छत्तीसगढ़ की श्रीजन कल्याण समाजसेवी संस्था की हेमलता राजपूत कहती हैं कि 'गांवों में अब भी महिलाओं के साथ कई तरह के भेदभाव होते हैं। ये आम तौर पर परिवार और समाज में देखने को मिलते हैं। इसी के मद्देनजर हमारी संस्था ने भेदभावों के खिलाफ अभियान छेड़ा है और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की भी कोशिश हो रही है।' इस बदलाव की शुरुआत वर्ष 2016 से हुई है, लेकिन हेमलता, संस्था के गठन के पहले से ही इस दिशा में सक्रिय रही हैं।

बाबा मायाराम

संस्था द्वारा कानूनी मार्गदर्शन केंद्र चलाया जाता है, जहां लोगों की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की जाती है।

छत्तीसगढ़ पारिस्थितिकीय और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। मध्य क्षेत्र का मैदानी भाग, जहां से महानदी गुजरती है, धान का इलाका है। यहां राइस मिलें हैं। हेमलता बताती हैं, 'समाज की सोच गैर बराबरी पैदा करती है, जिसे हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार, समाज और स्वैच्छिक संगठनों के प्रयास से इसमें सुधार आ रहा है।'

संस्था द्वारा कानूनी मार्गदर्शन केंद्र चलाया जाता है, जिसमें लोग समस्याएं लेकर आते हैं। परिवार से मिलकर पूरे मामले की जानकारी ली जाती है। परिवार व समाज के स्तर पर मामला सुलझाने की कोशिश की जाती है, अगर वहां मामला नहीं सुलझा, तो परिवार परामर्श केंद्र या कोर्ट भेजा जाता है।

संस्था ने जैविक खेती को पुनर्जीवित करने का भी काम किया है। इसने किसानों को जंगल को हरा-भरा करने, पारंपरिक बीज संरक्षण, जैविक खाद-कीटनाशक बनाने की दिशा में प्रेरित किया है।

संस्था ने जैविक खेती को पुनर्जीवित करने का भी काम किया है। इसने किसानों को जैविक खेती, प्राकृतिक खेती करने, जंगल को हरा-भरा करने, पारंपरिक बीज संरक्षण, जैविक खाद, जैव कीटनाशक बनाने की दिशा में प्रेरित करने का काम किया है। कुहरी गांव की कौशल्या बाई कहती हैं कि देसी बीजों में रोग ज्यादा नहीं लगता है, खाने में भी स्वादिष्ट होते हैं। अगर फसलों में कीट प्रकोप लगता भी है, तो जैव कीटनाशक बनाकर छिड़कते हैं, जिसे वे स्थानीय पौधों की पत्तियों से तैयार कर लेते हैं। करां, आक, नीम, कड़वा रोहना, बिरहा आदि की पत्तियों से जीवामृत बनाया जाता है। बोदरा गांव की श्यामा ध्रुव बताती हैं कि हम देसी बीजों के साथ धान की खेती करते हैं। रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिससे हमारी लागत भी कम हो जाती है। इससे हमें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिली है।

कुल मिलाकर, घरेलू हिंसा के खिलाफ अभियान, स्वास्थ्य जागरूकता, किचन गार्डन, जैविक खेती, सामुदायिक वन अधिकार दिलवाने में मदद करना और महिला नेतृत्व को गांवों में उभारने की कोशिश करना संस्था का काम है। हेमलता राजपूत कहती हैं कि अगर आधी आबादी सशक्त बनेगी, तो परिवार और समाज भी सशक्त होगा। यह पहल सराहनीय होने के साथ प्रेरणादायक भी है।

आंकड़े

प्रति व्यक्ति चीनी खपत

भारत में प्रति व्यक्ति चीनी की खपत प्रतिवर्ष 2-4 फीसदी की दर से बढ़ रही है, लेकिन अब भी यह वैश्विक औसत से कम है।

2022	20.0
2018	19.5
2015	19.8
2013	17.9
2011	16.5

आंकड़े -प्रति व्यक्ति किलोग्राम में सालाना | स्रोत : ISMA

प्रेम की पराकाष्ठा में दीवानापन प्रारंभ हो जाता है। यही जुनून ईश्वर के लिए पैदा हो जाए, तो जीवन सफल हो जाता है।

ईश्वर की दीवानगी

एक बार की बात है। रामकृष्ण परमहंस श्रीकृष्ण नाम संकीर्तन के दौरान बहुत भावुक हो गए। वह काफी देर तक मग्न होकर नृत्य करते रहे और फिर समाधि में लीन हो गए। जब उनकी चेतना लौटी, तो उन्होंने भक्तों की ओर मुस्कराकर देखा और कहा, राधा और गोपियों का अनुराग कितना अनोखा था। एकदम प्रेमोन्माद!

वहां उपस्थित एक भक्त ने कहा, जी हां, प्रेम में भी एक पागलपन होता है। कहते हैं कि गौरांग (चैतन्य महाप्रभु) का भी यही हाल था। वह भी प्रेम में इतने विभोर हो जाते थे कि सुध-बुध खो बैठते थे। तभी तो किसी भी वन को देखकर उसे वृंदावन और समुद्र को देखकर उसे यमुना समझ बैठते थे।

रामकृष्ण परमहंस श्रीकृष्ण के प्रेम में विह्वल होते हुए बोले, अहा! प्रेम की एक बूंद भी अगर किसी को मिल जाए, तो यही सच्चा अनुराग है। ऐसे अनुरागी को संसार पागल कहता है।

अंतर्यात्रा
संकलित

वहां उपस्थित सभी भक्त उनकी प्रेम वाणी सुनकर भावुक हो उठे। रामकृष्ण परमहंस ने उनसे कहा, अगर हमें दीवाना ही होना है, तो संसार की चीजों के लिए क्यों दीवाने हों, क्यों न ईश्वर के लिए दीवाने हो जाएं। सच ही कहा गया है कि प्रेम की पराकाष्ठा में दीवानापन प्रारंभ हो जाता है। यही दीवानापन ईश्वर के लिए पैदा हो जाए, तो जीवन सफल हो जाता है।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 3 जुलाई, 2006

अग्रिम मोर्चे पर हो महिलाओं की तैनाती

महिलाएं अग्रिम मोर्चों पर तैनात की जाएं: आयोग

सेना में महिला सैनिकों की भूमिका पर उठे विवाद के बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं को युद्ध में उतारने की पैरवी की है। आयोग की अध्यक्ष गिरिजा व्यास स्वयं रक्षा मंत्री को इस पर सिफारिशें सौंपने वाली हैं।

वक्त है कि पुलिस खुद को फिर से गढ़े

पुलिस सुधार इसलिए भी जरूरी है, ताकि इसे बदलते समय के अनुरूप और प्रभावी बनाया जा सके।

ओपी सिंह | **प्रशासन**

भारतीय पुलिस को लेकर आम जनमानस में मिश्रित धारणा है। जब कोई संकट आता है—दंगा हो, सड़क दुर्घटना, चोरी या प्राकृतिक आपदा हो, तो सबसे पहले जो संस्था पहुंचती है, वह पुलिस होती है। तमाम सीमाओं और दबावों के बीच पुलिस ने इस देश में व्यवस्था को संभाले रखा है। न उसकी ड्यूटी का समय तय है, न कार्य का स्वरूप...फिर भी वह हर परिस्थिति में तैयार खड़ी रहती है। सप्ताह के सातों दिन...साल के 365 दिन। भारतीय पुलिस को यह क्षमता किसी चमत्कार से नहीं मिली, बल्कि एक अनुशासित संस्कृति, परिणामोन्मुख सोच और स्थितियों से जूझने के अभ्यास ने यह बनाया है।

सवाल यह है कि क्या यही पर्याप्त है? क्या पुलिस केवल संकट से निपटने के लिए बनी है? क्या उसे केवल घटना के बाद कार्रवाई करने वाली व्यवस्था बने रहना चाहिए? इसका उत्तर अब 'नहीं' में है, क्योंकि देश बदल रहा है, अपराध बदल रहे हैं, नागरिकों की अपेक्षाएं और अधिकार-चेतना भी कहीं अधिक स्पष्ट और मुखर हो गई है। अब सिर्फ व्यवस्था बनाए रखना काफी नहीं है। अब पुलिस को नागरिकों के भीतर विश्वास जगाना होगा। यह विश्वास तभी बनेगा, जब पुलिस अपनी भूमिका को केवल बल प्रयोग करने वाली संस्था के बजाय समाज के साथ संवाद और सहयोग करने वाली संस्था के रूप में पुनर्परिभाषित करेगी।

आज भी अधिकतर नागरिक पुलिस से बचना पसंद करते हैं। यह दूरी किसी कानून की वजह से नहीं, बल्कि अनुभव और पूर्वाग्रह की वजह से है। अगर लोगों को लगे कि पुलिस उनकी बात सुनती है, मदद करती है और बिना भय के उनसे संवाद किया जा सकता है, तो यह रिश्ता बदलेगा। इसके लिए थानों से बदलाव की शुरुआत करनी होगी। थाने सिर्फ एफआईआर लिखने या गिरफ्तारी करने के स्थान नहीं होने चाहिए। उन्हें मोहल्ले का समस्या समाधान केंद्र बनना होगा। एक ऐसा स्थान, जहां कोई भी नागरिक बेहिचक जाकर मदद मांग सके।

पुलिस में एक और बुनियादी बदलाव जरूरी है, अपराध और अपराधियों को समझने के नजरिये में। हर अपराधी एक जैसा नहीं होता। बहुत से लोग परिस्थितियों से मजबूर होकर अपराध की ओर धकेले जाते हैं। कोई गरीबी में, कोई अशिक्षा में, तो कोई गलत संगति में। ऐसे मामलों में सुधार और पुनर्वास की नीति अपनाई जानी चाहिए, न कि जेल की। जो अपराधी सचमुच समाज के लिए खतरा हैं, उनके साथ कठोरता उचित है, लेकिन बाकी के लिए सुधार की संभावना को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

यह भी समझना होगा कि आज का अपराधी पुरानी सोच वाला नहीं है। वह तकनीक से लैस है, कानून की सीमाओं को जानता है और डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करता है। आज साइबर क्राइम, वित्तीय धोखाधड़ी, सोशल मीडिया के जरिये उकसावों जैसी घटनाएं आम होती जा रही हैं। इनसे निपटने के लिए पुलिस को भी भविष्य की सोच और तकनीकी दक्षता से लैस होना होगा। हर जिले में अपराध विश्लेषण, डाटा आधारित फैसले और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग जैसी व्यवस्थाएं अनिवार्य की जानी चाहिए।

एक और अहम पक्ष है संवाद का। अक्सर पुलिस अपने काम की जानकारी जनता तक पहुंचाने में पीछे रह जाती है। जहां अफवाहें तेजी से फैलती हैं, वहां चुप्पी नुकसान करती है। पुलिस को अब अपने पक्ष को स्पष्ट, संवेदनशील और समय पर जनता तक पहुंचाना आना चाहिए। इसके लिए हर जिले में प्रशिक्षित जनसंपर्क अधिकारी होने चाहिए, जो न केवल मीडिया से संवाद करें, बल्कि सोशल मीडिया और जन मंचों पर भी पुलिस की बात रख सकें।

सबसे जरूरी यह समझना है कि पुलिस सुधार की मांग इसलिए नहीं हो रही है कि पुलिस अपने कार्य में विफल हो रही है, बल्कि यह इसलिए है कि पुलिस अब भी सफलतापूर्वक काम कर रही है, लेकिन उसे बदलते समय के साथ और भी प्रभावी बनाया जा सकता है। सुधार की प्रक्रिया संकट से नहीं, साहसिक सोच और दूरदृष्टि से शुरू होती है। जब कोई संस्था अब भी खड़ी हो, पर दबाव महसूस करने लगे, तभी सही समय होता है आत्ममंथन और नव निर्माण का।

आज जब देश एक नई सामाजिक और तकनीकी दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो पुलिस को भी एक नई सोच और रणनीति के साथ चलना होगा। अगर पुलिस को नागरिकों की पहली प्रतिक्रिया बने रहना है, तो उसे नागरिकों का पहला भरोसा भी बनना होगा। और यह विश्वास ही उस पुल की नींव बनेगा, जो राज्य और समाज के बीच मजबूती से खड़ा रह सकेगा।

(लेखक पुलिस महानिदेशक एवं हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख हैं।)

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 132

जोखिम भरा विकल्प

हेज फंड जेन स्ट्रीट के विरुद्ध नियामकीय कदम ने इक्विटी डेरिवेटिव्स बाजार की ओर नए सिरे से ध्यान आकर्षित किया है। अभी इस मामले पर कोई टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी क्योंकि हेराफेरी के आरोपों और जेन स्ट्रीट के कीमतों के आर्बिट्राज (कीमतों में अंतर का लाभ) के दावों की पुष्टि होनी बाकी है। इसके बावजूद यह तो स्पष्ट है कि इक्विटी बाजार के नकद और डेरिवेटिव्स क्षेत्र के बीच असंतुलन है और हेज फंड तथा अनुभवी व्यापारी इसी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हाल ही में कहा भी डेरिवेटिव्स बाजार का नॉमिनल टर्नओवर नकद बाजार से 350 गुना था और यह कोई सामान्य हालात नहीं है। देश का कुल बाजार पूंजीकरण जहां उसे आकार में दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा शेयर बाजार बनाता है वहीं उसका डेरिवेटिव्स बाजार मात्रा के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है।

खुदरा ट्रेडर्स बेहतर रिटर्न की उम्मीद में बड़ी संख्या में वायदा एवं विकल्प कारोबार में पैसा लगाते हैं। हालांकि, सेबी के कई अध्ययन बताते हैं कि 90 फीसदी से अधिक खुदरा ट्रेडर्स को वायदा एवं विकल्प क्षेत्र में अपना पैसा गंवाना पड़ता है। वर्ष2024-25 में उनका समग्र नुकसान 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक था।

डेरिवेटिव्स एक ऐसा क्षेत्र है जहां कुछ ट्रेडर्स को जितना लाभ होता है बाकियों को उतना ही नुकसान होता है। इस आकलन में विनिमय शुल्क और करों को हटाया जा सकता है। यह सच है कि इस धन को शेयरों जैसी अधिक उत्पादक परिसंपत्तियों में निवेश के माध्यम से दीर्घावधि पूंजी वृद्धि को लक्षित करने में अधिक लाभप्रद ढंग से लगाया जा सकता है, बजाय इसके कि इसे विकल्पों जैसी परिसंपत्तियों में लगाया जाए, जिनमें एक निश्चित तारीख पर सौदे काटने ही होते हैं। यही वजह है कि नियामक ने खुदरा कारोबारियों को कई चेतावनियां दीं और उन्हें डेरिवेटिव्स कारोबार के जोखिमों बारे में बताया। खबरों के मुताबिक तो वह कहीं अधिक व्यापक जागरूकता अभियान भी शुरू करने वाला है। वह शायद एक्सपायरी के दिन कारोबार पर नियंत्रण लागू करने के उपायों पर भी विचार कर रहा है। यह खुदरा ट्रेडर्स में डेरिवेटिव्स कारोबार लोकप्रिय है। विकल्प अपनी एक्सपायरी के थोड़ा पहले काफी सस्ते हो जाते हैं। ऐसे में ट्रेडर्स के पास गुंजाइश अधिक होती है और कीमतों में मामूली फेरदबल भी भारी लाभ और हानि की वजह बन सकते हैं।

हालांकि कई बातें हैं जिन पर नियामक को ध्यान देना होगा और उसके बाद ही वह नए उपायों की घोषणा कर सकेगा। उसने नवंबर 2024 में डेरिवेटिव्स में सटोरिया गतिविधियां नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए और उनका असर हुआ क्योंकि उसके बाद से कुल वॉल्यूम में कमी आई है। अधिक नियंत्रण और हेज फंडों के परिचालन की निगरानी के कारण भविष्य में मात्रा में और कमी आ सकती है। ऐसे में वायदा एवं विकल्प बाजार के लिए उपयोगी लक्ष्यों को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। उदाहरण के लिए आर्बिट्राज की अपनी व्यवस्था के माध्यम से मूल्य खामियों को दूर करना, लागत की दृष्टि से बेहतर हेजिंग संभावनाएं तैयार करना और इक्विटी बाजार के लिए गहराई तैयार करना। इस संदर्भ में खरीदार के लिए सावधान रहने वाली पुरानी चेतावनी सामने आती है। जो लोग पैसा गंवाते हैं उन्हें पता होता है कि वे पैसा गंवा चुके हैं और हर डेरिवेटिव्स कारोबार प्लेटफॉर्म अब उपयुक्त चेतावनी जारी करते हैं। अगर खुदरा ट्रेडर्स जोखिम लेना ही चाहते हैं तो शायद नियामक के लिए उनको रोकना उचित नहीं होगा बशर्ते कि बाजार की स्थिरता प्रभावित न हो रही हो। नियामक निरंतर शैक्षणिक अभियानों के जरिये जागरूकता फैलाता रह सकता है।

इसके अतिरिक्त यह तर्क दिया गया है कि असंतुलित मात्रा अनुपातों की एक वजह नकद इक्विटी में लीवरेज की कमी और सेकंडरी बॉन्ड बाजार में गतिविधि का अभाव है। इसलिए यह सही है कि डेरिवेटिव्स में वॉल्यूम असामान्य है। बहरहाल अगर बाजार प्रणाली और नियामक, डेट और इक्विटी बाजार दोनों में नकद बाजार टर्नओवर सुधारने पर ध्यान दें तो असंतुलन दूर होना शुरू हो जाएगा।

ट्रंप्लोमेसी के दौर से गुजर रही दुनिया

मुखर, जोरदार, स्पष्ट, अनुचित और अतिशय प्रशंसा से भरपूर, कभी-कभी अपमान से युक्त। इसे ही हम 'ट्रंप्लोमेसी' कहते हैं। परंतु इसका उद्देश्य वही है: अमेरिकी वर्चस्व को कायम रखना

राष्ट्र की बात

शेखर गुप्ता

अमेरिका को फिर से महान बनाने के नाम पर राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप दुनिया के उन हिस्सों में अमेरिका विरोध को नए सिरे से जन्म दे रहे हैं जहां वह सुषुप्तावस्था में पहुंच गया था। अब तक उनका तरीका यही रहा है, सहयोगियों का सार्वजनिक रूप से मखौल उड़ाना और विरोधियों के साथ पींगें बढ़ाना।

भारत की बात करें तो वह बार-बार यह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भारत-पाक जंग रुकवाई और मध्यस्थता की। इन दावों ने उन पुराने जख्मों को कुरेद दिया है जो भारत-पाकिस्तान को एक समान पलड़े पर रखने ने दिए थे। वाम रुझान वाले और मोदी विरोधी विचारों को मानने वालों में खामोश जश्न का माहौल है: जब आप अविश्वसनीय लोगों से डील कर रहे थे तो आपने क्या उम्मीद की थी? और क्या पता इस वर्ष के आखिर में अगर वह क्वाड की बैठक में शामिल होने भारत आते हैं तो कहीं कुछ समय के लिए पाकिस्तान में भी न रुक जाएं।

कूटनीति के पुराने नियम उन पर लागू नहीं होते। अगर पाकिस्तान के साथ अपना नाम आने से भारत चिढ़ता है तो यह भारत की दिक्कत है। ट्रंप इससे अपने लिए नियम नहीं तय करेंगे। कम से कम चार वक्तव्यों में उन्होंने एक ही वाक्य में नरेंद्र मोदी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम लिया है। सबसे ताजा मामला 19 जून का है जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जनरल (जो दोपहर के खाने पर व्हाइट हाउस गए थे) बहुत ही स्मार्ट व्यक्ति हैं और भारत के प्रधानमंत्री मोदी एक शानदार व्यक्ति और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं।

इस तरह उन्होंने एक बार फिर हमें पाकिस्तान के साथ बराबरी पर रखा और अब मोदी और मुनीर को एक साथ रख रहे थे। क्या बदकिस्मती है। मैं गहरी सांस लेने और मुस्कुराने की सलाह दूंगा। अगर ट्रंप मुनीर को मोदी के बराबरी पर रख रहे हैं तो सबसे अधिक शिकायत क्या शहबाज शरीफ को नहीं होनी चाहिए। आखिर बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने ही तो मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया। कम से औपचारिक तौर पर तो अभी भी फील्ड मार्शल ही प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है।

यहां तक कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी शरीफ को केवल अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से बात करने को मिला। यानी भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के समकक्ष से। ऐसे में अगर किसी को दुखी होना चाहिए तो वह हैं शरीफ। अब तक किसी अमेरिकी नेता ने पाकिस्तान की हकीकत और उसके पाखंड को उतने मुखर और सच्चे ढंग से नहीं उजागर किया है जितना कि ट्रंप ने।

इस पर शांति से विचार करें। दशकों तक भारत यह कहता रहा है कि पाकिस्तानी लोकतंत्र तमाशा है और असली शक्ति सेना के हाथों में है। पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत में ट्रंप उसी बात को और पुष्ट कर रहे हैं। एक तरह से वह भारत का ही काम कर रहे हैं। ट्रंप के पूर्ववर्ती मूर्ख नहीं थे। उन्हें पता था लेकिन फिर भी वे इन तमाम दशकों के दौरान पाकिस्तान में लोकतंत्र बहाली की कोशिश (या दिखावा) करते रहे।

ट्रंप अब एक्स या ट्रुथ सोशल पर जब अपने ही वफादार समर्थकों को फटकार लगाते हैं- अपने प्रिय शब्द 'बकवास' के द्वारा, तब वह कोई बकवास नहीं करते बल्कि सीधी बात करते हैं। किसी भी देश में जिसका भी शासन हो वह उससे निपट लेंगे। समय के साथ भारत के साथ भी उनका यही रवैया होना चाहिए।

अगर ट्रंप अपनी घरेलू राजनीति को यूं ही सोशल मीडिया पोस्ट से चलाते रहे, जिसकी वर्तनी और व्याकरण इतनी खराब होती है कि वे हमारी यूपीएससी परीक्षा के प्रीलिम्स में ही फेल हो जाएंगे, तो फिर भला वे कूटनीति को जरा भी तवज्जो क्यों देंगे। वह पुरानी संकेतों वाली कूटनीति से बोर हो गए हैं जहां निजी तौर पर कुछ कहा जाता है और सार्वजनिक रूप से कुछ और।

बात केवल यह है कि उन भरोसा नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए नाटो महासचिव (और पूर्व डच प्रधानमंत्री) मार्क रट का ट्रंप को लिखा गया चापलूसी भरा नोट आपको याद होगा जिसका ट्रंप ने तुरंत स्क्रीनशॉट लिया और सार्वजनिक कर दिया। यूरोपीय लोग सन्न रह गए। वह यही चाहते हैं: स्तब्ध करना और विस्मित करना। दुनिया को यह सब और अमेरिका की ताकत महसूस करनी चाहिए और इसे स्वीकार करना चाहिए। रट ने तो अपने नोट में चापलूसी की हद पार कर दी थी और नाटो के नेताओं से कह डाला था कि वे ट्रंप को अपने 'पिता' के रूप में देखें।

जब कभी आप परेशान महसूस करें तो देखिए कि ट्रंप अपने करीबी सहयोगियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। उन्होंने कनाडा को आमंत्रित किया कि वह अमेरिका का राज्य बन जाए और पूरी सुरक्षा, शून्य टैरिफ और कम कर दरों का लाभ ले। उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को गवर्नर कहकर पुकारा और नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के सामने भी 51वें राज्य का विचार रखा। यहां तक कि उनके नकारने पर भी ट्रंप ने हार नहीं मानी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ट्रंप मोदी के साथ बैठे हैं और उनसे कह रहे हैं, 'मेरा ख्याल है कि आपको कश्मीर का हजारों साल पुराना युद्ध खत्म करना चाहिए। दोनों पक्षों के पास जो है उसी में खुश रहिए।' ध्यान रहे कि वे कनाडा से इससे भी बुरी बात कह चुके हैं।

जब वह चाहते हैं कि हमास लड़ाई रोक दे तो कहते हैं कि गाजा को अमेरिका को तोहफे में दे दिया जाएगा और वह वहां एक बेहतरीन रिवेरा बनाएंगे। वह एआई से बनी तस्वीरें पोस्ट करते हैं जिनमें वे समुद्र तट पर आराम फरमा रहे हैं। वह ईरान से बातचीत कर रहे थे लेकिन जब इजरायली हमले हो रहे हों तभी वह भी बमबारी करते हैं।

इसके बाद उन्होंने अपने करीबी साझेदार इजरायल से कहा कि वह अपने बमवर्षक विमान वापस बुला ले। अब वह ईरान से बातचीत दोबारा शुरू करना चाहते हैं और अब्राहम समझौते का विस्तार करते हुए सऊदी अरब को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं।

वह जेलेंस्की को सार्वजनिक रूप से अपमानित करते हैं, उन्हें त्याग देने का दिखावा करते हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि खनिज सौदे के बदले उन्हें संरक्षण दिया जाएगा, वह नाटो को डराने के लिए पुतिन की तारीफ करते हैं और उसके बाद खुद ही उनसे नाराज हो जाते हैं। अब वह यूरोप से नए हथियारों की कीमत चुकाने को कह रहे हैं।

इसे ही हम 'ट्रंप्लोमेसी' कहते हैं। मुखर, जोरदार, स्पष्ट, अनुचित और अतिशय प्रशंसा से भरपूर, कभी-कभी अपमान से युक्त। परंतु व्यापक लक्ष्य एक ही है, अमेरिका की श्रेष्ठता का विचार। उनके प्रशंसक उनके इस अंदाज को पसंद करते हैं। उनका हालिया गुस्सा विशुद्ध रूप से घरेलू मुद्दों पर है। उदाहरण के लिए एप्सटीन फाइल्स जारी करने से उनका इनकार।

अमेरिका के दोस्त उन्हें ठुकराए हुए प्रेमी की तरह नहीं छोड़ सकते। उन्हें अमेरिका की जरूरत है। इसी सप्ताह वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक शानदार स्टोरी प्रकाशित की जिसमें इस बात को लेकर जानकारी दी गई कि कैसे यूरोप के लोग उन्हें अपने पाले में कर रहे हैं। इसके लिए उनके परिवार और मित्रों को तोहफे दिए जा रहे हैं, अपमान पर मुस्कराया जा रहा है वगैरह। वहीं उनके शत्रु अगले कदम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चीन जैसे देश जिनके पास अहम खनिज संसाधन हैं, वे शांत हैं। उन्हें पता है कि यूक्रेन में शांति हो या नहीं लेकिन ट्रंप उन पर असामान्य शुल्क दर के साथ हमला नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत अपनी स्थिति देखें। भारत को सोचना होगा कि अगर ट्रंप पाकिस्तान में रुकते हैं और बहुत पहले भुलाए जा चुके दो देशों वाले नियम को दोबारा जिंदा करते हैं तो क्या उनसे कहा जा सकता है कि वे फिर कभी आएं?

दुनिया नई हकीकत को स्वीकार कर रही है। अमेरिका में ट्रंप के आलोचक कहते हैं कि उनकी नीतियां चीन को दोबारा महान बना रही हैं और इस बात में दम है। उनकी नीतियों के अनचाहे परिणाम सामने आ रहे हैं। दुनिया ट्रंप के बारे में दो बातें समझती है। पहली, अनिश्चितता, बेतुकी बातें करना और नीति निर्माण में अव्यवस्था। दूसरा, वह हमेशा नहीं रहने वाले। ज्यादा से ज्यादा 2026 के अंत तक उनका प्रभाव सिमट जाएगा। ऐसा नहीं होता है तो भी ज्यादा से ज्यादा 2028 तक हम प्रतीक्षा कर सकते हैं। तीसरी बात, हम सभी को यह सीखने की जरूरत है कि उनकी नीतियों से अधिक उनके तरीके अस्थिरता पैदा करने वाले हैं। ऐसे में अच्छा यही होगा कि अगले कुछ वर्षों तक शांति से ट्रंप्लोमेसी का आनंद लिया जाए।

अमेरिका की नीतियों की नकल खतरनाक

नीति नियम

मिहिर शर्मा

भले ही आने वाले दशकों में अमेरिका की आर्थिक और सैन्य शक्ति कमजोर हो जाए, लेकिन उसकी सांस्कृतिक मजबूती पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तमाम महाशक्तियों के साथ अक्सर ऐसा ही होता आया है। समय के साथ उनकी अर्थव्यवस्थाओं के शिथिल पड़ने के बावजूद विचारों और संस्कृति की दुनिया में उनकी धमक लंबे समय तक सुनाई देती है। आर्थिक मोर्चे पर अमेरिका 1880 के दशक में ही ब्रिटेन से आधिक ताकतवर बन गया था लेकिन उसकी वैचारिक-सांस्कृतिक जमीन को मजबूत होने में 40-50 साल और लग गए। और इस बीच अस्तित्व में आया हॉलीवुड।

वैचारिक ताकत का तात्पर्य केवल फिल्मों और संगीत से नहीं है। किसी महाशक्ति की आंतरिक क्रियाशीलता कैसे शेष दुनिया पर असर डालती है, इसका पता उस देश की आंतरिक राजनीतिक बहसों से चलता है। किसी न किसी रूप में ये बहसें धुरी का काम करती हैं जिसके इर्द-गिर्द अन्य देशों की राजनीति घूमती दिखाई देती है।

अमेरिकी राजनीति ने भिन्न सामाजिक और आर्थिक ढांचे वाले देशों को किस तरह प्रभावित किया है, इस पर एक नजर डालते हैं। अमेरिका में नस्लीय उत्पीड़न का ऐसा कड़वा इतिहास रहा है, जिसकी नजीर दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती। ब्राजील जैसे कुछ अन्य देश भी आंशिक रूप से दास व्यापार प्रथा द्वारा निर्मित हुए थे और वहां भी कानूनी तौर पर गुलामी की प्रथा उतनी ही पुरानी थी जितनी अमेरिका में, या शायद उससे भी पुरानी।

लेकिन अमेरिका में जैसी दासता, संवैधानिक नागरिक अधिकार और पीढ़ियों से चली आ रही नस्लीय अलगाव की स्थिति रही वैसा और कहीं नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि अमेरिकी राजनीति जिस प्रकार इन मसलों से निपटती है अथवा उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, वैसा कहीं और देखने को नहीं मिलता।

इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जब अमेरिका में 'ब्लैक लाइव्स मैटर्स' विरोध-प्रदर्शनों या व्यापक स्तर पर युवा हिस्पैनिक पुरुषों (लैटिन अमेरिकी देशों के स्पैनिश भाषी लोग) के डॉनल्ड ट्रंप का समर्थन करने जैसे नस्लीय आक्रोश फूटते हैं तो यह एक बेचैन समाज में उभरती बहुत ही अलग तरह की नस्लीय सहमति का रूप सामने आता है। जातीय या नस्लीय तनाव से जूझते अन्य देश इससे बहुत सीख नहीं ले सकते। यूरोप में नस्लीय अल्पसंख्यकों का अफ्रीकी-अमेरिकियों से एकदम अलग इतिहास रहा है। वहीं भारत में भी जातिगत भेदभाव है, जिसकी तुलना अक्सर नस्लीय उत्पीड़न से की जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सफल हिंदुत्व एजेंडा दिखाता है कि एक अलग तरीके से इसे कैसे राजनीति के लिए अपने पक्ष में किया जा सकता है। अमेरिका की नस्लीय राजनीति से दुनिया के अन्य देश कुछ सीख तो सकते हैं, लेकिन उन्हें यह याद रखना होगा कि इसमें से कुछ भी उनके लिए प्रासंगिक नहीं है। वे इन नीतियों को अपने यहां लागू नहीं कर सकते।

एक और चीज जो अमेरिका को खास बनाती है, वह है अपनी सरकार की भूमिका के प्रति उसका नजरिया। कहा जाता है कि अमेरिकी लोग छोटी सरकार को पसंद करते हैं। कुछ हद तक यह सही भी है। अमेरिका में सरकारी खर्च सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 36 फीसदी है, जबकि जापान में यह 41 फीसदी और स्वीडन में 47 फीसदी तक है। लेकिन यह भी सच है कि अमेरिका में बजटीय सीमा जैसी कोई अवधारणा नहीं है। सेंट लुइस के फेडरल रिजर्व बैंक के अनुसार जीडीपी के प्रतिशत के रूप में इसकी संघीय सरकार का घाटा 6.3 फीसदी है। ट्रंप सरकार का नया बजट विधेयक ऋण को बढ़ने से रोकने की कोई वास्तविक योजना सामने नहीं रखता, जिससे यह बोझ बढ़ता जा रहा है।

लंबे और मजबूत वित्तीय इतिहास वाली अर्थव्यवस्था के मालिक ब्रिटेन समेत कोई भी देश ऐसी आर्थिक अनियमितता से बच नहीं सकता। फिर भी ऐसा माना जाता है कि औद्योगिक नीति से लेकर विनियमन और पूंजीगत लाभ कर तक अमेरिका की आर्थिक बहसों और धारणाओं का शेष विश्व की आर्थिक नीतियों पर असर पड़ता है। क्या अन्य देश वास्तव में इससे प्रभावित होते हैं। यहां तक कि उस समय भी जब लोक वित्त में सबसे महत्त्वपूर्ण बाधा मानी जाने वाली सरकार की बजट सीमा उन पर लागू नहीं होती।

यह उम्मीद करना बेहद खतरनाक होगा कि कोई भी देश अमेरिका की सब्सिडी, व्यापार नीति, शोध, कर संरचना या उसकी नियामकीय बहसों से कोई नीतिगत सबक सीख सकता है या उन्हें अपने यहां लागू कर सकता है। क्योंकि सभी किसी न किसी तरह इस तथ्य से वाकिफ हैं कि अमेरिका वित्तीय बाजारों से बेखटके असीमित मात्रा में धन उधार ले सकता है जबकि कोई अन्य देश ऐसा नहीं कर सकता। हम सभी अमेरिका, वहां की राजनीति व नीतियों से प्रभावित हैं और दशकों तक रहेंगे भी, लेकिन यह केवल एक पर्यवेक्षक के रूप में हो, प्रतिभागी या शिष्य के रूप में ऐसा कतई न करें।

आपका पक्ष

अमेरिका से टैरिफ समझौतों पर धैर्य रखे भारत

रिपोर्ट 'अपनी शर्तों पर अमेरिका से बात करे भारत' स्पष्ट रूप से यह मत व्यक्त करता है कि भारत को अमेरिका के दबाव में आकर टैरिफ समझौता नहीं करना चाहिए। अमेरिका की टैरिफ नीति में बार-बार बदलाव हो रहे हैं और स्वयं अमेरिका सुनिश्चित नहीं है कि अंततः उसकी टैरिफ नीति किधर जा रही है। छोटे देशों की विवशता हो सकती है। उनकी आवश्यक आपूर्ति श्रृंखला विकसित देशों पर अधिक निर्भर होती है जबकि उनके पास निर्यात के सीमित अवसर हैं। इसके अतिरिक्त उन पर वैश्विक दबाव भी अधिक हो सकते हैं। ऐसे में इंडोनेशिया व अन्य पूर्वी एशियाई देशों से टैरिफ नीति के समझौतों की तुलना उचित नहीं है। संभवतः अमेरिका भारत के साथ अपने पक्ष में ट्रेड सरप्लस चाहता है जो अभी भारत के पक्ष में है। डॉनल्ड ट्रंप उच्च कर व्यवस्था में विश्वास करते है और वह इसको हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं परंतु इसके लिए उनको अपने पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन से सीख लेनी चाहिए। भारत के उद्योग और औद्योगिक कॉर्पोरेट अब आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ चुके हैं। जितनी बेसब्री से अमेरिका अपनी टैरिफ नीति पर आक्रामक रुख दिखा रहा है, वह उसकी विवशता है, हमारी विवशता नहीं है। भारत सरकार ने निश्चित रूप से बहुत धैर्य का परिचय दिया है परंतु अब टैरिफ संबंधित समझौतों की अपनी सीमाएं भारत को स्पष्ट दिखाई देने लगी हैं। सौदा बराबरी का होना चाहिए।

विनोद जौहरी, दिल्ली

भारत को अमेरिका के टैरिफ से संबंधित समझौतों में सौदा बराबरी का करना चाहिए

मानव निर्मित कारकों पर नियंत्रण बेहद जरूरी

हमारे देश की स्थिति भौगोलिक रूप से अधिक विविधता वाली है। इसमें एक ओर हिमालय जैसे पर्वत शिखर तो दूसरी ओर बड़े-बड़े समुद्री तट हैं। इसके अतिरिक्त, सदाबहार से लेकर मौसमी तक भारत में नदियों का विस्तृत संजाल मौजूद है, साथ ही भारत के मुख्य भागों में वर्षा की अवधि का वर्ष में निश्चित समय है। इससे वर्षा ऋतु के दौरान बड़ी मात्रा में जलभराव एवं बाढ़ की समस्या का सामना करना पड़ता है। उपर्युक्त भौगोलिक कारकों के अतिरिक्त मानवीय कारक भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक वर्ष आने वाली वर्षाजनित बाढ़ से बड़ी मात्रा में जन-धन की हानि होती है, साथ ही इससे सर्वाधिक नकारात्मक रूप से समाज का सबसे गरीब वर्ग प्रभावित होता है। इस आलोक में बाढ़ जैसी आपदा की रोकथाम तथा बाढ़ आने के बाद होने वाली हानि को कम करने के लिए जरूरी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि, विभिन्न सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों द्वारा बाढ़ के प्रभावों को कम करने के प्रयास किए जाते हैं, किंतु ये प्रयास तब तक ऐसी आपदाओं को रोकने में कारगर नहीं हो सकेंगे, जब तक मानव निर्मित कारकों जैसे- जलवायु परिवर्तन, निर्वनीकरण, अवैज्ञानिक विकास कार्य आदि को नहीं रोका जाता। विभिन्न शासकीय एवं सामाजिक आंदोलनों के जरिए पौधरोपण को प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

जापान के 248 सदस्यीय ऊपरी सदन 'हाउस ऑफ काउंसलर्स' की आधी सीट के लिए रविवार को मतदान शुरू हुआ। मतदाता जापान की संसद 'डायट' के दोनों सदनों में से कम शक्तिशाली उच्च सदन की 248 सीट में से 124 पर फैसला करेंगे।

हिन्दुस्तान 1936

तीन माता-पिता

दुनिया में दो डीएनए के मिलने से एक बच्चे का जन्म होता है, पर अब तीन डीएनए के संयोग से एक बच्चे को पैदा करने का प्रयास साकार हो गया है। वैज्ञानिकों को पूरा यकीन है कि अगर लाइलाज आनुवंशिक रोग होने की आशंका हो, तो तीन डीएनए की मदद से स्वस्थ शिशु को जन्म दिया जा सकता है। इस पद्धति से जन्म लेने वाला बच्चा तमाम तरह के लाइलाज आनुवंशिक रोगों से मुक्त रहेगा। ब्रिटेन इस मामले में नेतृत्व करता दिख रहा है। *द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन* के मुताबिक, माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़ी वंशानुगत बीमारियों से निपटने के लिए माता-पिता के साथ-साथ एक अन्य महिला के डीएनए का इस्तेमाल किया गया, जिसमें डॉक्टरों को सफलता मिली है। बताया गया है कि ऐसे आठ बच्चे पैदा हुए हैं, जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया संबंधी वंशानुगत रोगों के लक्षण नहीं दिखे हैं। इससे स्वाभाविक ही उन माता-पिता की उम्मीदें बढ़ गई हैं, जो इस चिंता में अपनी संतान नहीं पैदा करना चाहते कि कहीं उनका रोग उनके बच्चे को न हो जाए। हालांकि, इस प्रयोग को लेकर नैतिकता का भी प्रश्न खड़ा किया जा रहा है। आलोचक अंदेशा जता रहे हैं कि इससे 'डिजायनर बेबी' का चलन बढ़ जाएगा। मगर वैज्ञानिक खुश हैं कि इससे लाखों बच्चों की जान बच सकेगी।

आंकड़ों की मानें, तो हर 5,000 में एक शिशु माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़ी बीमारी से ग्रसित होता है। निस्संदेह, माइटोकॉन्ड्रिया हमारी हर कोशिका में मौजूद रहता है और हमारे जीवित रहने का आधार भी माना जाता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन का उपयोग करके भोजन को ऊर्जा में बदलता है और हमारे शरीर को जरूरी ईंधन मुहैया कराता है। इसीलिए इसे 'कोशिका का पावरहाउस' भी कहा जाता है। मगर इसमें यदि कुछ दोष निकल आए, तो जीवन जीने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है, वह हमें नहीं मिल पाती। नतीजतन, मस्तिष्काघात, दौरे, मांसपेशियों में कमजोरी, लकवा ग्रस्त होने का खतरा बढ़ जाता है। यही कारण है कि ऐसी बीमारियों से ग्रसित कई बच्चे असमय ही काल के शिकार बन जाते हैं। इसीलिए, 'तीन माता-पिता वाले बच्चे' के जन्म और उनकी सेहत की खबर का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। ब्रिटेन ने 2015 में ही अपने कानून में जरूरी बदलाव करते हुए 'माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन' को हरी झंडी दे दी थी। लिहाजा, यह कह सकते हैं कि देर से ही सही, लेकिन चिकित्सा वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खबर साझा की है, जो आने वाले समय में आईवीएफ प्रक्रिया में एक नई क्रांति ला सकती है।

आलोचकों की नजर में डीएनए से छेड़छाड़ नैतिकता के खिलाफ है, पर चिकित्सा विज्ञान इसे ऐसी उपलब्धि मान रहा है, जिससे लाखों बच्चों की जान बच सकती है।

नैतिकतावादियों और वैज्ञानिकों में इस बात को लेकर मतभेद बना हुआ है कि भ्रूण के डीएनए में बदलाव नैतिक है या नहीं? बेशक, ऐसी तकनीक जानलेवा बीमारियों को ठीक करने में मददगार मानी जाती है, लेकिन नैतिक मूल्यों की चिंता करने वालों को डर है कि इससे मनचाहे गुणों वाले बच्चों को जन्म देने की मानसिकता पनप सकती है और खास आंखें, बाल या समझ वाले बच्चों की मांग बढ़ सकती है। इसी तरह की चिंता मानव क्लोनिंग को लेकर भी हम देखते रहे हैं, जिसमें सामाजिक संरचना, परिवार या मानव संबंधों में बदलाव की आशंकाएं जताई जाती हैं। हालांकि, ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं है, जो लाइलाज बीमारियों के उपचार और वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने को नैतिक रूप से उचित मानते हैं। उनके मुताबिक, चिकित्सकीय कार्यों और शोध के लिए न सिर्फ क्लोनिंग की अनुमति दी जानी चाहिए, बल्कि पर्याप्त निगरानी रखते हुए इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

समझौते की सही शर्त पर अड़े भारत

इंडोनेशिया जैसा समझौता हमारे लिए फायदेमंद नहीं हो सकता। भारत जहां भी अमेरिका को रियायत देगा, बदले में उसे भी वैसा ही फायदा मिलना जरूरी है।

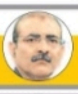

यहां स्कैन करें

आलोक जोशी | वरिष्ठ पत्रकार

ऐसा लगने लगा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता जल्दी हो सकता है। इसकी रूपरेखा क्या होगी और यह कैसे होगा, यह रहस्य अब भी बरकरार है। मगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इंडोनेशिया की तर्ज पर भारत से व्यापार समझौता हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के बाजार उनके लिए पूरी तरह खुल जाएंगे।

इन बातों का क्या अर्थ है, यह तो तभी पता चलेगा, जब समझौता सामने होगा, मगर इंडोनेशिया को देखें, तो वहां अमेरिका से जाने वाले माल पर कोई भी सीमा शुल्क नहीं लगेगा, जबकि इंडोनेशिया से अमेरिका को निर्यात होने वाले माल पर 19 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने यह भी बताया कि इंडोनेशिया अमेरिका से 15 अरब डॉलर के ऊर्जा उत्पाद, यानी तेल गैस खरीदने को भी राजी हुआ है और 4.5 अरब डॉलर के कृषि उत्पाद भी खरीदेगा। यही नहीं, वह बोइंग के 50 विमान भी खरीदेगा।

अब अगर मान लें कि ट्रंप भारत के साथ भी ऐसा ही समझौता करने की सोच रहे हैं, तो क्या भारत अमेरिका को ऐसा ही खुला मैदान सौंप देगा? हालांकि, यहां याद रखना चाहिए कि ट्रंप ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम लेकर कहा था कि भारत में अमेरिकी उत्पादों पर 52 प्रतिशत आयात शुल्क लगता है और जवाब में वह भारतीय उत्पादों पर सिर्फ 26 प्रतिशत शुल्क लगा रहे हैं। इसके पहले, वह एलान कर चुके थे कि सभी देशों पर 10 प्रतिशत आयात शुल्क तो लगेगा ही और उसके ऊपर जवाबी शुल्क लगाया जाएगा, जिसकी दर सबके लिए अलग-अलग बताई गई। यानी, भारत पर कुल 26 प्रतिशत शुल्क लगना था। हालांकि, कुछ ही समय बाद उन्होंने रेसिप्रोकल, यानी जवाबी टैरिफ टालने का एलान किया और तब से वह एक के बाद दूसरे देश के साथ समझौते कर रहे हैं या फिर उनको चिट्ठियां भेजकर टैरिफ का एलान कर रहे हैं। बहुत से कूटनीतिज्ञ मानते हैं कि ऊंची दरों पर टैरिफ का एलान कर ट्रंप मोलभाव के लिए दबाव बना रहे हैं। जैसे-जैसे समझौते हो रहे हैं, वैसे-वैसे इस बात में दम भी दिख रहा है।

बहरहाल, एक बात तो तय है कि समझौता जिन भी शर्तों पर होगा, भारत के लिए, खासकर व्यापार और उद्योग जगत के लिए यह अच्छी खबर होगी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मोर्चे पर ट्रंप और टैरिफ एक पतले धागे से टंगी तलवार की तरह लटक रहे हैं। इस चक्कर में भविष्य का खाका खींचना या कोई योजना बनाना लगभग असंभव हो गया है। कहा जाता है, अच्छी खबर आने में भले ही देर हो, बुरी खबर जितनी जल्दी मिल जाए, इंसान उतनी अच्छी तैयारी कर सकता है। इसीलिए अब भारत में भी लोग समझौते की शर्तों से ज्यादा इस डील के होने का इंतजार कर रहे हैं।

यहां एक खास बात यह है कि अब ट्रंप प्रशासन भी इस मसले को जल्दी निपटाने के मूड में है। एक तो वह भारत जैसा बड़ा बाजार हाथ से जाने नहीं दे सकता। दूसरा, अब अमेरिका में टैरिफ का असर दिखने लगा है, यानी वहां महंगाई भड़क रही है। ऐसे में, अगर जल्द समझौते नहीं हुए, तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर मंदी का संकट बढ़ सकता है। दूसरी तरफ, ताजा आंकड़े दिखा रहे हैं कि जून के महीने में भारत द्वारा अमेरिकी निर्यात में 23 प्रतिशत का उछाल आया है, जबकि अमेरिका से आयात में 10 फीसदी की गिरावट आई है। यह आंकड़ा देखकर भ्रम हो सकता है। कुछ लोग दावा भी करने लगे हैं कि अब यह सिलसिला तेज होगा और भारत अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापार साझीदार बनने की तरफ बढ़ रहा है। मगर ध्यान रहे, यह अपवाद है।

दरअसल, ऊंचे सीमा शुल्क की आशंका में वहां के ज्यादातर बड़े व्यापारियों ने विदेश से भारी मात्रा में माल आयात करके 'स्टॉक' कर लिया है, ताकि काफी समय तक वे नए टैरिफ से बचे रह सकें। इसके बावजूद अमेरिका में खुदरा महंगाई की दर 2.4 प्रतिशत से बढ़कर 2.7 प्रतिशत पर पहुंच गई है। यह फरवरी के बाद से महंगाई दर का सबसे ऊंचा स्तर है। ऐसे में, आसानी से समझा जा सकता है कि टैरिफ वृद्धि का पूरा असर आने के बाद क्या होगा!

इसलिए यह समझना जरूरी है कि भारत इस वक्त टैरिफ के बोझ से दबने की आशंका से नहीं जूझ रहा है, पर यह खुशफहमी भी ठीक नहीं है कि अमेरिका दबाव में आने वाला है। शायद दोनों ही तरफ से जो टीमें बातचीत में जुटी हैं, उनको यह बात समझ में आ रही है, इसीलिए बातचीत अटकती हुई दिखती भले हो, मगर लगातार चलती रही है।

टैरिफ की चर्चा शुरू होने के साथ ही बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने हिसाब लगाया था कि अगर अमेरिका ने भारत से आयात पर 20 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया, तो उससे लगभग 14.6 अरब डॉलर की ड्यूटी लग जाएगी। इसका सबसे बड़ा असर भारत से अमेरिका जाने वाले ऑटो पार्ट्स और बायोफार्मा उत्पादों के दाम पर पड़ेगा। हालांकि, कीमत अमेरिकी उपभोक्ता को ही चुकानी होगी, लेकिन इसका असर भारतीय कंपनियों के कारोबार पर दिख सकता है। उसका यह भी कहना था कि इसके बावजूद भारत का अंतरराष्ट्रीय व्यापार और जीडीपी सालाना 6.4 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ता रहेगा और अगले दशक तक भारत विश्व व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा।

मगर अमेरिका को छोड़कर भी दुनिया नहीं चल सकती, इसलिए अभी उसके साथ टैरिफ समझौता होना भारत के लिए भी जरूरी है। भारत अपने उन उद्योगों के लिए अमेरिका का बाजार खुले रखना चाहता है, जिनमें सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। तो दूसरी तरफ, अमेरिका हथियारों व औद्योगिक उत्पादों के अलावा अपने कृषि उत्पादों और मांस, मछली, अंडे व दूध जैसी चीजों के लिए भी यहां बड़ा बाजार देख रहा है। मगर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भारत जीएम फसलों के लिए रास्ता नहीं खोलना चाहता और डेयरी उत्पादों के लिए भी। दूध के मामले में तो देश के भीतर शाकाहार और मांसाहार की बहस भी खड़ी हो गई है।

बहरहाल, बातचीत का अंदाज बता रहा है कि रास्ता बहुत दूर नहीं है। मगर भारत को यह ख्याल रखना होगा कि इंडोनेशिया जैसा समझौता हमारे लिए किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं हो सकता। भारत जहां भी अमेरिका को रियायत देगा, बदले में उसे भी वैसा ही फायदा मिलना जरूरी है। उम्मीद है, ऐसा ही होगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

भारतीयता को कहीं कमजोर न कर दे जाति जनगणना

यहां स्कैन करें

नितिन पई | निदेशक, तक्षशिला संस्थान

भारत में जाति एक विलक्षण असलियत है, जो सामाजिक जीवन में अलगाव और वैमनस्य पैदा करने वाली राष्ट्र-विरोधी शक्ति है। इसलिए जातियों की गणना न सिर्फ भारत में विकास की धार को कुंद करेगी, बल्कि हमारे मूलभूत सांविधानिक मूल्यों को भी कमजोर कर देगी। इस संदर्भ में मैं भारतीय गणतंत्र के गठन के दिन दी गई बी.आर. आंबेडकर की चेतावनी को याद कराना चाहूंगा, 'जातियां राष्ट्र-विरोधी हैं। वे राष्ट्र-विरोधी इसलिए भी हैं, क्योंकि वे जाति-जाति के बीच ईर्ष्या और द्वेष पैदा करती हैं। अगर हम वास्तव में एक राष्ट्र बनना चाहते हैं, तो हमें इन सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होगी। राष्ट्र के बिना भाईचारा संभव नहीं है और भाईचारे के बिना समता और स्वतंत्रता बेमानी है। समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के बिना राष्ट्र दिखावे के रंग-रोगन से ज्यादा कुछ भी नहीं।'

जब अंग्रेजों ने भारत में जनगणना के साथ जातियों की गणना शुरू की, तो जाति समूह संख्या-बल दिखाने के लिए लामबंद हुए थे। मंडल के बाद के दौर में कारों के शीशों पर जाति का नाम लिखकर 'शान दिखाने' का खुला प्रदर्शन आम बात है। समाज विज्ञान के अध्ययन आंबेडकर की दलील की तस्दीक करते हैं। देखा गया है कि जब छात्रों को स्कूल में स्वैच्छिक रूप से अलग-अलग कक्षाओं में बैठाया गया, तो वे जल्दी ही उस कक्षा की पहचान बन गए और दूसरी कक्षा से प्रतिस्पर्द्धा करने लगे। लेकिन यदि सामाजिक पहचान, ऊंच-नीच की भावनाओं के आधार पर उन्हें बैठाया जाए, तब उनका आपसी तालमेल कैसा होगा? ऐसी स्थिति में देश में राष्ट्रीय चेतना का विकास असंभव है।

जाति जनगणना का उद्देश्य सत्ता में हिस्सेदारी देखना है। जातीय चेतना को मजबूत करके जातीय भेदभाव को खत्म नहीं किया जा सकता।

बुद्धिजीवियों की यही प्रतिक्रिया होगी कि जाति जनगणना सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है। लेकिन इससे उनकी मुराद केवल आरक्षण और कोटा बढ़ाने से होती है। फिर भी, यह समझना मुश्किल है कि ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित समुदायों की संभावनाओं को जाति जनगणना कैसे बेहतर बना सकेगी? इसके विपरीत, अधिकांश राज्यों में आरक्षण की मांग सामाजिक रूप से शक्तिशाली समुदायों द्वारा अधिक राजनीतिक सत्ता पाने के संघर्ष के तौर पर सामने आई है। दरअसल, जाति जनगणना का असली कारण सत्ता में जातियों की भागीदारी का पता लगाना है। वैसे, यह कोई बुरी बात नहीं होती, अगर इससे भारत के एक राष्ट्र बनने में किसी तरह की बाधा नहीं आती। लेकिन, ऐसा नहीं है। कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि जातीय व भाषायी पहचान के साथ-साथ राष्ट्रीयता रह सकती है। भारतीयता की बात केवल दूसरे देशों के साथ प्रतिस्पर्द्धा या युद्ध के समय ही होनी चाहिए। हालांकि, उनका यह तर्क तभी तक चलेगा, जब वे संसदीय परिसीमन, वित्तीय संघवाद और क्षेत्रीय स्वायत्तता जैसे प्रश्नों से अनभिज्ञ बने रहेंगे। क्योंकि इन प्रश्नों का समाधान हम तब तक सौहार्दपूर्ण, परस्पर विश्वास के साथ नहीं कर सकते, जब तक कि एक राष्ट्र की भावना से हम ओत-प्रोत नहीं होंगे। भारतीयों के लिए राष्ट्रवाद केवल नारा नहीं, एकता, सुरक्षा और समृद्धि का केंद्र भी है। वास्तव में, हमारा कोई 'सार्वजनिक सरोकार' है ही नहीं, बल्कि कुछ अतिरंजना के साथ कहूं, तो इस देश में 'जनता' है ही नहीं, सिर्फ 'मैं' और 'मेरी जाति' है। यहां 'नागरिक समुदाय' नामक भावना बेहद कमजोर स्थिति में है। ऐसे में, आगामी जाति जनगणना 'करेला नीम चढ़ा' ही साबित होगी और यह जाति चेतना को और भड़का देगी। यह भाईचारे की हमारी भावना को कमजोर करेगी और जो कुछ हमारी सामाजिकता है, उसे नष्ट कर देगी। यह आर्थिक विकास को कम करेगी और नागरिकों को केवल उनकी 'जाति' में बांध देगी।

संविधान हमें सामाजिक न्याय की गारंटी देता है और सदियों से वैमनस्य और भेदभाव की बेड़ियों में जकड़े समाज को इससे मुक्त करने के उपाय भी बताता है। लेकिन सामाजिक न्याय की गाड़ी आरक्षण और कोटा से आगे बढ़ नहीं पा रही है। हमारी सदियों पुरानी रूढ़ियों को दूर करने के लिए नई सोच की जरूरत है और इसका पहला कदम तो यही होना चाहिए कि वर्तमान हालात और न बिगड़े। जातिगत चेतना को मजबूत करके जातीय भेदभाव को खत्म नहीं किया जा सकता।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

अपना धर्म खुद खोजें

भगवान महावीर ने धर्म की परिभाषा सरलता से की है : वस्तुओं का स्वभाव ही उनका धर्म है। अस्तित्व में हर वस्तु का एक निजी स्वभाव है, उसी को उसका धर्म कहते हैं। जैसे नीचे बहना पानी का स्वभाव है, ऊपर उठना ज्योति का। भाप हमेशा आकाश में विलीन होती है। शरीर का स्वभाव है धीरे-धीरे मरते जाना।

स्वभाव वह है, जो अनुकूल आ जाए, जो प्रीतिकर लगे, जो प्रेयस है, जिसके पास आते ही आप नाचने लगते हैं, जिसके पास होते आपकी ही सुगंध आपको घेर लेती है। स्वभाव प्रयास से नहीं मिलता, पहले से ही अपने स्वभाव के अनुकूल चलेंगे, तो सहज मिल जाएगा। मुश्किल इसलिए मालूम पड़ता है, क्योंकि लोग अपने स्वभाव से दूर चले गए हैं, बड़े नकली हो गए हैं।

झेन फकीर कहते हैं, अप्रयास से जो सध जाए, वही सत्य है; प्रयास से जो सधे, चेष्टा से जो सधे, उसमें कहीं कुछ गड़बड़ है। ओशो बहुत सुंदरता से समझाते हैं, 'कली को फूल बनने में कोई अड़चन आती है? कली को खींच-खींचकर फूल बनाना पड़ता है? पौधों को जमीन से खींच-खींचकर बाहर निकालना पड़ता है? वे अपने आप बढ़े चले आते हैं। कलियां खिल जाती हैं, फूल बन जाती हैं। फूलों से सुगंध बिखर जाती है हवाओं में और आकाश की यात्रा पर निकल जाती हैं। सब चुपचाप होता चला जाता है।

ऐसा ही आदमी भी है। पर आदमी की अड़चन यह है कि आदमी के पास सोच-विचार का यंत्र है, उससे अड़चन खड़ी होती है। आप किसी गुलाब के पौधे को सोच-विचार का यंत्र दे दो, बस मुश्किल हो जाएगी। फिर तो गुलाब मुश्किल में पड़ा, क्योंकि तब वह सोचेगा, कितना बड़ा फूल चाहिए? पड़ोसी गुलाब से ईर्ष्या भी जगेगी। ईर्ष्या के साथ राजनीति पैदा होगी, महत्वाकांक्षा जगेगी कि मैं सबसे बड़ा गुलाब खिलाऊं। सबसे बड़े गुलाब उगाने की जद्दोजहद में बड़ी चिंता खड़ी होगी, रात तनाव में रहेगा, नींद नहीं आएगी, दिन भर उदास रहेगा, गणित बिठाएगा : कैसे सबसे बड़ा हो जाऊं! डर यह है कि इस सब चिंता में जो ऊर्जा नष्ट होगी, उससे वह, वह भी न हो पाएगा, जो हो सकता था।'

मनुष्य पूरे अस्तित्व में सबसे बुद्धिमान प्राणी है, तो वह अपने स्वभाव में क्यों नहीं जी सकता? क्यों इतनी तकलीफ में जी रहा है? दरअसल, बुद्धि का दुरुपयोग हो रहा है; यदि सदुपयोग हो, तो बुद्धि आपसे सहयोग करेगी। आप जैन घर में पैदा हो गए, अब आपकी बुद्धि कहती है कि आप जैन हैं या जिस भी धर्म में पैदा हुए, वही आप हैं? धर्म एक रहस्य है, वह बहुत पुराना है, लेकिन बहुत नया भी। क्योंकि हर एक को अपना धर्म खुद खोजना पड़ता है। एक फूल के खिलने से सारे फूल तो नहीं खिल जाते। हर फूल को अलग से खिलना पड़ता है।

अस्तित्व में मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है, तो वह अपने स्वभाव में क्यों नहीं जी सकता? वह तकलीफ में है? दरअसल, बुद्धि का दुरुपयोग हो रहा है; सदुपयोग हो, तो ही बुद्धि उससे सहयोग करेगी।

अमृत साधना

पोप लियो XIV | ईसाई धर्मगुरु

यह धरती पूरी मानवता के लिए पर्याप्त भोजन पैदा कर सकती है, फिर भी दुनिया के बहुत से गरीबों को रोजाना की रोटी नहीं मिल पाती। यह स्थिति भूख व कुपोषण की त्रासदी को और ज्यादा शर्मनाक बनाती है।

हिन्दुस्तान | 75 साल पहले
21 जुलाई, 1950

अमरीका का इन्कार

हमारे प्रधान मंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने कोरिया-युद्ध को न फैलने देने के लिए जो शान्ति-प्रयास किया था, फिलहाल उसका अन्त हो गया है। शान्तिप्रेमियों के लिए यह एक दुखद घटना है और यह निश्चय ही आश्चर्य का विषय है कि शान्ति प्रयास पर वज्रपात उस रूस की ओर से नहीं हुआ, जिसको सारे बखेड़े की जड़ बताया जाता है बल्कि शान्ति की दुहाई देने वाले अमरीका ने उसमें साथ देने से इन्कार किया है। ब्रिटेन का रुख अधिकृत रूप से सामने नहीं आया, किन्तु छनकर जो संभावना सामने आ रही है, वह यही है कि काले भारत के बजाय वह गोरे अमरीका का ही पदानुसरण करना चाहता है। यह स्थिति इस संदेह को जन्म दे तो आश्चर्य नहीं कि अमरीकी गुट के पूर्वग्रह बड़े तीव्र हैं और जिस संघर्ष को वह अपने प्रतिस्पर्धी रूसी गुट के खिलाफ समझता है, उसमें भारत जैसे किसी ऐसे देश का पड़ना उसे पसन्द नहीं है, जो गुटों के अस्तित्व का ही विरोधी है और संकीर्ण स्वार्थों के बजाय विश्व-हित एवं विश्व-शान्ति की दृष्टि से सोचता व करता है।

नेहरूजी का शान्ति-प्रयास के सिलसिले में स्टालिन और अचेसन के साथ पत्र-व्यवहार जब प्रकाशित हो गया है, तब सब स्थिति सामने आ गई है और राय बनाने के लिए कल्पनाओं या अनुमानों की आवश्यकता नहीं रह गई। स्टालिन का जवाब जहां सद्भावनापूर्ण है वहां अमरीकी परराष्ट्र-मंत्री अचेसन ऊपर से मीठे रहते हुए भी चोट करते मालूम पड़ते हैं। यह तो वह कही कैसे सकते थे कि वह शान्ति नहीं चाहते या राष्ट्रसंघ को अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के लिए साधन नहीं बनाना चाहते, नेहरूजी की सदाशयता में अविश्वास दरसाना भी कूटनीतिज्ञता के विरुद्ध होता। अतः इन सबका उनके पत्र में उल्लेख है, परन्तु साथ ही यह स्पष्ट कर दिया गया है कि शान्ति या युद्ध-स्थगन की खातिर वह कोरिया के संबंध में ग्रहण किये अपने रुख में परिवर्तन करने को तैयार नहीं हैं, चीन के प्रतिनिधित्व का रूप बदलने की उनकी न मंशा है और न इसे वह इस मामले में मुद्दा ही बनने देना चाहते हैं। इसी प्रकार रूस को सुरक्षा-परिषद में लाने यानी संयुक्त राष्ट्र के बहिष्कार को खत्म कराकर उसे कारगर बनाने की भी उन्हें कोई उत्सुकता नहीं है। रूस और असली चीन के बगैर राष्ट्र संघ का अस्तित्व विश्व-संगठन के रूप में अधूरा और सदोष है।

लोग साफ-सफाई को आदत बनाएं

इस बार फिर इंदौर ने साफ-सफाई के मामले में देश के सभी शहरों को पीछे छोड़ दिया है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन, सफाई कर्मचारी और वहां के नागरिक बधाई के पात्र हैं। इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां साफ-सफाई से जुड़े अफसर कितनी ईमानदारी से अपना काम करते हैं। हालांकि, कुछ राज्य साफ-सफाई के मामले में अब भी फिसड्डी बने हुए हैं। यह स्थिति तब है, जब देश भर में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है और स्वच्छता बनाए रखना कोई मुश्किल काम नहीं है।

माना जाता है कि भारत में हर परिवार अपनी सालाना आमदनी का औसतन 15 से 20 फीसदी हिस्सा इलाज पर खर्च करता है। हम इसमें से कुछ पैसे बचा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें साफ-सफाई की आदतें अपनानी होंगी। मगर यहां तो सफाई का मतलब है, अपने घर को साफ करके कूड़ा-कचरा गली या मुहल्ले में फेंक देना। यह गलत है। इससे बीमारियां फैलती हैं, जो सभी को अपनी चपेट में ले सकती हैं, कूड़ा फेंकने वाले को भी। इसलिए, जब तक देश के सभी नागरिक स्वच्छता को अपना परम धर्म नहीं मानते और देश के शासक वर्ग व राजनेताओं में लोकसेवा-देशसेवा-समाजसेवा संबंधी स्वच्छता नहीं आती, तब तक हमारे देश के शहरों और गांवों में गंदगी पसरी रहेगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश, समाज साफ-सुथरा रहे, तो हमें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करना होगा। स्थानीय प्रशासन को भी इसमें तत्परता दिखानी होगी और लोगों को इसके बारे में बताना होगा।

अच्छी बात है कि सरकारें अपनी तरफ से देश में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कई अभियान चला रही हैं। लोगों को हरसंभव समझाया जा रहा है कि वे अपने आस-पास साफ-सफाई रखें। इसे सामूहिक जिम्मेदारी बताकर लोगों में सामाजिकता का बोध भी पैदा किया जा रहा है। मगर स्वच्छ भारत का सपना तब तक अधूरा है, जब तक देश के सभी नागरिक स्वच्छता के महत्व को समझते हुए इसके प्रति गंभीर नहीं हो जाते। साफ-सफाई की संकल्पना हमारे दिल-दिमाग में बस जानी चाहिए। जब तक हम शारीरिक और खान-पान की स्वच्छता की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तक तक हम आस-पड़ोस में साफ-सफाई के महत्व को भी नहीं समझ सकेंगे। हमें समग्रता में काम करना होगा। सरकार के प्रयासों से कदम मिलाना होगा और साफ-सुथरे समाज का निर्माण करना होगा।

स्वच्छता सर्वेक्षण जारी करने का मकसद भी दरअसल यही है कि देश के सभी इलाके साफ-सफाई को लेकर एक-दूसरे से स्पर्द्धा करें और स्वच्छ-स्वस्थ समाज बनाने में सहायता करें।

राजेश कुमार चौहान, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम
स्वच्छता सर्वेक्षण

स्थानीय प्रशासन की सुस्ती से गंदगी

स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर के फिर से नंबर वन बनने के बाद यह बहस नए सिरे से शुरू हो गई कि बाकी शहर क्यों नहीं इसको पछाड़ पा रहे हैं? इसकी कई वजहें हैं, लेकिन एक बड़ा कारण यह है कि बाकी जगहों पर स्थानीय प्रशासन उस तरह मुस्तैदी नहीं दिखाता, जिस तरह से इंदौर में हमें देखने को मिलता है। जब शिक्षक रोज स्कूल जाकर पढ़ाते हैं, अधिकारी ऑफिस जाकर काम करते हैं, ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं, मजदूर मजदूरी करते हैं, तब हम यही कहते हैं कि यह उनकी जिम्मेदारी है और उसे ही वह निभा रहे हैं। मगर जब बात नगर निगम या नगरपालिका के अधिकारियों-कर्मचारियों की आती है, तो हम यह कहकर बहस का रुख बदलने का प्रयास करते हैं कि साफ-सफाई तो सामूहिक जिम्मेदारी है, इसे सिर्फ उनके भरोसे छोड़ना उचित नहीं।

क्या इस सवाल का जवाब नहीं खोजा जाना चाहिए कि शहरों की नालियां क्यों साफ-सफाई के अभाव में अटकी रहती हैं? सड़कों पर जहां-तहां कूड़े के ढेर क्यों दिखते हैं? घरों से निकलने वाले कचरे का सही से निपटारा क्यों नहीं होता? बड़े शहरों में तो खैर दबाव में ही सही, नगर निगम या नगरपालिका कुछ हद तक काम करती दिखती भी है, लेकिन छोटे शहरों की स्थिति ज्यादा नारकीय हो जाती है। वहां हल्की बरसात होते ही सड़कों पर पानी जमा हो जाता है, क्योंकि नालियां तय समय पर शायद ही साफ की जाती हैं। लोग अपने घरों से कचरा निकालते हैं और यह सोचकर बाहर रखते हैं कि नगर निगम की गाड़ी उसे उठा लेगी, लेकिन अव्वल तो इन गाड़ियों के आने का कोई तय वक्त नहीं होता और फिर वे कहीं से कचरा उठाती हैं, तो कहीं छोड़ देती हैं। इस तरह बचा कचरा सड़कों पर पसर जाता है। पर्याप्त संख्या में सार्वजनिक शौचालयों का अभाव भी साफ-सफाई की व्यवस्था में पलीता लगाता है। इससे आम लोगों को परेशानी भी खूब होती है।

इन सभी तथ्यों को यहां रखने का मतलब यह नहीं कि लोगों की कोई गलती नहीं, निश्चय ही कई लोग साफ-सफाई की तय व्यवस्था को मानने से बचते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर व्यवस्था दुरुस्त हो जाए, तो लोग भी गंदगी करने से पहले सोचेंगे। आप इसे यूं समझिए कि जहां गंदगी होती है, लोग वहीं थूकते हैं, साफ जगहों पर वे आमतौर पर थूकने से बचते हैं। स्थानीय प्रशासन को इसी सोच के साथ साफ-सफाई का अभियान चलाना चाहिए और गली-गली में काम करना चाहिए। अगर एक बार प्रशासन ने सख्ती दिखा दी, तो यकीनन हर शहर साफ-सफाई के मामले में इंदौर से मुकाबला करते दिखेंगे।

रियांशी मिश्र, टिप्पणीकार

चिंतन

कामकाज का गवाह बने मानसून सत्र

आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, यह सत्र काफी हंगामेदार होगा, लेकिन समूचा सत्र हंगामे की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। सर्वदलीय बैठक में सरकार ने विपक्ष की सभी मांगों पर गौर करते हुए आश्वासन दिया है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार अपने आश्वासन पर कायम रहेगी व बीच में विपक्ष कोई अनर्गल मांग नहीं करेगा तो करीब एक माह के इस सत्र में कामकाज शांतिपूर्ण तरीके से हो सकता है। यह सही है कि संसद चलाना सभी सांसदों व दलों की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार का रुख अधिक मायने रखता है कि वह विपक्षी दलों को कितना विश्वास में लेती है। इससे पहले संसद के शीत सत्र के दौरान वक्फ बिल को लेकर काफी हंगामा हुआ था। इस सत्र में विपक्ष के पास कई एजेंडे हैं, जिस पर वह बहस चाहता है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जवाब चाहता है। इस दौरान अगर सत्ता पक्ष का अड़ियल रुख रहा तो, मानसूत्र में भी विपक्ष का हंगामा व नारेबाजी देखने को मिल सकती है। ऐसा हुआ तो यह सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ेगा। विपक्ष पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीजफायर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत व पाक के बीच संघर्ष विराम के अनेक बार मध्यस्थता के दावे, भारत की विदेश नीति, बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर), देशभर में मतदाता सूची पुनरीक्षण आदि मुद्दों पर संसद में बहस चाहता है। पहलगाम की आतंकी घटना व ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए 3 जून को 16 विपक्षी दलों ने पीएम मोदी को पत्र लिख कर विशेष संसद सत्र बुलाने की मांग की थी, जिसे सरकार ने यह कर टाल दिया था कि चर्चा मानसून सत्र में ही होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के साथ एक भी मुस्लिम देश समेत किसी देश का नैतिक रूप से साथ नहीं होने को विदेश नीति की विफलता कहकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेण रिजिजू ने कहा है कि इस सत्र में 17 विधेयक सरकार के एजेंडे में हैं। सत्र 21 से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा, पहले यह 12 अगस्त तक प्रस्तावित था। सत्र का समय बढ़ने के पीछे माना जा रहा है कि बिहार चुनाव को देखते हुए सरकार का कोई सीक्रेट एजेंडा है। हालांकि 13 से 18 अगस्त के बीच कोई बैठक नहीं होगी। अंतिम चार दिनों सरकार कोई महत्वपूर्ण बिल ला सकती है। प्रधानमंत्री द्वारा संसद में विपक्ष के मुद्दों पर स्वयं जवाब देने की संभावना बहुत कम है। जब भी भारत-पाकिस्तान संघर्ष पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर चर्चा होगी, सरकार उचित जवाब देगी। राजग सहित कई नेता ऑपरेशन सिंदूर पर विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के माध्यम से सरकार की विदेश पहुंच की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए चर्चा भी चाहते हैं। सरकार संसद में अपना विचार रखने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी मैदान में उतार सकती है। सरकार ने महीने भर चलने वाले सत्र के दौरान संसद के सुचारू संचालन में विपक्ष से सहयोग मांगा है। संसद को चलाने के लिए सरकार और विपक्ष के बीच समन्वय होना चाहिए, यह बहुत जरूरी है। सरकार का रुख लचीला हो और विपक्ष का मकसद संसद में केवल और केवल हंगामा न हो। सांसदों की कोशिश जनता के व्यय को अपव्यय करना न हो। संसद हंगामे का अखाड़ा बनने की बजाय कामकाज का राष्ट्रमंदिर बने। सत्र का साथर्कता ही देशहित में है। दलगत भावना से ऊपर उठकर सांसद अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी समझेंगे।

मानसून सत्र
प्रमोद भार्गव

21 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। यह आशंका कायम है कि विपक्षी दल संसद को ठप बनाए रखने में ही अपना समय जाया करेंगे। इस सत्र में लंबे समय तक चलने वाला हंगामा बिहार में मतदाता सूची के गहन परीक्षण को लेकर हो सकता है। बिहार में इस साल के अंत में होने वाले चुनाव को लेकर संसद में गतिरोध बनाए रखने की कोशिश युद्धस्तर पर होगी। सत्ता पक्ष के लिए राहत की बात यह है कि निर्वाचन आयोग के बिहार की मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक नहीं लगाई है, इस मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। अतएव विपक्ष इस मुद्दे के न्यायालय में विचाराधीन होने के बहाने को सुरक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करेगी।

अखाड़ा बनकर न रह जाए संसद

इक्कीस जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र को गर्माए रखने के लिए कांग्रेस समेत लगभग समूचे विपक्ष ने अपने-अपने हथियार भांज लिए हैं। गोया, यह आशंका कायम है कि विपक्षी दल संसद को ठप बनाए रखने में ही अपना समय जाया करेंगे। इस सत्र में लंबे समय तक चलने वाला हंगामा बिहार में मतदाता सूची के गहन परीक्षण को लेकर हो सकता है। चुनाव आयोग की इस बड़े प्रयास पर समूचा विपक्ष बड़े राजनीतिक संग्राम की तैयारी में जुटा है। लोकसभा चुनाव की तरह एक बार फिर से इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के दल एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से बैठक भी की है। इस हंगामे में मुख्य रूप से कांग्रेस, राजद और तृणमूल कांग्रेस कार्यस्थगन प्रस्ताव ला सकते हैं। अतएव आशंका है कि बिहार में इस साल के अंत में होने वाले चुनाव को लेकर संसद में गतिरोध बनाए रखने की कोशिश युद्धस्तर पर होगी। सत्ता पक्ष के लिए राहत की बात यह है कि निर्वाचन आयोग के बिहार की मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक नहीं लगाई है, इस मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। अतएव विपक्ष इस मुद्दे के न्यायालय में विचाराधीन होने के बहाने को सुरक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करेगी।

सरकार ने इस सत्र में 8 नए विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किए हैं। इन विधेयकों में मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक-2025, सार्वजनिक न्यास प्रणाली (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक-2025, भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक-2025, पुरातत्व धरोहर स्थल और अवशेष (संरक्षण और देखरेख विधेयक-2025, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक-2025 एवं राष्ट्रीय डोपिंग (कचरा) रोधी संशोधन विधेयक-2025 शामिल हैं। इन विधेयकों पर सहमति बनाए जाने की चर्चा से पहले विपक्ष चाहेगा कि पहलगाम हमले में गुप्तचर तंत्र की नाकामी, सैन्य ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विदेशी हस्तक्षेप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के दावों के बीच सेना के अभियान को अचानक क्यों रोका गया जैसे मुद्दों पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा हो। विपक्ष की मंशा, मुद्दों की सच्चाई से कहीं ज्यादा सरकार को घेरना है। सत्तारुढ़ पक्ष इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे बताकर चर्चा से बचने की कोशिश कर सकता है ? इन बड़े मुद्दों के अलावा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के निवास में लगी आग के दौरान नकद राशि जलने के मामले में महाअभियोग लाने की पैरवी करने के साथ ओडिशा की छात्रा के साथ हुए अत्याचार जैसे मुद्दे भी सदन में गरमा सकते हैं। न्यायमूर्ती वर्मा के मामले में सरकार को उम्मीद है कि यदि वह इस मुद्दे पर महाअभियोग चलाने का प्रस्ताव लाती है तो उसे सभी दलों का समर्थन मिल सकता है। संभव है इस प्रक्रिया के शुरू होने से पहले वर्मा इस्तीफा दे दें। यदि नहीं देते हैं तो संसद में इस मुद्दे पर तीखी बहस संभव है। यदि बहस होती है तो न्यायाधीशों की मनमानी नियुक्ति प्रक्रिया पर भी गहन विमर्श होना तय है।

कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल मतदाता सूची को लेकर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। जबकि सत्तारुढ़ दल चुनाव आयोग की जानकारी के आधार पर विपक्ष के

आरोपों का जवाब देने की तैयारी कर रहा है। बावजूद तेलुगु देशम पार्टी द्वारा मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण पर सवाल उठाए जाने से सरकार की चुनौतियां बढ़ी हुई हैं। इधर निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार का ऐसा बयान आया है, जिसे सरकार अपनी ढाल बनाने का काम करेगी। ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बिहार में एसआइआर के तहत मतदाता सूची को दुरुस्त करने के प्रयास में मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी देखने में आई है। बिहार के 7.9 करोड़ मतदाताओं में से महज 6.85 प्रतिशत मतदाताओं ने अब तक विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत गणना फार्म नहीं भरे हैं। हालांकि राहुल गांधी, ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव ने इस कवायद पर कई प्रश्न खड़े कर दिए हैं, जिन पर संसद में बहस हो सकती है। दरअसल समूचा विपक्ष इसलिए चिंतित है, क्योंकि पहली बार बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के नाम मतदाता सूचियों से हटाए जाने की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू हुई है। यही वह समय है, जब राज्यों में सत्तारुढ़ भाजपा सरकारें घुसपैठियों को देश से विस्थापित करने के राष्ट्रहितैषी काम में लगी हैं। इस बाबत असम के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने ठीक ही कहा है कि असम जैसे राज्य में घुसपैठिए एक ही धर्म के लोग हैं, जो कांग्रेस समेत गैर भाजपा दलों को वोट करते हैं। इन घुसपैठियों को बाहर कर देने से ये दल हार के खतरे को अनुभव कर रहे हैं। जबकि घुसपैठिए कई राज्यों का जनसांख्यिकी घनत्व बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। सम के सीमावर्ती जिलों अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जिलों की मतदाता सूची में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिकों के नाम मिले हैं। एक अनुमान के मुताबिक इनकी संख्या 15 लाख से अधिक हो सकती है। गृह विभाग ने भी कई जिलों में बांग्लादेशियों की संख्या को लेकर रिपोर्ट पेश की है। इसके अनुसार सीमांचल में अवैध घुसपैठियों के कारण कई जिलों का जनसांख्यिकी गणित पूरी तरह गड़बड़ा गया है। 1951 से 2011 तक देश की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी जहां चार प्रतिशत बढ़ी है, वहीं सीमावर्ती जिलों में यह आंकड़ा करीब 16 प्रतिशत है। सरकारी दस्तावेजों में ये लोग भारतीय नागरिक बनते जा रहे हैं। इस कारण उन्हें अनेक केंद्र एवं राज्य सरकार की लोककल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इस कारण उनका भारत की जमीन पर रहना आसान हो गया है। अतएव प्रस्तावित विधेयकों की बजाय मतदाता सूची पर ज्यादा हंगामा होना तय है। यदि संसद में राजनीतिक गतिरोध बना रहता है और संसद अखाड़े में तब्दील होती रही तो उन विधेयकों और अधिनियमों पर बारीकी से बहस संभव नहीं है, जो देश की 1.4 करोड़ जनता की भलाई व नियमन के लिए कानून बनने जा रहे हैं? प्रत्येक सांसद का दायित्व बनता है कि वह विधेयकों के प्रारूप का गंभीरता से अध्ययन करे, जिससे यह समझा जा सके कि उसमें शामिल प्रस्ताव देश व जनता के हित से जुड़े हैं अथवा नहीं? लेकिन राज्यसभा और लोकसभा का यह दुर्भाग्य है कि ज्यादातर सांसद अधिनियम के प्रारूप पर चर्चा करने की बजाय, ऐसे मुद्दों को बेवजह बीच में घसीट लाते हैं, जिनसे उनकी क्षेत्रीय राजनीति चमकती रहे। ऐसी स्थिति सत्तारूढ़ सरकार के लिए लाभदायी होती है, क्योंकि वह बिना किसी बहस-मुबाहिशे के ही ज्यादातर विधेयक पारित करा लेती है। जबकि विपक्ष सार्थक बहस करने की बजाय गाहे-बगाहे सरकार को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश में लगा रहकर संसद का समय जाया कर देता है। प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा की दृष्टि से यह स्थिति देशहित में कतई नहीं है। इस लिहाज से सत्तारूढ़ सरकार और दल का कर्तव्य बनता है कि वह राजनीतिक गतिरोध का समाधान, राजनीतिक तौर-तरीकों से ही निकाले।

(लेखक वरिष्ठ साहित्यकार और पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

बड़ी समस्या
राकेश अचल

कुत्तों की आवारगी पर बड़ी अदालत का रुख

इंसानों की आवारगी पर आज तक देश का कोई कुत्ता सर्वोच्च न्यायालय नहीं पहुंचा लेकिन इंसान आवारा कुत्तों के मुद्दे पर देश की सबसे बड़ी अदालत तक जा पहुंचा। संवेदनशील माननीय अदालत ने आवारा कुत्तों के बारे में याचिका सुनी भी और कुछ निर्देश भी दिए जो देशभर के कुत्ता विरोधियों के लिए एक सबक है। देश के आवारा कुत्तों की ओर से मैं सर्वोच्च न्यायलय का आभार व्यक्त करता हूं। मेरी दादी फूलकुंवर देवी निरक्षर थीं लेकिन सांसारिक मुद्दों पर उनका ज्ञान असीमित था। वे आवारा कुत्तों को उसी स्नेह से रोटी खिलाती थीं जितने स्नेह से गाय को। सनातन भारतीयों के लिए आवारा गाय फिर भी पूजनीय है लेकिन आवारा कुत्ता नहीं। दादी आवारा, बेसहारा कुत्तों को 'बिना झोली का फकीर' कहती थीं। कमोवेश यही बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को खाना देने से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से ही सवाल पूछ लिए। अदालत ने नोएडा में आवारा कुत्तों को खाना देने पर परेशान किए जाने का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा, "क्या हमें इन बड़े दिल वाले लोगों के लिए हर गली, हर सड़क खुली छोड़ देनी चाहिए? इन जानवरों के लिए तो पूरी जगह है लेकिन इंसानों के लिए कोई जगह नहीं है। आप उन्हें अपने घर में खाना क्यों नहीं देते? आपको कोई नहीं रोक रहा है।" यह याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट के मार्च 2025 के आदेश से संबंधित है। इस पर वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता को परेशान किया जा रहा है और वह पशु जन्म नियंत्रण नियमों के अनुसार सड़कों पर रहने वाले कुत्तों को खाना देने में असमर्थ है। पशु जन्म नियंत्रण नियमावली, 2023 का नियम 20 सड़कों पर रहने वाले पशुओं के भोजन से संबंधित है और यह परिसर या उस क्षेत्र में रहने वाले पशुओं के भोजन के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का दायित्व स्थानीय 'रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन' या 'अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन' या स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि पर डालता है। शीर्ष अदालत ने इस पर कहा, "हम आपको अपने घर में ही एक आश्रय स्थल खोलने का सुझाव देते हैं। गली-मोहल्ले के प्रत्येक कुत्ते को अपने घर में ही खाना दें।" याचिकाकर्ता के वकील ने नियमों के अनुपालन का दावा किया और कहा कि नगर प्राधिकार ग्रेटर नोएडा में तो ऐसे स्थान बना रहा है लेकिन नोएडा में नहीं। ऐसे स्थानों पर भोजन केंद्र बनाए जा सकते हैं जहां लोग अक्सर नहीं आते। पीठ ने इस पर पूछा, "आप सुबह साइकिल चलाने जाते हैं? ऐसा करके देखिए क्या होता है।" जब वकील ने कहा कि वह सुबह की सैर पर जाते हैं और कई कुत्तों को देखते हैं तो पीठ ने कहा, "सुबह की सैर करने वालों को भी खतरा है। साइकिल सवार और दोपहिया वाहन चालकों को ज्यादा खतरा है।" इसके बाद पीठ ने इस याचिका को इसी तरह के एक अन्य मामले पर लंबित याचिका के साथ संलग्न कर दिया। इससे पहले उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए नियमों के प्रावधानों को उचित देखभाल और सतर्कता के साथ लागू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया। न्यायालय ने कहा, "कानून के प्रावधानों के अनुसार गलियों में रहने वाले कुत्तों का संरक्षण आवश्यक है लेकिन साथ ही अधिकारियों को आम आदमी की चिंता को भी ध्यान में रखना होगा ताकि इन आवारा कुत्तों के हमलों से सड़कों पर उनकी आवाजाही बाधित न हो।" 2019 की पशुधन गणना के अनुसार, भारत में आवारा कुत्तों की संख्या लगभग 1.53 करोड़ थी, जो 2012 में 1.71 करोड़ थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में आवारा कुत्तों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है, और यह रेबीज जैसी बीमारियों के प्रसार का प्रमुख कारण भी है। भारत में कुत्तों की आवारगी भले ही एक राष्ट्रीय समस्या है लेकिन ये ही भारतीय कुत्ते को भगवान भैरव की सवारी मानकर उसे पूजते भी हैं। टोटके करने वाले लोगों को काले कुत्ते को रोटी खिलाने की सलाह देते हैं। हमारे समाज में कुत्ते की मौत को सबसे घृणित और निकृष्ट मानकर इसे गाली के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। दुर्भाग्य ये है कि देश में आवारा इंसानों के लिए हवालातें और मर्सी होम्स हैं। आवारा गायों के लिए गोशालाएं हैं लेकिन कुत्तों के लिए कोई माकूल इंतजाम नहीं है। कुत्ते आये दिन इंसानों की क्रूरता और नृशंसता के शिकार होते हैं, वाहनों से कुचले भी जाते हैं। विदेशों में कुत्ते इंसानों की तरह सम्मानित जीवन जीते हैं।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

शरणागति के संत 'गोस्वामी तुलसीदास'

संकलित
दर्शन

भगवान शंकर जी ने भी विष पिया और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी। दोनों ने समाज को रामकथामृत देकर धन्य कर दिया। संसार में और समुद्र में अमृत-मंथन करने पर विष अवश्य निकलेगा, पर उसमें राम को जोड़ दिया तो वह विष भी अमृत हो जाएगा। यही तुलसीदास जी ने किया- गरल सुधा रिपु करहिं मिताई, गोपद सिंधु अनल सित लाई। गरुड़ सुमेरु रेनु सम ताही, राम कृपा करि चितवा जाही।।
राम नाम के प्रति गोस्वामी जी की आस्था तो सावन मास के अंधे की तरह थी, जिन्हें राम प्रेम में सब हरा ही हरा दिखाई देता था। राम की कृपा के प्रति गोस्वामी तुलसीदास जी की यह जो दीनता और शरणागति है, यही उनका चरम पुरुषार्थ है। कृपा के मूल में पुरुषार्थ नहीं होता है, अपितु पुरुषार्थ के मूल में कृपा होती है। रामचरितमानस कृपासाध्य ग्रंथ है, साधन साध्य नहीं। कर्म, उपासना, साधन, अनुष्ठानादि सब ठीक हैं, पर यह सब पाने के साधन हैं, किंतु जिसके जीवन में प्राप्तव्य ही कृपा से प्राप्त हुआ हो, वह क्या करे? रामचरितमानस में पुरुषार्थ के चरम आदर्श श्री लक्ष्मण जी और कृपा के चरम आदर्श श्री भरत जी दोनों के आदर्श और सर्वस्व श्रीराम हैं। इसका तात्पर्य यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने वाल्मीकि जी, व्यास जी और जितने भी श्रेष्ठतम पुराणकार हुए सबकी वंदना की है, पर उन्होंने अपने ग्रंथ में न तो इतिहास को उठाया, न किसी ग्रंथ से कुछ लिया। इसीलिए श्रीरामचरितमानस भक्तों के हृदय सिंहासन पर विराजमान हो सका।

अहंकार ही समस्याओं का कारण

संकलित
प्रेरणा

एक बार नारद मुनि ने कामदेव को पराजित कर दिया तो इस बात का घमंड हो गया। इसके बाद नारद जी जहां जाते, वहां अपनी तारीफ करने लगते। ऐसे ही एक दिन वे शिव जी के पास पहुंच गए। नारद जी ने शिव जी के सामने अपनी प्रशंसा करना शुरू कर दी। शिव जी नारद मुनि की बातें सुनकर समझ गए कि इन्हें अहंकार हो गया है। शिव जी से विदा लेकर नारद मुनि विष्णु जी के पास पहुंच गए और विष्णु जी के सामने अपनी तारीफ करनी शुरू कर दी। विष्णु जी के सामने नारद मुनि ने अहंकार दिखाया तो विष्णु जी ने तय किया कि नारद जी भक्त हैं और इनका घमंड करना सही नहीं है। इसके बाद विष्णु जी ने अपनी माया रची। नारद मुनि विष्णु जी के यहां लौट रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक सुंदर राज्य दिखा। वे उस राज्य में पहुंचे तो वहां देखा कि एक राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा है। राजकुमारी बहुत सुंदर थी। उसे देखकर नारद ही मोहित हो गए और तुरंत ही विष्णु जी के पास पहुंच गए। नारद मुनि ने विष्णु जी से कहा कि आप मुझे सुंदर रूप दे दीजिए। ताकि मैं उस स्वयंवर राजकुमारी से विवाह कर सकूं। इसके बाद नारद मुनि उस स्वयंवर में पहुंच गए। विष्णु जी ने नारद मुनि को बंदर का मुख दे दिया था। स्वयंवर में नारद पहुंचे तो वहां बंदर जैसे मुख की वजह से उनका बहुत अपमान हुआ। गुस्से में नारद मुनि ने विष्णु जी को शाप दे दिया, लेकिन जब उनका मन शांत हुआ तो उन्हें पूरी बात समझ आ गई। जब नारद का घमंड टूटा तो उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी।

अंतर्मन

आज की पाती

सावन महीने से भगवान शिव का है शाश्वत संबंध

सावन हिंदू पंचांग का पांचवां महीना होता है। यह हरियाली, सुंदरता, सकारात्मकता, शुभता और पवित्रता का महीना होता है, जो प्राय: संपूर्ण सृष्टि के लिए नवोन्मेष एवं नवजीवन का उपहार लेकर आता है। सच कहा जाए तो ज्येष्ठ-आषाढ़ की तपती गर्मी, चिलचिलाती धूप, उमस और पसीने से परेशान संपूर्ण प्राणी जगत को सावन महीने की प्रतीक्षा रहती है, क्योंकि इस महीने में होने वाली रिमझिम वर्षा के कारण तापमान में गिरावट आती है और प्रकृति में सुखद परिवर्तन होते हैं। इसके परिणामस्वरूप संपूर्ण सृष्टि में तृप्ति और तुष्टि का प्रसार होता है तथा प्राणियों के जीवन में उमंग, उल्लास और प्रसन्नता का संचार होने लगता है। सारा संसार शिवमय हो जाता है।

-रमेश कश्यप, बिलासपुर

ट्रेंड

'एक पेड़ मां के नाम'

वन महोत्सव में माननीय न्यायाधीशों की भागीदारी हर किसी को प्रेरित करने वाली है। मुझे विश्वास है कि 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान को इससे एक नई गति मिलेगी।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

विनम्र श्रद्धांजलि!

भारत माता के वीर सपूत, अमर क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि! आपका बलिदानी और साहसिक जीवन स्वतंत्रता संग्राम की अमर गाथा है, जो सदैव हम सभी को राष्ट्रसेवा की प्रेरणा देता रहेगा।

-योगी आदित्यनाथ, सीएम, उप्र

नारी शक्ति मेरी प्रेरणा

मैं स्वयं को दिल्ली की हर उस नारी की प्रतिनिधि मानती हूं जो निस्वार्थ भाव से अपने घर, समाज और राष्ट्र की नींव को सींच रही है। वही नारी शक्ति मेरी प्रेरणा है, मेरा दायित्व है। उनकी आकांक्षाएँ नीतियों की दिशा तय करती हैं और उनका संघर्ष मेरे संकल्पों को दृढ़ता देता है।

-रेखा गुप्ता, सीएम, नई दिल्ली

युवाओं को रोजगार

महारोजगार मेला में उमड़ा जनसैलाब सिर्फ भीड़ नहीं, एक संदेश है कि बिहार का युवा अब रोजगार से अपना भविष्य चाहता है। नीतीश सरकार ने बिहार को जिस तरह बेरोजगारी की आग में झोंका, वहां से युवाओं को पलायन करना पड़ता है।

-राहुल गांधी, सांसद, कांग्रेस

अपने विचार
हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

करंट अफेयर

नेपाल के पीएम ओली मध्य सितंबर में भारत आएंगे

नेपाल के प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली सितंबर के मध्य में भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लोक बहादुर छेत्री ने कहा, प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा की तैयारियां जारी हैं। हालांकि, यात्रा की तारीख और विस्तृत कार्यक्रम अभी तय नहीं हुए हैं। हालांकि, प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि ओली 16 सितंबर को भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगे। सूत्रों ने बताया कि इस बार यह यात्रा संक्षिप्त होगी, संभवत: सिर्फ दो दिन के लिए ही होगी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (यूनिफाइड मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के अध्यक्ष ओली पिछले साल जुलाई में, चौथी बार प्रधानमंत्री बने थे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को सीपीएन-यूएमएल के नाम से भी जाना जाता है। ओली प्रधानमंत्री पद का संभालने के बाद पहली विदेश यात्रा के तौर पर भारत आने की बजाय चीन गए थे। उन्होंने पिछले वर्ष दिसंबर में चीन के प्रधानमंत्री ली. कियांग के निमंत्रण पर उक्त देश का दौरा किया था। ओली ने अपनी चार दिवसीय यात्रा के दौरान बीजिंग में पीकिंग यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम को संबोधित किया था तथा राष्ट्रपति शी चिनफिंग और प्रधानमंत्री कियांग से मुलाकात की थी।

ऑफ बीट

तेल व गैस कुओं के पास रहने वालों बच्चों को ल्यूकीमिया

'एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया' भले ही दुर्लभ होता है लेकिन यह बच्चों में होने वाले सबसे सामान्य कैंसरों में से एक है। यह अस्थि मज्जा में शुरू होता है और तेजी से बढ़ता है। इन मामलों में लंबे समय तक जीवित रहने की दर 90 प्रतिशत से अधिक है, लेकिन कई रोगियों को जीवन भर स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनमें हृदय संबंधी समस्याएं, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं और दूसरी बार कैंसर होने का अधिक जोखिम शामिल है। अमेरिका में कैंसर की कुल दर 2002 से घट रही है लेकिन बचपन में होने वाले 'एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया' के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यह प्रवृत्ति इस बीमारी के केवल इलाज पर ध्यान देने के बजाय रोकथाम की आवश्यकता को और भी अधिक रेखांकित करती है। अध्ययन सामग्री से पता चलता है कि तेल और प्राकृतिक गैस के कुओं से निकलने वाले रसायनों के संपर्क में आने से बच्चों में 'एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया' होने का खतरा बढ़ जाता है। हम पर्यावरण महामारी विज्ञान के अध्ययनकर्ता हैं, जो कोलोराडो और पेंसिल्वेनिया में तेल और प्राकृतिक गैस विकास कार्यों से जुड़े स्थलों के आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर इसके प्रभावों को समझने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

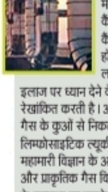

CCI NG 3.7 Product: NBTDelhiBS PubDate: 21-07-2025 Zone: Mahanagar Edition: 1 Page: NBTMAH10 User: dilip.lal Time: 07-20-2025 21:28 Color:

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । सोमवार, 21 जुलाई 2025

बहस हो, हंगामा नहीं

संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। देश के सामने अमेरिका के साथ ट्रेड डील और बिहार में चल रही वोटर लिस्ट की समीक्षा समेत कई मुद्दे हैं, जिन पर इस सेशन में चर्चा होने की उम्मीद है। विपक्ष ने एकजुटता दिखाते हुए अपना अजेंडा तय कर लिया है, लेकिन ध्यान रखना होगा कि सत्र शोर-शराबे की भेंट न चढ़ जाए।

ऑपरेशन सिंदूर । पाकिस्तान के साथ हुए टकराव को लेकर सरकार समय-समय पर जवाब दे चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वैश्विक समर्थन जुटाने के लिए उसने जब कई देशों में प्रतिनिधिमंडल भेजे, तो उनमें विपक्षी सदस्यों को भी जगह दी गई। लेकिन, फिर भी कुछ सवाल हैं, जिन पर विपक्ष सीधे प्रधानमंत्री से जवाब की उम्मीद कर रहा है। इसमें सबसे अहम हैं ये सवाल कि टकराव में भारत को कितना नुकसान हुआ और सीजफायर में अमेरिका ने क्या भूमिका निभाई।

मॉनसून सत्र आज से

सरकार पर दबाव । अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप लगातार दोहरा रहे हैं कि उन्होंने दोनों पड़ोसियों में शांति कराई। अब तो उन्होंने यह भी दावा कर दिया है कि संघर्ष में कुछ जेट गिरे थे। सरकार पर स्थिति स्पष्ट करने का दबाव होगा। इसी तरह, चुनाव आयोग का Special Intensive Revision केवल वोटिंग लिस्ट की समीक्षा तक सीमित नहीं रह गया है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी SIR की टाइमिंग को सही नहीं माना है, तो सरकार को कुछ कठिन प्रश्नों का सामना करना पड़ सकता है।

बजट सत्र का उदाहरण । संसद के बाहर सरकार और विपक्ष के सदस्यों में हाल में बेहद तल्खी देखने को मिली है। बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ, भाषा विवाद जैसे मुद्दों को लेकर टकराव हुआ है, लेकिन आशा की जानी चाहिए कि यह टकराव सदन के भीतर सकारात्मक बहस तक सीमित रहेगा। इस मामले में बजट सत्र को नजीर बनाया जा सकता है, जहां वक्फ बिल पर तीखी चर्चा के बावजूद दोनों सदनों ने अपनी क्षमता से बढ़कर काम किया।

बाधा नहीं बना विपक्ष । इस साल बजट सत्र में राज्यसभा की प्रॉडक्टिविटी 119%, जबकि लोकसभा की 118% रही। विपक्ष ने नई शिक्षा नीति, मणिपुर के हालात और बढ़ती रेल दुर्घटनाओं को लेकर सवाल पूछे थे। इस दौरान कुल 16 बिल पास हुए।

सदन पर खर्च । बजट सत्र के आंकड़े भले थोड़े अच्छे दिख रहे हों, पर आमतौर पर संसद से हंगामे की तस्वीरें ही ज्यादा आती हैं। पिछला शीत सत्र उदाहरण है, जब लोकसभा के 65 से ज्यादा घंटे बर्बाद हो गए। सत्र को चलाने में हर मिनट ढाई लाख रुपये से ज्यादा खर्च होते हैं। ऐसे में सदन का काम नहीं करना समय के साथ देश के संसाधनों की भी बर्बादी है।

चक्र-व्यू

दुख भी नहीं टिकता

राहुल पाण्डेय

बात ब्लैक एंड वाइट टीवी के जमाने की है। उसी दौरान हम बच्चों ने गुरुदत्त की फिल्म 'प्यासा' काफी बोर होते-होते देखी। फिल्म तो नहीं, अलबत्ता उसके कुछेक गीत याद रह गए। फिर तो अम्मा यानी नानी जब हम बच्चों की कुटाई करें, मुझे और मेरी बहन को फिल्म का एक गीत याद आने लगे। पूरे दुख में डूबकर छत या दुछत्ती का कोना खोजते, फिर बैठकर गाते। अम्मा मनाएं या न मनाएं, इसे गाने के बाद हम खुद-ब-खुद मान जाते थे। गीत के बोल थे, *'ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया। ये इंसा के दुश्मन समाजों की दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है!'* बच्चे थे, कितने भी कच्चे थे लेकिन इतना तो इससे पता ही चल जाता था कि इस दुनिया में कुटाई के अलावा और कुछ नहीं रखा है। चाहे अम्मा कूटें या समाज! अम्मा सभ्य बनाने के लिए कूटा करती थीं और समाज अम्मा बनने के लिए! गुरुदत्त आज भी अगर सबकी आंखों में बसे और दिमाग पर चढ़े हुए हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने आम लोगों के जीवन से जुड़े मुद्दों पर फिल्में बनाईं और रिश्तों को भी नई नजर से देखने वाला सिनेमा दिया। आज भी उनके गीत की वो बात नहीं भूलती- *'मेरे सामने से हटा लो ये दुनिया, तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया।'*

गुरुदत्त की फिल्में देखकर शायद पहली बार हमें अपने-आप से बात करने का शऊर आया। हमने सीखा कि बहुत सारे गम ऐसे भी होते हैं, जिन्हें अगर खुद को ही बता दिया जाए तो कुछ न कुछ तो कम हो ही जाते हैं। या फिर छत पर जाकर हवा में बोल दिए जाएं तो उड़ भी जाते हैं। बाद में यही सीन इरफान खान और कोंकणा सेन की मूवी 'लाइफ इन अ मेट्रो' में दिखा। उसमें इरफान दुख निकालने के लिए काफी तलाश करने के बाद शहर से दूर एक निर्जन सी इमारत की छत पर पहुंचते हैं और जोर-जोर से चिल्लाते हैं। मूवी में उन्हें लाइफ को लेकर करीब-करीब कॉन्फिडेंट दिखाया गया है। वैसे अकेले में चिल्लाने वाले सीन और भी कई फिल्मों में हैं, मगर उनमें ब्लैक एंड वाइट फिल्में कम हैं। श्वेत-श्याम से रंगीन तक के इस सफर में दुख अब कोने में छुपकर गाने नहीं गाता, खुले निर्जन में आकर चिल्लाने भी लगा है। बुद्ध ने सही कहा था, कुछ भी नहीं टिकता, दुख भी।

एकदा

समस्या में समाधान

एक दिन महात्मा बुद्ध जब शिष्यों की सभा के बीच पहुंचे, तो उनके हाथ में कपड़े का एक टुकड़ा था। आमतौर पर वह अपने पास कुछ भी नहीं रखते थे। यह देख शिष्य हैरान थे। एक शिष्य ने देखा कि आसन पर बैठने के बाद बुद्ध ने उस कपड़े में थोड़ी-थोड़ी जगह छोड़कर पांच गांठें लगा दीं। फिर उन्होंने शिष्यों से पूछा, 'क्या गांठ लगाने के बाद भी कपड़ा वैसा ही है, जैसा गांठ लगाने के पहले था? एक शिष्य ने कहा, 'तथागत, कपड़ा वही है, क्योंकि इसके मूल तत्व में कोई

Subrata Dhar

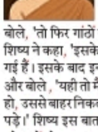

परिवर्तन नहीं हुआ। हां, गांठ लगने से उसका स्वरूप जरूर बदल गया, लेकिन उसकी मूल प्रकृति नहीं बदली है। इसका केवल बाह्य रूप ही बदला है।' बुद्ध अब गांठें खोलने के लिए दोनों सिरों को खींचने लगे। शिष्य बोला, 'तथागत, इस तरह तो ये गांठें और भी कस जाएंगी। ऐसा करने से गांठें खुलेंगी नहीं।' बुद्ध बोले, 'तो फिर गांठों को खोलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए?' शिष्य ने कहा, 'इसके लिए पहले देखना होगा कि ये गांठें लगाई कैसे गई हैं। इसके बाद इन्हें खोलना आसान हो जाएगा।' बुद्ध मुस्कुराए और बोले, 'यही तो मैं बताना चाहता था कि जिस समस्या में तुम पड़े हो, उससे बाहर निकलने के लिए जानना जरूरी है कि समस्या में कैसे पड़े।' शिष्य इस बात को समझ चुके थे कि समस्या के कारणों को खोज लें तो समस्या का समाधान निकालना आसान हो जाता है। यानी मूल कारण है समस्या।

संकलन : ललित गर्ग

भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जिसे आगे चलकर सेना में शामिल किया जाएगा

हाइपरसोनिक से कलाम का सपना पूरा

रंजीत कुमार

मिसाइलों की दुनिया में भारत उस मुकाम तक पहुंच गया है जहां अमेरिका, रूस और चीन पहुंचे हुए हैं। रक्षा शोध एवं विकास संगठन (DRDO) ने आवाज से आठ गुना अधिक गति वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिसे अगले कुछ सालों के अंदर सेना में शामिल किया जा सकता है। विष्णु प्रॉजेक्ट के तहत भारतीय रक्षा वैज्ञानिकों ने स्क्रैमजेट इंजन आधारित जिस मिसाइल का परीक्षण 12 से 14 जुलाई के दौरान किया, उसका कोई औपचारिक नाम नहीं है, इसे फिलहाल Extended Trajectory Long Duration Hypersonic Cruise Missile (ET-LDHCM) कहा जा रहा है।

कलाम का पहलू। स्क्रैमजेट इंजन पर आधारित हाइपरप्लेन की परिकल्पना डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के कार्यकाल में की गई थी। तब इसे एक दिवास्वप्न बताया गया था। लेकिन पिछले दो दशकों के अथक प्रयासों के बाद अब भारतीय रक्षा वैज्ञानिक इसे साकार कर रहे हैं।

पृथ्वी-अग्नि से अलग। हाइपरसोनिक मिसाइलें आवाज से पांच गुना अधिक मारक गति (mach-5) से हमला करती हैं, जबकि पृथ्वी मिसाइल या मध्यम दूरी तक मार करने वाली अन्य मिसाइलें इससे कम गति वाली यानी सुपरसोनिक कही जाती हैं। भारत ने सबसे अधिक मारक गति वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल (mach-2.8) बनाई है, जो कि दुनिया में सबसे तेज गति वाली क्रूज मिसाइल मानी जाती है। इसी मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के नौ वायुसैनिक अड्डों को तहसनहस कर अपनी जबर्दस्त विध्वंसक ताकत दिखाई थी।

दर्जनों मिलाइलों का विकास। हाइपरसोनिक मिसाइलों की खासियत यह है कि इसे दुश्मन की कोई भी हवाई रक्षा प्रणाली आसमान में मार कर गिरा नहीं सकेगी। DRDO के प्रॉजेक्ट विष्णु के तहत विभिन्न किस्मों की ऐसी दर्जन मिसाइलों का विकास किया जा रहा है, जो हाइपरसोनिक गति वाली होंगी। इनमें विमान से लॉन्च करने, युद्धपोत से छोड़ने और जमीन से लॉन्च करने वाली किस्में शामिल हैं।

जल-थल-नभ तीनों में अजेय। हाइपरसोनिक मिसाइलों को यदि युद्धपोतों पर तैनात किया जाए तो यह दुश्मन के पोतों के लिए काल बन सकती हैं क्योंकि इसके हमले को बीच आसमान में रोकने वाली कोई काट नहीं है। इसी तरह इसे विमान से छोड़ा जाए तो दुश्मन के इलाके में काफी भीतर तक मार की जा सकती है। जमीन से भी दुश्मन के ठिकानों पर अचूक मार की जा सकती है। इस तरह जल-थल-नभ में यह हाइपरसोनिक मिसाइल दुश्मन के लिए काफी विनाशकारी साबित होगी।

सैनिकों की जान का बचाव। दुश्मन के इलाके में भीतर मार करने के लिए लड़ाकू विमानों को जोखिम मोल लेते हुए दुश्मन के वायु क्षेत्र में जाना होता है। लेकिन उन्हीं ठिकानों को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से भी ध्वस्त किया जा सकता है। इसमें अपने किसी सैनिक के शहीद होने का खतरा नहीं रहता है। जाहिर है, भविष्य के युद्ध में मिसाइलों का अधिक से अधिक इस्तेमाल होगा जैसा कि हम इस्राइल ईरान युद्ध में पिछले महीने देख चुके हैं।

पलट सकता है पासा। भारत ने पृथ्वी (350 किमी), अग्नि-1 से अग्नि-5 (1500, 2000, 3000, 4000, 5000 से अधिक किमी तक मार करने वाली मिसाइलें) तैनात की हैं। लेकिन इन्हें एंटी मिसाइल प्रणाली से बीच आसमान में रोका जा सकता है, जबकि नई पीढ़ी की विष्णु हाइपरसोनिक मिसाइलों से युद्ध का पासा ही पलटा जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइलों ने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ दी थी, लेकिन नई विष्णु मिसाइलें तो दुश्मन की संपूर्ण मिसाइल रक्षा प्रणाली को बेकार साबित कर देंगी।

हवा के ऑक्सिजन से ईंधन। नवीनतम भारतीय हाइपरसोनिक मिसाइल की एक खासियत यह है कि ये स्क्रैमजेट इंजन से संचालित होती हैं, जो हवा से ऑक्सिजन लेकर अपना ईंधन बनाते हैं। ये मिसाइलें 11 हजार किमी. प्रतिघंटे की गति से 1500 किमी. दूर तक वार कर सकती हैं। इन पर 2000 किलो का परमाणु या पारंपरिक बम रखा जा सकता है।

हाइपरसोनिक का जमाना । हाल के रूस-यूक्रेन और इस्राइल-ईरान युद्धों में जिस तरह बैलिस्टिक मिसाइलों ने अपना दमखम दिखाया है, उसके मद्देनजर आने वाले सालों में सैन्य ताकतों द्वारा लंबी दूरी की तेज मारक गति वाली मिसाइलें हासिल किए जाने पर जोर बढ़ेगा। लेकिन जिन देशों के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें होंगी वे दुश्मन सेना पर आसानी से हावी हो सकेंगी। हालांकि चीन भी हाइपरसोनिक मिसाइल चला सकता है, जिसे लेकर अमेरिकी रक्षा हलकों में तो चिंता है ही, भारतीय सेना भी अपने स्तर पर सजग है।

बदलेगा शक्ति संतुलन। ऐसी स्थिति में यदि भारतीय सेना के पास हाइपरसोनिक मिसाइल आ जाए तो इससे चीन की सेना में भी खौफ पैदा होगा। खासकर, पाकिस्तान की सेना के लिए तो ये मिसाइलें मौत का पैगाम ही साबित होंगी। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के भारतीय सेना में शामिल हो जाने से दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन काफी हद तक भारत के पक्ष में झुक सकता है।

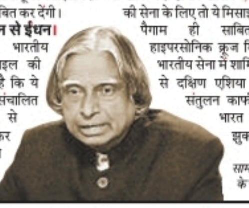

(लेखक सामरिक मामलों के जानकार हैं)

चिट्ठी आज भी लाती है ख़ुशियों का संदेश

AI Image

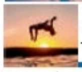

जीवन आनंद

शैलेंद्र पांडेय

अंटार्कटिका के बर्फीले रेगिस्तान से बस ठंडी हवाएं ही नहीं, कुछ संदेश भी आते हैं। यहां के Goudier Island पर स्थित है दुनिया का सबसे दूरस्थ डाकघर Port Lockroy। हर साल हजारों पोस्टकार्ड भेजे जाते हैं यहां से। आईलैंड घूमने आने वाले पर्यटक अपने दोस्तों-रिश्तेदारों को यादगार के रूप में पोस्ट भेजते हैं।

इस द्वीप की सैर जितनी मुश्किल है, उतना ही कठिन है डाक का यहां से निकलना। कई हफ्तों लंबी यात्रा है, जिसमें कागज पर लिखे संदेश महासागर की लहरों की सवारी करते हैं, हवाई जहाज पर चढ़ते हैं और फिर धक्के खाते हैं बस-ट्रेन में। लेकिन, सारी मशक्कत सफल हो जाती है, जब तय पते पर डाकिया दरवाजा खटखटा कर कहता है - आपके लिए चिट्ठी आई है। क्या यह अनुभूति कोई डिजिटल मेसेज दे सकता है?

आज के वक्त में भी खत जिंदा हैं, क्योंकि ये केवल संदेश नहीं देते। इनमें भेजने वाले की भावनाएं छिपी होती हैं। हम कागज पर बस शब्द नहीं उकेरते, अपने जज्बात की नदी बहाते हैं, जिसे पढ़ने वाला अपने दिल के भीतर महसूस करता है। यह अनुभव, संवाद, प्रतीक्षा और आत्मीयता - यही तो है पत्र लिखने और पढ़ने का असली आनंद। न फोन की घंटी बजी और न स्क्रीन पर रोशनी हुई। बस हाथों से लिखे शब्द चमक उठते हैं और पढ़ने वाले का मन धीरे-धीरे उसमें उतरता जाता है।

टाइप किए संदेश व्यवस्थित हो सकते हैं, लेकिन खूबसूरती तो आती है लिखाई के टेढ़े-मेढ़े अक्षरों में ही। इसमें मिलावट होती है भावनाओं के उतार-चढ़ाव की। लिखने वाले ने किन हालात में लिखा होगा, अंदाजा लगा लेता है इसे पढ़ने वाला। पत्र सहूलियत नहीं देते सुंदर फॉन्ट के पीछे खुद को छिपाने की। सच को सच दिखाने वाले ऐसे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं अब।

आज के डिजिटल युग में जब सब कुछ इंस्टेंट है, तब एक पत्र किसी खजाने से कम नहीं। उसमें लिखी हर पंक्ति, हर लकीर, हर रुकावट एक कहानी कहती है। उसमें भावनाएं होती हैं, सच्चाई होती है और अक्सर आंसू या हंसी के कुछ छींटे भी। पत्रों ने ही सभ्यताओं को जोड़ा, सरकारें बनाईं। गुप्त साम्राज्य ने धावकों और घुड़सवारों को तैयार किया, जो तेजी से सरकारी संदेश पहुंचा सकें। चीन के शासकों ने हर थोड़ी दूरी पर पोस्टल स्टेशन बनाए, तो रोमन सम्राटों ने cursus publicus। मुगल अपने फरमान डाक चौकियों से भेजते थे, जबकि कुछ अरसे में ही मुगलों की नींव हिलाकर रख देने वाले शेरशाह सूरी ने खड़ी कराईं कोस मीनारें। सत्ता को टिकने के लिए संदेश चाहिए। तलवार में धार कितनी भी हो, लेकिन आखिर में बात आ टिकती है गिनती के कुछ शब्दों पर। वरना ब्रिटेन को अपने जमाने में जमीन और समुद्र, दोनों रास्तों को मिलाकर एक Overland and Sea Mail Route तैयार करने की जरूरत न पड़ती।

SMS जल्दबाजी में भेजे जाते हैं, वॉट्सऐप इमोजी से भरे होते हैं और ई-मेल औपचारिकताओं से। इनमें बैलेंस बनाता है पत्र, याद दिलाता है कि AI के दौर में हम अब भी इंसान हैं। मेसेज का रिप्लाई पाने की जल्दी के बीच पत्र बताता है कि हर मेसेज रिप्लाई के लिए नहीं होता।

शेयर करें अपना अनुभव

जीवन की दिनचर्या के अनुभवों में आप कैसे आनंद महसूस करते हैं, भेजिए इस मेल आईडी पर **nbtreader@timesofindia .com** और सब्जेक्ट में लिखें 'जीवन आनंद'

चीन के माथे से यह दाग़ नहीं मिटेगा

मृत्युंजय राय

Daughters of the Bamboo Grove में लेखिका बारबरा डेमिक (Barbara Demick) ने चीन की 'One child policy' के एक त्रासद पहलू की ओर ध्यान दिलाया है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले यह समझते हैं कि इस पॉलिसी ने चीन को कितना नुकसान पहुंचाया। चीन में 2011 से ही कामकाजी आबादी घट रही है। 2022 के बाद से कुल जनसंख्या में भी कमी आ रही है। चीन सरकार अब अपने यहां नागरिकों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन इसमें भी अभी तक कामयाबी मिलती नहीं दिख रही।

AI Image

विचार विंडो

अब आइए चीन की 'One child policy' के उस त्रासद पहलू की बात करते हैं, जिसका जिक्र ऊपर किया गया है। इस नीति की वजह से चीन में बड़ी संख्या में जबरन Abortions हुए। जिन लोगों को इस पॉलिसी का उल्लंघन करते पकड़ा गया, उन पर भारी जुर्माना लगाने के बाद नसबंदी भी कर दी गई। किसी दंपती का दूसरा बच्चा तब अवैध माना जाता था, इसलिए उस दूसरे बच्चे को Identity papers नहीं दिए जाते थे। ऐसे में वह बच्चा सरकारी स्कूल में दाखिला नहीं ले पाता था।

एक अमेरिकी अखबार की China correspondent रह चुकीं बारबरा इस किताब में लिखती हैं कि One child policy के कारण अवैध बच्चों को उनके माता-पिता से छीनकर International adoption के लिए दिया गया और इससे सरकारी अधिकारियों ने खूब पैसा बनाया। बारबरा लिखती हैं कि 1991 में चीन के International adoption की इजाजत देने और पिछले साल इस पर प्रतिबंध लगाने के बीच 1.60 लाख बच्चों को विदेशियों ने गोद लिया। जानकारों का हवाला देते हुए वह बताती हैं कि इनमें से 10% को जबरदस्ती उनके माता-पिता से छीना गया था। अक्सर यह काम परिवार नियोजन विभाग से जुड़े अधिकारी करते थे। वे माता-पिता से बच्चों को छीनकर सरकारी अनाथालयों को देते और वहां से उन्हें विदेश भेजा जाता। बारबरा बताती हैं कि इस काले कारनामे को छुपाने के लिए लोकल मीडिया में यह इश्तहार दिया जाता था कि मां-बाप ने अपने इन बच्चों को छोड़ दिया है। अक्सर जिन अखबारों में इस तरह के नोटिस छपवाए जाते, वे उन गांवों में नहीं बिकते थे, जहां के बच्चों को अधिकारी उठाकर लाते थे। बारबरा ने किताब में यह भी लिखा है कि इस तरह के ज्यादातर चाइनीज बच्चों को अमेरिकी अभिभावकों ने गोद लिया। उन्हें लगता था कि चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से इन बच्चों को बेसहारा छोड़ दिया गया है।

बारबरा के मुताबिक, One child policy के पहले दो दशकों में परिवार नियोजन महकमे की सख्ती के कारण कई लड़कियों को उनके माता-पिता को छोड़ना पड़ा था। गोद लेने वाले विदेशी अभिभावकों को अडॉप्शन फीस के अलावा बच्चे के माता-पिता को जो कैश देना पड़ता था, वह वहां के लिए बहुत बड़ी रकम थी। फिर अनाथालय भी अडॉप्शन फीस पर बच्चों की देखरेख के लिए आश्रित होते गए, जिनके पास तब संसाधनों की कमी थी। जाहिर तौर पर इस पूरे धंधे में जिन अधिकारियों की मिलीभगत थी, वे ऊपरी कमाई कर रहे थे।

सेहत नहीं, संभावनाएं

प्रणव प्रियदर्शी

इसी महीने की 9, 10 और 11 तारीख को सार्क (साउथ एशियन असोसिएशन फॉर रीजनल को-ऑपरेशन), यूनिसेफ, WHO और अन्य पार्टनर्स की ओर से कोलंबो में आयोजित एक सम्मेलन में इस पर जोर दिया गया कि एनीमिया दक्षिण एशियाई देशों के लिए स्वास्थ्य संबंधी बड़ी चुनौती बना हुआ है। इन देशों में टीनेज लड़कियों और महिलाओं की कुल आबादी का लगभग आधा हिस्सा इस मर्ज की जकड़ में है। यही नहीं, अगर कोई कारगर पहल नहीं हुई तो अगले पांच साल में 1.8 करोड़ और लड़कियां इसकी चपेट में आ जाएंगी। अपने देश की ही बात करें तो 15-49 वर्ष के उम्र समूह की 57% और प्रेग्नेंसी से गुजरती 52% महिलाएं तो 5 साल से कम उम्र के 67% बच्चे एनीमिक हैं। जाहिर है, यह कोई छोटी संख्या नहीं है। लेकिन जैसे ही हम समस्या को समझने या इसे हल करने की ओर कदम बढ़ाते हैं, यह स्पष्ट होने लगता है कि समाज में जड़ जमाए बैठे जेंडर से जुड़े पूर्वाग्रह इस रास्ते की सबसे बड़ी बाधा हैं। पीरियड्स और प्रेग्नेंसी के दौरान वैसे भी महिलाओं को पोषक भोजन की जरूरत होती है, लेकिन भारतीय संस्कृति यह बताती है कि महिलाओं को सबसे आखिर में और सबको खिलाने के बाद ही भोजन करना चाहिए। भोजन का सबसे स्वादिष्ट और समृद्ध हिस्सा परिवार के दूसरे सदस्यों को खिलाने के बाद बचे-खुचे से काम चलाना ही त्याग की प्रतिमूर्ति भारतीय नारी की गरिमा के अनुकूल है। ऐसे में अपने स्वास्थ्य का खुद ख्याल रखने का 'स्वार्थी' रवैया वह भला कैसे अपना सकती है! लेकिन, हालात न सुधरे तो नुकसान केवल लड़कियों, महिलाओं और बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य का ही नहीं होगा, इकॉनमी में बन रहे नए अवसर यूं ही दम तोड़ देंगे, लेबर फोर्स में लड़कियों का प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा और मार्केट को एक्सप्लोर करने की कई सारी संभावनाएं सिर्फ संभावनाएं ही बनी रह जाएंगी।

AI Image

आधी दुनिया

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

भारत के पास मौका

19 जुलाई का संपादकीय 'काम अभी अधूरा' पढ़ा। The Resistance Front (TRF) को अमेरिका द्वारा वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किया जाना भारत की कूटनीतिक सफलता है। TRF लश्कर-ए-तैयबा का ही नया रूप है, जिसे पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय दबाव से बचने के लिए खड़ा किया था। TRF के खिलाफ कार्रवाई तभी प्रभावी होगी जब इसके संरक्षक पाकिस्तानी सेना और ISI को भी कठघरे में लाया जाए। अमेरिका को केवल प्रतीकात्मक प्रतिबंधों से आगे बढ़कर इस्लामाबाद पर ठोस दबाव बनाना होगा। भारत के पास सुनहरा मौका है कि वह TRF के जरिए पाकिस्तान के आतंकवाद के नेटवर्क को वैश्विक मंचों पर उजागर करे।

धीरेंद्र कटारिया, ईमेल से

बस मन दुरुस्त रखें

जीवन आनंद कॉलम में 14 जुलाई को प्रकाशित लेख 'उम्र का इशारा कहीं गलत तो नहीं समझ रहे' पढ़ा। उम्र के पड़ाव पर हर दिन हमें कुछ नया सिखा जाता है। आज जो गलतियां हुई हैं कल वही गलतियां सीख देती हैं कि उन्हें न दोहराया जाए। इस तरह गलतियां हमें बेहतर बनाती चलती हैं। युवा भी बड़ों के ऐसे अनुभवों से सीखकर जिंदगी की राह को आसान बना सकते हैं। बढ़ती उम्र का यही अनुभव समाज को सही दिशा मे ले जाने में भी सहायक होता है। बस बढ़ती उम्र के साथ अपने मन-मिजाज पर ध्यान देने की जरूरत होती है।

पैंथर तोमर, किशन गंज

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

ट्रंप ने फिर किया भारत-पाक के बीच मध्यस्थता का दावा - खबर

- एक झूठ सौ बार बोलकर उसे सच बनाना चाहते हैं शायद!

मीनाक्षी रावत

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

www.speakingtree.nbt.in

जीवन का हर दिन कोरे काग़ज़ जैसा कुछ सुंदर लिखिए

प्रेम रावत जी

जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वैसा आनंद हमारे भीतर पहले से ही है। लेकिन आनंद पाने के लिए हम दूसरों के पीछे भागते रहते हैं। हमारे जीवन में हर दिन उल्लास और उमंग के साथ आता है। लेकिन अपने जीवन के अंदरूनी अध्याय में झांक कर देखें, तो हर दिन कोरे कागज की तरह आता है हमारे सामने। अपनी कलम से उस पर हम कुछ न कुछ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सिर्फ हमें मालूम है। कल इस कोरे कागज पर हमने क्या लिखा?

कुछ लिखा तो था, लेकिन इतनी जल्दी में थे कि पढ़ भी न सके। समझने के पहले ही पन्ना पलट गया। कई बार तो कलम को कागज पर रख कर सोच ही रहे थे कि क्या लिखा जाए और इतने में पन्ने को पलटने का समय आ गया। कागज कोरा ही छूट गया। क्यों हुआ ऐसा, जबकि जीवन की हर सांस उस स्याही से भरी है, जिससे जिंदगी को कोई नया मोड़ दे सकते हैं। कलम हमारे हाथ में, सांसों की स्याही और पन्ना हमारे सामने - फिर लिखने में क्या दिक्कत?

कोल्हू में जुता बैल एक लकीर पर चलता जाता है। उस वक्त उसके मन में विचार आता होगा कि कितना चल लिया, कहां से कहां पहुंच गया! लेकिन, जब आंखों से पट्टी खोली जाती है, तो उसे पता चलता है कि जहां था, वहीं पर है। कहीं भी नहीं गया। चला तो कई मील, लेकिन पहुंचा कहीं नहीं। इस दुनिया की भी यही हालत है। इसने हर इंसान को एक बैल की तरह बना दिया है। हम कर्म तो करते हैं, पर यह नहीं मालूम कि क्यों कर रहे हैं। इसका क्या फल होगा, क्या हमको करना चाहिए था - इन सवालों के बारे में कभी नहीं सोचते। बस कुछ न कुछ करते रहते हैं।

इसलिए अपनी जिंदगी में आंखें खोल के काम कीजिए, अंधविश्वास से नहीं। आंखों पर पर्दा पड़ा रहा, तो जीवन हाथ से निकल जाएगा। जो पन्ने मिले हैं आपके नाम के, उस पर कुछ ऐसा लिखने की कोशिश कीजिए, जो सुंदर और अर्थपूर्ण हो - जो देखने, सुनने और पढ़ने में अच्छा हो। जो भीतर से मधुर है, उसमें बाहर भी मधुरता ही होगी। अगर अंदर क्लेश है, कपट है, तो बाहर भी वही आएगा।

लोगों को चिंता लगी रहती है कि क्या लिखूं, सब कुछ तो बदलता रहता है। अगर आपको लगता है कि चीजें ठीक चल रही हैं, तो थोड़ा इंतजार करें - सब कुछ बदल जाएगा। अगर आपको लगता है कि चीजें बुरी चल रही हैं, तो थोड़ा इंतजार करें - तब भी सब कुछ बदल जाएगा। आप बदलते हैं। आपके सोचने का तरीका बदलता है। विचार बदलते हैं। दुनिया बदलती है। लेकिन, एक चीज नहीं बदलती है और वह है इस सांस का आना-जाना। इसलिए सांस के इस उपहार में अपना आराम खोजें। इस वास्तविकता में अपना आनंद तलाशें। इसके लिए ठहरकर देखना होगा।

प्रस्तुति : आर.डी. अग्रवाल 'प्रेमी'

दैनिक जागरण
लोकहित के लिए की गई याचना उत्तम होती है

कृपया सार्थक चर्चा करें

यह अच्छी बात है कि संसद के मानसून सत्र में सरकार पहलगाम में आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान के खिलाफ किए गए आपरेशन सिंदूर पर चर्चा को तैयार है। इस तैयारी के अनुरूप सरकार का कार्य और व्यवहार होना भी चाहिए और दिखना भी। इसी तरह विपक्ष को भी आपरेशन सिंदूर और इससे जुड़े अन्य विषयों पर गंभीर चर्चा के लिए तत्पर दिखना होगा। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि दोनों सदनों के सुचारु संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक में पक्ष-विपक्ष के बीच इस विषय पर सहमति बनी, क्योंकि अभी तक का अनुभव यही बताता है कि संसद सत्र के पहले आयोजित होने वाली सर्वदलीय बैठकों में कहा-बताया कुछ जाता है और लोकसभा एवं राज्यसभा में कुछ और देखने को मिलता है। आमतौर पर यह कुछ और नहीं, बल्कि हल्ले एवं हंगामे के रूप में देखने को मिलता है। संसद के भीतर अथवा बाहर किसी विषय पर चर्चा में महत्वपूर्ण यह होता है कि उस पर किस इरादे से पक्ष-विपक्ष के नेता अपनी बात कह रहे हैं। कई बार ये इरादे वैसे नहीं होते, जैसे प्रचारित किए जाते हैं। कभी सत्तापक्ष विपक्ष के विषयों को अनावश्यक समझता है और कभी विपक्षी दल विरोध के लिए विरोध की राजनीति करते दिखते हैं।

अब तो ऐसा अधिक दिखता है कि कई विपक्षी नेताओं का एकमात्र उद्देश्य हंगामा करना होता है। सत्ता पक्ष भी उनके उद्देश्य को पूरा करना बेहतर समझता है। इसके नतीजे में किसी भी मुद्दे पर सकारात्मक एवं सार्थक चर्चा नहीं हो पाती। स्थिति यह है कि राष्ट्रीय महत्व के कई विधेयकों पर भी ढंग से चर्चा नहीं होती। वे या तो लंबित पड़े रहते हैं अथवा हंगामे के बीच जैसे-तैसे पास हो जाते हैं। जब ऐसा होता है तब विपक्ष यह शोर मचाता है कि बहुमत के बल पर विपक्ष की आवाज को दबा दिया गया और अब तो ऐसा अक्सर सुनने को मिलता है कि देश में लोकतंत्र के नाम पर एक तरह की तानाशाही चल रही है। यह बात वह कांग्रेस खासतौर पर कहती है, जो सचमुच तानाशाही के रास्ते पर चली थी। तब उसकी तानाशाही का विरोध करने वाले कई दल आज उसके साथ खड़े हैं और उसकी ही भाषा बोल रहे हैं। कई बार तो विपक्षी दल ऐसी भाषा बोल जाते हैं जो पाकिस्तान, चीन को रास आती है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पहलगाम आतंकी हमले और आपरेशन सिंदूर पर विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से ऐसे कई बयान दिए भी गए थे। यदि संसद में सकारात्मक चर्चा नहीं होगी और कानूनों के निर्माण का मूल कार्य ढंग से नहीं किया जाएगा तो फिर कहां किया जाएगा? यह एक तथ्य है कि संसद में अब सार्थक चर्चा का अभाव ही अधिक देखने को मिलता है। यह न तो राजनीति के लिए शुभ है, न लोकतंत्र के लिए और न ही आम जनता के लिए।

दवा की गुणवत्ता

बीमारी के उपचार के लिए दवा का सेवन आवश्यक है, लेकिन जब दवा मानकों पर खरी नहीं उतरती है तो उपचार की उम्मीद कैसे की जा सकती है। केंद्रीय दवा नियंत्रक मानक संगठन (सीडीएससीओ) हर महीने देशभर में निर्मित दवाओं के सैंपल लेकर उनकी गुणवत्ता की जांच करता है। जून में लिए गए सैंपल में 188 दवाएं मानकों पर खरी नहीं उतरीं, जिनमें से 58 दवाएं हिमाचल प्रदेश में निर्मित हैं। बद्दी के एक उद्योग में निर्मित 16 दवाओं के सैंपल फेल पाए गए हैं, जबकि गोवा और महाराष्ट्र के उद्योगों में भी छह-छह दवाएं गुणवत्ताहीन पाई गई हैं। हिमाचल प्रदेश दवा उत्पादन में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। सोलन जिले के बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ में कई दवा उद्योग स्थापित हैं। जांच में पाया गया है कि अधिकतर दवाओं में डिस्क्रिप्शन और लेवल की कमी है, कई में धूल के कण पाए गए हैं। दवाओं की गुणवत्ता में कमी के कई और कारण भी सामने आए हैं। दवाएं लोगों के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, इसलिए इनमें किसी भी प्रकार की कमी स्वीकार्य नहीं है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दवाओं की गुणवत्ता की जांच बाजार में भेजने से पहले की जाए। इसके साथ ही, जिन उद्योगों की दवाएं बार-बार खराब पाई जा रही हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े इस गंभीर मुद्दे पर सरकार को अधिक गंभीरता से विचार करना होगा।

> दवाओं के वार-वार मानकों पर खरा न उतरने से लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है

विश्व के लिए खतरनाक होगा टैरिफ का दांव

शिवकांत शर्मा

यदि अमेरिका ने भारत, चीन आदि पर रूसी तेल खरीद को लेकर प्रतिबंध लगाए तो उससे बढ़ने वाली महंगाई के असर से अमेरिका-यूरोप भी अछूते नहीं रह पाएंगे

खातिर गजनवी की मशहूर गजल का मतला है-गो जरा सी बात पर बरसों के याराने गए। पुतिन और ट्रंप के बीच हाल में कुछ ऐसा ही हुआ है। हां, बात केवल इतनी ही नहीं है। 2013 की मिस यूनिवर्स सौंदर्य प्रतिस्पर्धा को लेकर मास्को गए ट्रंप ने रूसी अरबपतियों और राष्ट्रपति पुतिन की खातिरदारी से अभिभूत होकर कहा था कि वे राष्ट्रपति ओबामा से भी अधिक प्रभावशाली हो चुके हैं। पुतिन का रंग उन पर इतना गहरा चढ़ा कि राष्ट्रपति बनने के बाद 2018 के हेलसिंकी शिखर सम्मेलन में उन्होंने अपने खुफिया तंत्र के खिलाफ पुतिन का पक्ष लेते हुए यह मानने से इन्कार कर दिया कि रूस ने अमेरिकी चुनाव में गड़बड़ी कराई थी। पुतिन के साथ अपने खास रिश्ते का दम भरते हुए उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रपति बनने के 24 घंटों के भीतर युद्धविराम करा देंगे। जब वह नहीं हुआ तो उन्होंने रूस के प्रतिबंध हटाने और क्रीमिया को रूस के भाग के रूप में मान्यता देने जैसे प्रलोभन देकर पुतिन को मनाने की कोशिशें कीं। जंग का ठीकरा जेलेंस्की के सिर फोड़ा, उन्हें तानाशाह बताते हुए व्हाइट हाउस में मीडिया के सामने बुरा-भला कहा। उन्होंने यूक्रेन की सैन्य और आर्थिक मदद रोक ली और बिना शर्त बातचीत के लिए राजी किया।

युद्ध विराम के लिए ट्रंप ने पुतिन के साथ छह बार फोन-वार्ताएं कीं, परंतु पुतिन न केवल बात लटकाते रहे, बल्कि हर बातचीत के बाद बड़े-बड़े हमले करते रहे। इस महीने की बातचीत के बाद ट्रंप का पुतिन से मोहभंग हो गया और उन्होंने कहना शुरू किया कि वे उनसे नाखुश हैं। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि वे पुतिन से निराश हैं, पर हताश नहीं। उन्होंने यूक्रेन को नाटो के माध्यम से अधुनातन रक्षा प्रणाली और मिसाइलें देना शुरू करने का एलान किया और पुतिन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वे 50 दिनों के भीतर युद्ध विराम के लिए राजी नहीं हुए तो रूसी माल खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत टैरिफ जैसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। नाटो महासचिव मार्क रूटा ने तो चीन, भारत और ब्राजील को सीधे ही कह दिया कि या तो तीनों मिलकर पुतिन को युद्ध विराम के लिए राजी करें, अन्यथा अमेरिकी प्रतिबंधों के लिए तैयार हो जाएं। यूरोपीय संघ ने रूस पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं और अमेरिकी सीनेट रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने वाले प्रस्ताव की तैयारी कर रही है।

रूस प्रतिदिन लगभग 70 लाख बैरल तेल का निर्यात करता है, जिसका 47 प्रतिशत चीन खरीदता है और 38 प्रतिशत भारत। रूस इस समय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। उसके तेल की बिक्री बंद होने से दुनिया में तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर चीन और भारत पर तो पड़ेगा ही, यूरोप और अमेरिका भी उससे अछूते नहीं रह पाएंगे, क्योंकि तेल की कीमतों में उछाल से महंगाई बढ़ेगी और दुनिया की अर्थव्यवस्था संकट में पड़ जाएगी। इससे रूस का नुकसान तो तब होगा जब चीन, भारत और ब्राजील तेल खरीदना बंद करेंगे। हालांकि तेल की कीमतें बढ़ने से रूस को फायदा होना तुरंत शुरू हो गया है। वैसे भी पुतिन को लगता है कि ट्रंप की धमकी गीदड़भभकी के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए पुतिन ने यूक्रेन पर 700 ड्रोन और दर्जन भर मिसाइलों से बड़ा हमला किया। अमेरिकी चेतावनी के जवाब में रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता जखारोवा ने भी कहा कि अल्टीमेटम, ब्लैकमेल और धमकियां हमें मंजूर नहीं हैं। हम अपनी सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। रूसी शेयर बाजार में भी घबराहट की जगह तेजी दिखाई दी।

ट्रंप का पुतिन से मोहभंग होना तो समझ में आता है, परंतु आर्थिक प्रतिबंधों के जिस हथियार से बाइडन कुछ हासिल नहीं कर पाए तो उसी को दोबारा चलाने का मकसद क्या हो सकता है? सुप्रसिद्ध इतिहासकार युवाल नोआ हरारी के अनुसार ट्रंप किलेबंदी की मानसिकता से काम करते हैं। उनकी नीतियों में किसी न किसी ठोस प्राप्ति का स्वार्थ छिपा रहता है। यूक्रेन की सैनिक मदद के लिए उन्होंने नाटो को माध्यम बनाया, ताकि यूक्रेन को हथियार मिल जाएं और उन्हें नाटो के जरिये उनके दाम। ट्रंप दावा कर चुके हैं कि चीन के साथ सैद्धांतिक रूप से व्यापार सौदा हो चुका है, परंतु उस दावे को तीन हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन सौदे पर मुहर नहीं लग पाई है। उन्होंने भारत के साथ भी सौदा हो जाने का संकेत दिया है। अलबत्ता औपचारिक रूप से कोई घोषणा नहीं हुई है। हो सकता है कि इन्हीं व्यापार सौदों को मनमुताबिक और जल्दी निपटाने के लिए रूसी तेल खरीदने वालों पर टैरिफ लगाने की चेतावनी दी जा रही हो। वरना यह बात पुतिन भी जानते हैं और ट्रंप भी कि शी चिनफिंग भी ट्रंप की धमकी में आकर रूस से तेल लेना बंद नहीं करने वाले। वे टैरिफ जंग में भी नहीं झुके, क्योंकि चीन के पास दुर्लभ खनिजों, चुंबकों और सेमीकंडक्टरों का ब्रह्मास्त्र था। उसके साथ आखिरकार ट्रंप को ही सौदा पटाना पड़ा।

ट्रंप समझ चुके हैं कि सवा लाख से अधिक सैनिकों और अर्थव्यवस्था की बलि चढ़ा चुके पुतिन को बातों और धमकियों से पीछे हटाना संभव नहीं है। न ही वे इस अंतहीन लड़ाई में यूक्रेन के लिए अमेरिकी खजाना खोलने को तैयार हैं। इसलिए उन्होंने नाटो के जरिये हथियार बेचने का रास्ता चुना है, ताकि यूक्रेन अपनी रक्षा करते हुए रूसी सेना और रक्षा तंत्र को इतनी चोट पहुंचाता रहे कि एक दिन पुतिन थककर बातचीत के लिए विवश हो जाएं। दूसरी ओर, पुतिन का लक्ष्य यूक्रेन की सैनिक और खुफिया शक्ति और रक्षा उद्योग को तबाह कर उसे ऐसे नाकाम राज्य में बदल देना है जहां रूसी हमलों के भय से कोई निवेश न करे और वह रूस पर आश्रित होकर रह जाए। इस खेल में भारत को कूटनीतिक निपुणता के साथ चीन के साथ मिलकर चलना होगा, क्योंकि ट्रंप उसी की सुनते हैं जिसके पास पलटवार की क्षमता होती है। चीन के पास पलटवार के लिए दुर्लभ खनिज हैं और रूस के पास तेल और अनाज। ऐसे में भारत को अपनी कूटनीति पर दांव लगाना होगा।

(लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं)
response@jagran.com

अवधेश राजपूत

शिक्षा संस्थानों में संभावनाओं की मौत

प्रमोद भार्गव

शिक्षा परिसरों में छात्रों की आत्महत्याएं यही संकेत करती हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली में कुछ गंभीर समस्याएं हैं

देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में हाल के दिनों में कई चिंताजनक घटनाएं सामने आई हैं। पहले जहां छात्रों द्वारा आत्महत्या के मामले चर्चा में थे, वहीं अब छात्राओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। गत दिनों ओडिशा के बालासोर में एक छात्रा ने यौन उत्पीड़न की शिकायत के बाद आत्मदाह कर लिया। बेंगलुरु में दो शिक्षकों ने एक छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। आइआइएम, कोलकाता में भी एक मनोविज्ञानी महिला परामर्शदाता के साथ इसी तरह की घटना हुई। नोएडा के शारदा विश्वविद्यालय में दंत चिकित्सा की एक छात्रा ने छात्रावास में आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले उसने एक पत्र लिखा, जिसमें विश्वविद्यालय के डीन और कुछ प्राध्यापकों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। इस मामले में पुलिस ने दो प्राध्यापकों को गिरफ्तार किया है और कुछ को निलंबित किया गया है। ये घटनाएं उच्च शिक्षा परिदृश्य को शर्मसार करने वाली हैं।

यह चिंता की बात है कि भारत सरकार देश में विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस खोलने की अनुमति दे रही है। यदि हम विदेशी शिक्षा पद्धति और संस्थानों को प्राथमिकता देंगे, तो हमारे छात्र और अभिभावक अपने देश के संस्थानों को कमतर मानने लगेंगे। होना तो यह चाहिए कि सरकार देश के शिक्षण संस्थानों में ही बुनियादी सुधार करती। वैसे भी विदेश में पढ़ाई के बढ़ते चलन के चलते प्रतिभाओं के पलायन का बड़ा संकट खड़ा हो रहा है। ऊपर से शिक्षकों द्वारा दुष्कर्म और प्रताड़ना के बढ़ते मामले इस समस्या को और गंभीर ही बनाएंगे। ये घटनाएं बताती हैं कि हमारे कुछ शिक्षक छात्रों में उम्मीदों की उड़ान पैदा करने के बजाय निराशा, कुंठा और अवसाद पैदा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ऐसे शिक्षकों पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है, अन्यथा शिक्षण संस्थानों में ऐसी शर्मनाक घटनाएं नहीं होतीं। शिक्षा के जरिये विद्यार्थी उपलब्धि के शिखर पर पहुंचने की आकांक्षा रखते हैं। यदि शिक्षण संस्थानों में ही यह संभावना दम तोड़ने लगे तो यह शिक्षा का अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण पहलू माना जाएगा।

ज्ञान की महत्ता ने इस भ्रम को तोड़ दिया है कि शिक्षा केवल कुछ वर्गों का अधिकार है। भारतीय मनीषियों ने हजारों साल पहले ज्ञान की इस शक्ति को पहचाना था। 21वीं सदी को ज्ञान की सदी कहा गया है। आज दुनिया शिक्षा और अनुसंधान के माध्यम से एक ऐसे तकनीकी संसार का निर्माण कर रही है, जिसमें सुविधाएं हर किसी की मुट्ठी में हैं। अब तो मनुष्य अंतरिक्ष में बसने-बसाने की संभावनाएं तलाश रहा है। शिक्षा के माध्यम से गरीब और वंचित वर्ग के लिए सरकारी और निजी क्षेत्रों में अनेक अवसर उपलब्ध हुए हैं। ऐसे में जब शिक्षण संस्थानों में प्रताड़ना, दुष्कर्म और आत्महत्या के मामले सामने आ रहे हैं, तो सरकारों के लिए यह एक गंभीर विषय होना चाहिए। शिक्षा परिसरों में छात्रों की आत्महत्या की घटनाएं इसका संकेत करती हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली में कुछ गंभीर समस्याएं हैं। यदि उत्पीड़न और आत्महत्या का यह सिलसिला जारी रहा, तो देश के भविष्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इन मौतों का कारण अध्ययन और अध्यापन से जुड़ी समस्याएं हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के नेता इन मौतों को केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, जिससे समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। यदि आने वाले समय में आत्महत्या के मामलों को शिक्षा की व्यापक समझ के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा गया, तो इन मौतों पर विराम लगाना मुश्किल होगा।

देखा जाए तो देश में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च और तकनीकी शिक्षा तक शिक्षण पद्धति में भ्रम और विरोधाभास की स्थिति बनी हुई है। शिक्षा के निजीकरण, अंग्रेजीकरण और विदेशीकरण पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। वैसे इसमें सुधार के लिए तमाम आयोगों का गठन किया गया, उनकी रिपोर्ट भी आईं, लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ। इसके चलते शिक्षा प्रणाली में आदर्श और समावेशी शिक्षा के बुनियादी तत्वों को शामिल करने में हम पिछड़ गए हैं। इससे शिक्षा में निजीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। यह हमारी शिक्षा को केवल अंग्रेजीकरण की ओर ले जा रहा है, जिससे शिक्षा का उद्देश्य केवल पैसा कमाना रह गया है। कोटा के कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों द्वारा की जा रही आत्महत्या के मामलों की जांच से पता चलता है कि अभिभावक अपने बच्चों पर अपनी इच्छाएं थोपने लगे हुए हैं। केरल के एक छात्र ने आत्महत्या से पहले लिखा था, 'सॉरी मम्मी-पापा, आपने मुझे जीवन दिया, लेकिन मैंने इसकी कद्र नहीं की।' यह एक दुखद बयान है, जो उस किशोर का है, जो आइआइटी की तैयारी कर रहा था। ये संस्थान प्रतिभाओं को निखारने का दावा करते हैं, लेकिन युवाओं को महान बनाने का सपना दिखाने वाला यह उद्योग कितना खोखला है, यह बढ़ती आत्महत्याओं से स्पष्ट होता है। शिक्षा का यह कोचिंग उद्योग अब देशव्यापी समस्या बन चुका है और इसकी जकड़न में अन्य प्रदेशों के बड़े नगर भी आ रहे हैं।

इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की महती आवश्यकता है। हमें अपने संस्थानों में बुनियादी बदलाव लाने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। यदि हम इस दिशा में आगे नहीं बढ़ते, तो शिक्षा का यह संकट और भी गहरा सकता है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)
response@jagran.com

न्याय की गुहार लगाते मृतक छात्रा के परिजन। फाइल

ऊर्जा

सहयोग करें, उपकार नहीं

संसार परमात्मा की वैविध्य से परिपूर्ण रचना है। कोई शक्तिशाली, कोई निर्बल है। कोई धनवान, कोई निर्धन है। कोई ज्ञानवान है, कोई अज्ञानी है। अधिकांश धर्मग्रंथ इसे अपने कर्मों का फल मानते हैं। यह भी सत्य है कि परमात्मा दयालु है। सभी उसकी संतान हैं। अपनी संतान को कोई कैसे दुख में देख सकता है। वह विभिन्नता कैसे रच सकता है। यह भी ध्रुव सत्य है कि परमात्मा न्यायप्रिय है। अपने न्याय के अंतर्गत ही उसने किसी को राजा, किसी को रंक बनाया है। परमात्मा ने इस सृष्टि में अद्भुत समन्वय स्थापित किया है, जिसमें उसका न्याय और दया, दोनों एक साथ प्रकट होते हैं। यदि उसने निर्बल, निर्धन, अज्ञानी रचे तो उनके दुख दूर करने के लिए सबल, धनी और ज्ञानी के मन में करुणा का भाव भी उत्पन्न किया है। अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात अतिरिक्त जो भी सामर्थ्यवान मनुष्य के पास बचता है, वह उसे अभावग्रस्त में बांट देता है। सामर्थ्यवान को सामर्थ्य परमात्मा ने प्रदान की है। सामर्थ्यवान के माध्यम से वह उस सामर्थ्य का अंश निरीह को स्थानांतरित करता है।

दया और सहयोग की भावना का व्यवहार में बदलना मनुष्य का धर्म है और इसमें परमात्मा की व्यवस्था सुचारु बनी रहती है। मनुष्य कुछ देने की स्थिति में है तो देने में संकोच न करे। मनुष्य आगे देता जाएगा तो परमात्मा उसका प्रवाह बनाए रखेगा। जैसे कि नदी का जल आगे बढ़ता रहता है तो नया जल उसका स्थान लेता रहता है।

मनुष्य का किसी को करुणा, दया वश कुछ देना उसका उपकार नहीं, परमात्मा की व्यवस्था का अंगीकरण है। जब परहित को उपकार मान लिया जाता है तो वहां चाहे-अनचाहे अहंकार उत्पन्न हो जाता है। अहंकार स्वयं को दाता मानने का भ्रम पैदा कर देता है। परमात्मा को किसी भी तरह का अहंकार स्वीकार नहीं है।

डा. सत्येंद्र पाल सिंह

आपकी गतिविधियां भांप रहे बच्चे

डा. महेश परिमल

> अपने बच्चों को सही संस्कार दें और उन्हें यह समझाएं कि गलत तरीके से प्राप्त की गई वस्तुएं हमारे नैतिक मूल्यों का नाश करती हैं

हाल में बुकिंगडाटकाम और यूगोव द्वारा किए गए एक सर्वे में भारतीय ट्रैवलर्स की कुछ बुरी आदतें सामने आईं। इस सर्वे में शामिल 44 प्रतिशत भारतीयों ने स्वीकार किया कि वे होटल में मिलने वाले शैंपू, साबुन और ब्रश जैसी चीजें अपने घर ले आते हैं। कुछ लोग ट्रेन यात्रा के दौरान अपने सामान के साथ कुछ और सामान भी ले आते हैं, जैसे चादर, कंबल और तकिया। हाल में एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक महिला चेक-आउट के दौरान अपने सामान में होटल की चीजें जैसे टावेल, साबुन, चाय के प्याले और गिलास लेकर जा रही थी। उस समय लोग उस पर हंस रहे थे। यह केवल महिला की आदत नहीं है, बल्कि कई पुरुष भी ऐसा करते हैं, लेकिन यह आदत बहुत खराब है। आपका यह मानना कि बड़े होटल का किराया देने के बाद उन चीजों पर आपका हक बनता है, गलत है। यदि होटल का किराया आपके बजट से ज्यादा है, तो यह आपकी गलती है कि आपने उस होटल का चयन क्यों किया।

संभव है कि आपने कई ऐसी चीजों को घर में सजाकर रखी हो। संभव है आपकी देखादेखी भविष्य में आपकी संतानें भी ऐसा करना सीख जाएं। दरअसल आपने अपने घर में ढेर सारे चोरी की वस्तुएं सजाकर अपने बच्चों में कुसंस्कार का बीजारोपण कर दिया है। इस क्रम में हो सकता है कि आपकी संतानें किसी अपराध में फंस जाएं, तो आपकी संपत्ति उनको छुड़ाने पर खर्च हो जाएगी। पुलिस से लेकर वकील की फीस में आपकी दौलत स्वाहा हो जाएगी। संतानें कुछ दिनों तक पुलिस हिरासत या जेल की हवा भी खा लेंगी। समाज में आपकी इज्जत भी नहीं रहेगी। सोचिए, उस वक्त क्या होगा जब जमानत के लिए आपके अपनों में से कोई भी आगे नहीं आएगा? आप इज्जत बचाने के लिए शहर बदल सकते हैं, लेकिन संस्कार नहीं बदल सकते। ये संस्कार आपकी संतान में अनजाने में नहीं आए। आपकी हरकतों पर उनकी नजर थी। जब वे छोटे थे, तब समझ नहीं पाए, लेकिन बड़े होकर वे समझने लगे कि आपने गलत किया।

यह न भूलें कि आपकी हर हरकत पर कई नजरें टिकी हैं। आजकल सीसीटीवी का जमाना है। हमारी एक हरकत हमारी और हमारे बच्चों की जिंदगी से खेल सकती है। इसलिए इस तरह से चीजें होटलों या ट्रेन से न लाएं। ये वस्तुएं आपकी बेईमानी का जीता-जागता स्वरूप हैं। यादें वही होती हैं, जो हमें सुकून देती हैं। पराक्रम वही अच्छा है, जिसे सुनकर संतानें गर्व करें। यह आवश्यक है कि हम अपने बच्चों को सही संस्कार दें और उन्हें यह समझाएं कि गलत तरीके से प्राप्त की गई वस्तुएं केवल पद-प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि हमारे नैतिक मूल्यों का भी नाश करती हैं। हमें अपने कार्यों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे हमारी हरकतों से सीखते हैं।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

न्यायपूर्ण जांच की आवश्यकता

'न्यायिक जांच की मांग करता विमान हादसा' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में संजय लाजार ने लिखा है कि चूंकि एअर इंडिया विमान हादसे की जांच सही दिशा में बढ़ती नहीं दिख रही, इसलिए हमें आवाज उठानी ही होगी। लेखक की विमान हादसे की न्यायिक जांच की मांग अत्यंत उचित और आवश्यक प्रतीत होती है। लगता है कि अमेरिकी कंपनी बोइंग संभवतः अपने व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए सही जांच से लोगों का ध्यान भटका रही है, जिसने दुर्घटनाग्रस्त ड्रीमलाइनर 787 का निर्माण किया था। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और हास्यास्पद है कि दो अत्यंत अनुभवी पायलटों को आत्मघाती हमलावर की तरह प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। इस गंभीर मामले में पायलटों की कार्यक्षमता और प्रतिष्ठा को बिना ठोस साक्ष्यों के कठघरे में खड़ा किया जा रहा है। इस दुर्घटना की निष्पक्षता और गहराई से जांच तभी संभव होगी, जब जांच समिति में अंतरराष्ट्रीय अनुभव रखने वाले वरिष्ठ पायलटों और तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि समिति में एक सेवानिवृत्त प्रतिष्ठित न्यायाधीश को भी सम्मिलित किया जाए, जिससे न्याय और पारदर्शिता की भावना बनी रहे। समता और न्याय का यह सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति को बिना सुने उस पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस दुर्घटना में दोनों पायलटों सहित 260 निर्दोष लोगों की जान गई है। भविष्य में भारत में बन रहे हवाई अड्डों और खरीदे जाने वाले विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि इस हादसे की विस्तृत, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच हो। लेखक द्वारा उठाया गया मुद्दा न केवल तर्कसंगत है, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा और न्याय की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अधिवक्ता अमित कुमार, गाजियाबाद

अमेरिका की धीमी कार्रवाई

अमेरिका ने पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तोयबा के मुखौटा संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) को वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। अमेरिका का कहना है कि लश्कर के इस प्राक्सी फ्रंट ने पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 26 नागरिकों की हत्या हुई थी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि यह प्रतिबंध पहलगाम मामले में न्याय के प्रति राष्ट्रपति ट्रंप की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत ने भी अमेरिका के इस निर्णय का स्वागत किया है, लेकिन यह सवाल उठता है कि जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, तब अमेरिकी प्रशासन को सब कुछ पता था। यदि अमेरिका चाहता, तो वह इस मामले में तुरंत कठोर कार्रवाई कर सकता था। पहलगाम हमला मुंबई हमले के बाद का सबसे घातक और क्रूरतम हमला था। इस संदर्भ में, यह कहना उचित होगा कि अमेरिका भले ही आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की बात करता हो, लेकिन पाकिस्तान पर उसका हमेशा वरदहस्त बना रहता है। जब तक अमेरिका पाकिस्तान के प्रति थोड़ी भी सहानुभूति रखता है, तब तक यह स्थिति बनी रहेगी।

मनमोहन राजावत "राज", शाजापुर

स्वास्थ्य बीमा में दिनचर्या छूट

भारत में स्वास्थ्य बीमा की शुरुआत 1948 में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के माध्यम से हुई थी, जिसमें संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान की गई थी। 1954 में केंद्र सरकार ने सीजीएचएस के माध्यम से केंद्रीय कर्मियों के चिकित्सा व्ययों का भुगतान करना शुरू किया। सामान्य बीमा निगम द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की चार कंपनियों के माध्यम से आम जनता के लिए 1986 में मेडिक्लेम पालिसियों का विक्रय प्रारंभ हुआ। हालांकि उपचार की नवीन तकनीक और चिकित्सा सेवा मुद्रास्फीति की उच्च दर ने स्वास्थ्य बीमा को महंगा कर दिया है। इस दिशा में सरकार को कुछ राहत प्रदान करनी चाहिए। निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं द्वारा अच्छी दिनचर्या वाले, रोज पैदल चलने वालों को प्रीमियम में रियायत देने की घोषणा सराहनीय है, जिसका अनुसरण सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को भी करना चाहिए।

ओपी चौधरी, रतलाम

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

14.25 अरब डालर का निर्यात किया गया भारत द्वारा चीन को वर्ष 2024-25 के दौरान, जबकि इसी अवधि में चीन से किए गए आयात का मूल्य 113.46 अरब डालर था।

आजकल

वैश्विक गतिशीलता के दौर में नई दृष्टि

डा. नवीन कुमार मिश्र
भू-राजनीतिक मामलों के जानकार

वैश्विक बदलावों और महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा ने स्पष्ट कर दिया है कि रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं के साथ विश्व की राजनीति तीन महाशक्तियों रूस, चीन और अमेरिका की भू-राजनीतिक गतिशीलता से प्रभावित होती है। चीन और रूस वैश्विक व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक-ध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था बनाए रखने के लिए 'टैरिफ वार' छेड़ रखा है। भू-राजनीतिक तनाव के कारण आज विश्व में आर्थिक विखंडन की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में भारत को एक नए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना होगा

पिछले वर्ष आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत रूस और चीन के राष्ट्राध्यक्ष। फाइल

नई विश्व व्यवस्था के दौर में अनेक पुराने समीकरण ध्वस्त होते और नए बनते हुए दिख रहे हैं। स्वयं के हितों को सुरक्षित करके वैश्विक महाशक्तियां निष्पक्षता और न्याय की वकालत कर रही हैं। कुछ देश शक्ति संतुलन के लिए बहुध्रुवीय विश्व का सपना संजोए अपने गुटों को मजबूत करने में लगे हुए हैं। वहीं अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के प्रभाव और उनके नियम कमजोर पड़ गए हैं। इन परिस्थितियों में भारत किसी पक्ष में न होकर ध्रुवीकरण से अलग शांति और स्थिरता का समर्थक है, जो पूर्व-पश्चिम के बीच संतुलन का एक सेतु बनने की पर्याप्त क्षमता रखता है। भारत ने हमेशा जी-7 और ब्रिक्स दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है।

भारत क्वाड, ब्रिक्स और एससीओ का सदस्य है, और जी-7 में भी आमंत्रण पर शामिल होता है। भारत अपने हितों को सुरक्षित रखने के साथ संप्रभु-शक्ति के रूप में एक जिम्मेदार राष्ट्र है। परंतु पश्चिम का भारत को देखने का नजरिया अत्यंत ही संकीर्ण है। पाकिस्तान के साथ बीते दिनों हुए सैन्य संघर्ष के समय अमेरिका और यूरोपीय संघ के रुख से स्पष्ट हो गया है कि पश्चिमी देश आज भी भारत को अपनी धुरी का हिस्सा नहीं मानते हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध में पश्चिमी देश भारत को रूस का मददगार समझते हैं, जबकि भारत ने अपने नागरिकों को सामाजिक-आर्थिक संकट से बचाने के लिए रूस से तेल आयात किया था।

नाटो महासचिव मार्क रूट की प्रतिबंधों की धमकी पर हाल ही में भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत के लिए ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। वह पश्चिम के राजनीतिक फायदे के लिए अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। दबाव की रणनीति के माध्यम से पश्चिमी देश वैश्विक व्यवस्था पर फिर से नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के कारण दबाव की स्थिति से आगे निकल चुका है। आज की दुनिया 1990-2000 के दौर की एक-ध्रुवीय और पश्चिम-केंद्रित दुनिया नहीं है। भारत आज न केवल दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बल्कि उभरती बहु-ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में एक प्रमुख ध्रुव है, जो नाटो के भू-राजनीतिक मंच का अनुगामी नहीं है। हालांकि वर्ष 2014 में क्रीमिया पर कब्जे और 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों ने रूस को चीन के और निकट ला दिया। शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए भारत को रूस के साथ जुड़ा रहना पश्चिम के हित में भी है। रूस के साथ भारत के संबंधों का एक यूरेशियाई आयाम भी है।

आज वैश्विक व्यवस्था में तीव्र गति से परिवर्तन व समायोजन हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद पुराने सभी वैश्विक समीकरण बदल रहे है। चूंकि भारत-चीन के बीच भू-राजनीतिक संघर्षों का एक लंबा इतिहास रहा है। वर्ष 1962 के युद्ध से लेकर वर्ष 2020 में गलवन संघर्ष तक, चीन भारतीय संप्रभुता के लिए एक वास्तविक और निरंतर खतरा बना हुआ है। इसलिए जैसे-जैसे चीन के साथ तनाव गहराता गया, अमेरिका के साथ भारत की साझेदारी में तेजी आने लगी। चीन के साथ चल रहे सीमा तनाव और क्वाड के माध्यम से अमेरिका के साथ भारत की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी, एक एकीकृत शक्ति के रूप में इसकी भूमिका को जटिल बनाती है। परंतु इस बीच पाकिस्तान के प्रति ट्रंप का रवैया भारत की बेचैनी बढ़ाने वाला है। इसके साथ ही चीन और पाकिस्तान के बीच गहराता रणनीतिक संबंध ट्रंप की पाकिस्तान नीति से भी ज्यादा खतरा पैदा करने वाला है।

वहीं दूसरी ओर दक्षिण एशिया में 'सार्क' की निष्क्रियता और चीन के नेतृत्व में एक नए क्षेत्रीय समूह की आहट इस क्षेत्र की भू-राजनीति को बदल सकती है, जबकि चीन ने पहले ही अपना स्वयं का हिंद महासागर मंच बना लिया है। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता और पाकिस्तानी सेना के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का भारत के विरुद्ध आक्रामक रवैया तथा चीन की विस्तारवादी नीति के बीच बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता का लाभ लेकर उसे भारत-विरोधी धुरी में शामिल कर दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय समीकरणों को पूरी तरह से बदल दिया है।

नए रणनीतिक मंच को मजबूती : रूस के साथ संबंधों के कारण भारत को दुश्मन करार देना, वैश्विक मंच पर पश्चिम की भूमिका को नजरअंदाज करने जैसा है। शीत युद्ध के दौरान पश्चिम के साथ पाकिस्तान की निकटता भारत को रूस के करीब ले गया। परंतु बाद के दशकों से भारत ने बहुध्रुवीय दृष्टिकोण बनाए रखा है और ब्रिक्स, एससीओ एवं क्वाड जैसे संस्थानों के माध्यम से रूस, अमेरिका और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के साथ अपनी साझेदारी को संतुलित किया है। ब्रिक्स में भारत की सदस्यता इसे पश्चिम विरोधी नहीं बनाती है, परंतु डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स के अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों को अमेरिका-विरोधी के रूप में प्रस्तुत किया है। वर्तमान में वैश्विक बहुध्रुवीयता का उदय एवं अमेरिका, चीन व रूस जैसी महाशक्तियों की भू-राजनीतिक महत्वकांक्षा और ट्रंप की व्यापार संबंधी कूटनीति के समक्ष भारत को अपनी विदेश नीति को नए दृष्टिकोण से परिभाषित करना होगा। भारत ने इस दिशा में प्रयास करने भी शुरू कर दिए हैं। इसका परिणाम है कि भारत ग्लोबल साउथ के नेतृत्व-कर्ता के रूप में उभर कर सामने आया। ऐसे में जटिल सौदेबाजी और कमजोर होते गठबंधन की स्थिति में भारत को नए रणनीतिक मंच को बनाने व उसे मजबूत कर नई वैश्विक व्यवस्था में रणनीतिक स्वायत्तता के साथ बहुध्रुवीय एशिया के विकास को आगे बढ़ाने की जरूरत है।

रिश्तों में सुधार के साथ चीन के प्रति सतर्कता

विशाल कुमार सिंह

वर्तमान सदी की वैश्विक राजनीति में चीन एक ऐसी शक्ति बनकर उभरा है, जिसकी आर्थिक क्षमता, सैन्य विस्तार और रणनीतिक महत्वाकांक्षा ने समूचे एशिया और विशेषकर भारत के लिए एक सतत चुनौती खड़ी कर दी है। भारत और चीन दो प्राचीन सभ्यताएं, दो उभरती महाशक्तियां और दो परमाणु संपन्न पड़ोसी देश हैं। लेकिन इन संबंधों की जटिलता केवल भूगोल की सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें इतिहास, रणनीति, व्यापार और वैचारिक भिन्नताओं की भी गूंज सुनाई देती है। ऐसे में भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह चीन के साथ संबंधों में सहयोग की संभावनाओं को जिंदा रखते हुए अत्यधिक सतर्कता और रणनीतिक सजगता के साथ आगे बढ़े।

भारत-चीन संबंधों का इतिहास विश्वास और विश्वासघात की मिश्रित विरासत से भरा है। हाल के वर्षों में भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंधों में प्रगति के बावजूद सीमा पर सैन्य तनाव और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा लगातार बनी रही है। गलवन घाटी में हुए संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था। हालांकि उसके बाद उच्च-स्तरीय संवादों का सिलसिला शुरू हुआ और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच ब्रिक्स सम्मेलन में वार्ता भी हुई, परंतु यह सतही सुधार मात्र है। सीमा पर अब भी विश्वास का संकट है और चीन की रणनीति अस्पष्ट एवं बहुध्रुवीय बनी हुई है। कैलास मानसरोवर यात्रा का पुनः प्रारंभ, सीमा पर गश्त की अनुमति और व्यापार में आंशिक सुधार- ये सब भारत-चीन संबंधों के सकारात्मक संकेत हैं, परंतु इनकी बुनियाद बहुत नाजुक है। जब तक सीमा विवाद, अरुणाचल प्रदेश पर दावा, ब्रह्मपुत्र जल विवाद और पाकिस्तान के साथ चीन की निकटता जैसे मूल मुद्दों पर चीन स्पष्ट रुख नहीं अपनाता, तब तक संबंधों में स्थायी विश्वास नहीं बन सकता।

चीन के साथ भारत का व्यापार असंतुलित रहा है। भारत का चीन से आयात कहीं अधिक है, जबकि निर्यात सीमित। इससे देश की रणनीतिक आपूर्ति श्रृंखलाएं (सप्लाई चेन) चीन पर निर्भर रहती हैं, विशेषकर फार्मा, इलेक्ट्रानिक्स और भारी मशीनरी में। भारत ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस निर्भरता को कम करने की दिशा में कदम उठाए हैं, परंतु जब तक यह निर्भरता पूरी तरह खत्म नहीं होती, तब तक चीन के साथ आर्थिक संबंधों में भी सतर्कता आवश्यक है। चीन का डिजिटल स्पेस में हस्तक्षेप भी भारत के लिए खतरे की घंटी है। कई मोबाइल एप्स पर प्रतिबंध भारत की साइबर सुरक्षा नीति का हिस्सा था, जिसने चीन को यह संदेश दिया कि भारत इस ओर जागरूक हो चुका है।

चीन की विस्तारवादी नीति केवल भारत तक सीमित नहीं है। दक्षिण चीन सागर में उसकी गतिविधियां, ताइवान पर उसकी आक्रामक नीति, श्रीलंका, नेपाल और अफ्रीकी देशों में उसकी 'डेट ट्रैप' रणनीति, ये सभी संकेत देते हैं कि चीन वैश्विक सत्ता संतुलन को अपने पक्ष में झुकाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत को जापान, आस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप के साथ रणनीतिक गठजोड़ मजबूत करने होंगे। क्वाड और इंडो-पैसिफिक साझेदारियों में भारत की भागीदारी इसी दिशा में सराहनीय प्रयास हैं। भारत को यह समझना होगा कि चीन को केवल सैन्य शक्ति से नहीं, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता, तकनीकी स्वावलंबन और कूटनीतिक साझेदारियों के जरिए संतुलित किया जा सकता है।

भारत-चीन के संबंधों में संवाद और सहयोग की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता, किंतु यह भ्रम भी नहीं पालना चाहिए कि चीन भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार है। भारत को हर कदम पर यह तय करना होगा कि वह चीन की चालों को समझे, उसका प्रतिकार करे और संबंधों में मर्यादित दूरी बनाए रखे। कुल मिलाकर चीन के प्रति संबंधों में सुधार की राह पर आगे बढ़ते हुए निरंतर सतर्क भी रहना होगा।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

खरी-खरी

राजपंथी और नाराजपंथी

विनोद कुमार विक्की

मार्केट में इन दिनों साहित्यकारों की राजपंथी एवं नाराजपंथी प्रजातियां बहुतायत में उपलब्ध हैं। राजपंथी साहित्यकार श्रेणी में दिन-रात, सुबह-शाम हर मौसम, हर प्रहर सरकारी नीतियों का जय घोष करने एवं वर्तमान सरकार में घोर आस्था रखने वाले मूर्धन्य साहित्यकार आते हैं। इंटरनेट मीडिया पर सरकारी पोस्ट को शेयर करके सरकार का यशोगान ही इनके लेखन का मकसद और ध्येय होता है। सरकार एवं सभी प्रकार की सरकारी नीतियों का महिमा मंडन ही इनके साहित्यिक मोक्ष का आधार होता है।

दूसरी कैटगरी वाले नाराजपंथी वर्ग के साहित्यकार मां के गर्भ से ही यह तय कर लेते हैं कि सरकार की हर नीति में मीन-मेख निकाल कर सरकार पक्ष को कोसना है। इनकी कविताओं एवं व्यंग्य में शब्दभेदी क्षमता हो न हो, लेकिन विध्वंसक लक्ष्य पर सरकार एवं सत्ता पक्ष ही होता है। साहित्यिक लेखन से फेसबुकिया पोस्ट तक सरकार एवं उनकी नीतियों पर फुंफकारना ही इनकी साहित्यधर्मिता होती है।

वैसे नाराजपंथी श्रेणी में साम्यवाद का चोला धारण किए कुछ रंग साहित्यकार भी होते हैं, जो पक्षपाती और सामाजिक समरसता के लिए आत्मघाती होते हैं। ।

हालांकि इंटरनेट मीडिया पर उप प्रजाति के रूप में यमराजपंथी साहित्यकारों की पैदावार भी व्यापक पैमाने पर हो रही है। मां सरस्वती के ऐसे पुत्रों का साहित्य जगत में सृजित होने एवं इनके द्वारा सृजित किए गए क्षणभंगुर साहित्य का कोई साहित्यिक अथवा सामाजिक सरोकार नहीं होता। ऐसे कलमकार रोज लिखते और छपते हैं, लेकिन क्या लिखते हैं और कैसे छपते हैं? यह साहित्य का ऐसा यक्ष प्रश्न है जिसका उत्तर यमराजपंथी समुदाय के पूर्वजों एवं नचिकेता के पास भी नहीं है।

यमराज पंथी की तरह ही मनराजपंथी उप श्रेणी के लेखकों की रचनाओं का देश और दुनियादारी से कोई लेना-देना नहीं होता। मनमौजी प्रवृत्ति वाले मनराजपंथी लेखक के लेखन का विषय भले ही तात्कालिक होता है, लेकिन इनके लेखन का उद्देश्य छपासी होता है।

X पोस्ट

जस्टिस यशवंत वर्मा कह रहे है कि उनके आवासीय परिसर में पाए गए नोट उनके नहीं है। हालांकि ये नोट उनके बंगले तक पहुंचे कैसे, यह तो उनको ही बताना होगा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत यह साबित करने का दारोमदार तो उनके ऊपर ही है। आरके विज@ipsvijrk

आइएसआइ भारत में छांगुर जैसे लोगों को पैसा दे रही है कि वे हिंदू महिलाओं को बरगलाकर उनकी शादी अपने एजेंटों से कराए। लव जिहाद असल में एक घरेलू समस्या नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बनता दिख रहा है। पाकिस्तान और भारत में उसके पिट्ठू इसे पुरजोर तरीके से आगे बढ़ा रहे है।
मोनिका वर्मा@TrulyMonica

ट्रंप द्वारा लगातार धौंस दिखाने की अमेरिका को देर-सबेर कीमत चुकानी ही होगी। दूसरे देश इस साम्राज्यवादी रवैये से सबक लेते हुए अपने बचाव के उपाय सोचेंगे। भले ही हाल-फिलहाल अमेरिका को चुनौती न मिले, लेकिन तमाम देश अमेरिका पर निर्भरता घटाते हुए दूसरे विकल्प तलाशना शुरू करेंगे।
कंवल सिब्बल@KanwalSibal

उत्तर प्रदेश डायरी

आसमां नापकर उतरा अपना चांद

भारतीय वसंत कुमार
वरिष्ठ समाचार संपादक, उत्तर प्रदेश

अंतरिक्ष से लौटने के बाद कुछ इस तरह भावुक अंदाज में अपने परिवार से मिले शुभांशु शुक्ला। फाइल

लखनऊ के अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में अंतरिक्ष मिशन से वापसी के बाद जब अपने पुत्र कियाश और पत्नी कामना से मिले तो बहुत मार्मिक टिप्पणी लिखी- 'हम अक्सर जिंदगी की भागदौड़ में इतना उलझ जाते हैं कि अपने करीबियों की अहमियत भूल जाते हैं। आज ही किसी अपने को गले लगाइए और कहिए कि आप उनसे प्यार करते हैं। इंसानी अंतरिक्ष मिशन जादुई होते हैं, लेकिन उन्हें जादुई इंसान बनाते हैं।' खैर, लखनऊ ने शुभांशु को गले लगाया और सिर-माथे पर बैठाया भी। हर्षातिरेक में शहर डूबा रहा, तब भी जब एक्सिओम-4 मिशन पर शुभांशु जा रहे थे और अब भी जब वापस आए। केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा को पूरे देश के लिए गर्व, गौरव और खुशी का क्षण बताया। इस यात्रा ने भारत की असीम आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व तो किया ही, लखनऊ और यूपी को सम्मान का ऊंचा आसन भी दिया। यहां की ही गिट्टी-मिट्टी में पले-बढ़े शुभ ने लखनऊ के 'अंक' को मानव उपयोग के अपने शोध के साथ उपलब्धियों से भर दिया।

उत्तर प्रदेश के हिस्से में सफलता, सिद्धि, प्राप्ति, करतब और कारनामे के कई अध्याय हाल में जुड़ गए हैं। मतांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर का रक्तबीज नए-नए छांगुर पैदा कर रहा है। सिद्धि की कड़ी में राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ ने भी तीसरा स्थान पाकर अपना सिर ऊंचा किया है। डिजिटल अरेस्ट के मामले में देश में पहली सजा उत्तर प्रदेश के बदमाश देवाशीष राय को हुई है। प्रदेश की सफलता जल संरक्षण के क्षेत्र में भी खिलखिलाई है। सरोवरों के निर्माण में उत्तर प्रदेश यूं ही सरताज नहीं बन गया है। शासन और तंत्र की अदम्य जीवटता सफलता की कहानी सुना रही है। करतब और कारनामों के किस्से भी कम नहीं हैं। संभल की दो युवतियों की करतूत से सभ्य समाज आंखें पोछ रहा है।

सरोवरों में इच्छाशक्ति का अमृत : यूपी के खेत-तालाब मानसूनी बारिश से ही लबालब नहीं हैं, उपलब्धियों के शगुन से भी ऊभचूभ हैं। अमृत सरोवर निर्माण की दिशा में यूपी को प्रथम होने का खिताब हासिल हुआ है। वर्ष 2022 से शुरू हुई योजना में लक्ष्य तो साढ़े पांच हजार अमृत सरोवरों को बनाने का ही था, पर प्रदेश में इस समय तक 16,630 सरोवर बन चुके हैं जो लक्ष्य का तिगुना है। इस कड़ी में क्षेत्रफल से ज्यादा इच्छाशक्ति का महत्व है। तभी तो बिहार जैसा बड़ा राज्य (2,613 सरोवर) छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य (2902 सरोवर) से पीछे है। यूपी की इच्छाशक्ति के दूरगामी परिणाम होंगे। यह सद्प्रयास भूजल संवर्धन में भी सहायक होगा।

द केरल स्टोरी के नए-नए प्लाट : बलरामपुर में मतांतरण का ठिकाना बनाने वाले जलालुद्दीन उर्फ छांगुर, उसके सहयोगी नवीन और नीतू के कलंक से देश अब परिचित हो गया है, पर उसका रक्तबीज रोज-रोज पनप रहा है। छांगुर के छलिया रूप का परदा हट गया। अब उसके कुकृत्यों की परतें खुल रही हैं। हिंदू युवतियों को प्रेमजाल में फंसाकर उन्हें मतांतरण का शिकार बनाने का ठिकाना बलरामपुर के मधपुर गांव में छांगुर और उसकी सहयोगी नीतू नवीन रोहरा उर्फ नसरीन की कोठी थी जो ध्वस्त कर दी गई है, पर इसकी नींव बहुत गहरी है। पनामा गणराज्य से लेकर स्विस बैंक तक फैली जड़ को खाद पानी मुस्लिम देशों से खूब मिला है। अब तक 60 करोड़ रुपये की फंडिंग साबित हो चुकी है, फिर भी यूपी पुलिस, एटीएस और प्रवर्तन निदेशालय को अभी छांगुर की जड़ों का पता लगाने के लिए मिट्टी बहुत खोदनी पड़ेगी। कभी सड़कों पर नग और अंगूठियां बेचने वाला एक शख्स रुपये के बल पर दूसरे का धर्म नष्ट करने का दुस्साहस करे तो उसकी जड़ मिटनी ही चाहिए। अब तो आगरा, मुजफ्फरनगर में भी 'द केरल स्टोरी' का नया प्लाट ढूंढ निकाला गया है। आगरा के सदर बाजार से गायब हुई पंजाबी परिवार की दो बहनों को मतांतरण के जाल में फंसाने के लिए विश्वविद्यालय के खंदारी कैंपस में ही जाल बिछाया गया था।

समाज की विकृति पर पुलिस का अंकुश : इंटरनेट माध्यम का बेलगाम होना चिंताजनक है। अश्लीलता परोसने वालों के कुकृत्य पर यूपी पुलिस के प्रहार ने लोगों को राहत दी है। अभी शुरुआत है, पर इस सख्ती से नियमन कायम होगा। इंटरनेट मीडिया पर घोषित तौर पर अश्लीलता परोसने वाली संभल की बहनें मेहरुल निशा उर्फ परी व महक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके साथ ही बदायूं के दंपती को भी पुलिस ने पाबंद किया है। युवक को गिरफ्तार भी किया गया है। ये सारे लोग इंटरनेट मीडिया पर अश्लीलता परोस रहे थे। समाज मर्यादाबोध सिखाता है और नियंत्रित भी करता है, पर इंटरनेटजनित ऐसे अपकृत्य पर उसका वश कम ही चल पाता है। पुलिस ही समाज की ऐसी विकृति पर अंकुश लगा सकती है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है।

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या आइएनडीआइए से आम आदमी पार्टी का बाहर निकलना विपक्षी मोर्चे के लिए झटका है?

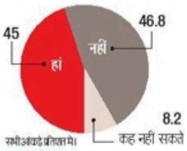

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या जस्टिस यशवंत वर्मा के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर सभी दलों को साथ आना चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

गहरी साजिश चल रही बदलाने की धर्म,
एक नहीं 'छांगुर' कई करते हैं यह कर्म।
करते हैं यह कर्म फंस रहे अपने बच्चे,
प्रगतिशील बन आप अक्ल के निकले कच्चे।
यदि बनकर सरकार रहेगी अंधी बहरी,
तो जनता हर बार सहेगी साजिश गहरी!
-ओमप्रकाश तिवारी

छत्तीसगढ़ डायरी

अंजोर की लक्ष्य प्राप्ति के लिए संघर्ष

सतीश चंद्र श्रीवास्तव
संपादकीय प्रभारी, रायपुर

अंजोर 2047 के विमोचन अवसर पर विष्णु देव साय और डा. रमन सिंह (बाएं से तीसरे व चौथे)। डीपीआर

विकसित छत्तीसगढ़ के लिए लक्ष्य तय करने वाला 'अंजोर विजन 2047' दस्तावेज मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 17 जुलाई की शाम प्रदेशवासियों को समर्पित कर दिया। अंजोर अर्थात दीप्तिमान या उज्जवल। छत्तीसगढ़ ऐसा करने वाला गुजरात के बाद दूसरा प्रदेश है। राज्य की जीडीपी को पांच लाख करोड़ से बढ़ाकर 75 लाख करोड़ तक पहुंचाने का सपना देखा गया है। रात गुजरी। अगले दिन सुबह पांच बजे ही भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल के गिरफ्तारी की सूचना पूरे प्रदेश में चर्चा के केंद्र में आ गई। कुछ उसी तरह जैसे सुख के साथ दुख, दिन के साथ रात, प्रकाश के साथ अंधकार का रिश्ता है।

अब कांग्रेस ने 22 जुलाई से प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया है कि सवाल बेटे की गिरफ्तारी का नहीं, प्रदेश में जल-जंगल-जमीन को बचाने का है। पार्टी के अंदर ही साथ में यह प्रश्न भी उठ खड़ा हुआ है कि कांग्रेस नेतृत्व ने आदिवासी नेता और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी के समय ऐसी सक्रियता क्यों नहीं दिखाई? वह तो अनपढ़ हैं। जनता ने लगातार पांचवीं बार विधायक बनाया है। उनके लिए ऐसी बेचैनी क्यों नहीं थी। इधर जन्मदिवस के दिन ही चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में 18 जुलाई से प्रदर्शन शुरू हो चुका है। केवल एक ही व्यक्ति हैं जो दोनों ही आयोजनों में भागीदार रहे।

नेता प्रतिपक्ष डा. चरणदास महंत ने शाम को 'अंजोर विजन 2047' की सफलता की कामना की तो दिन में भूपेश बघेल के साथ चैतन्य से मिलने कोर्ट पहुंचे। पार्टी के प्रभारी महासचिव सचिन पायलट की उपस्थिति में अपने ऊपर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका सही तरीके से नहीं निभाने के आरोप और बदले में विधानसभा सत्र में लाठी लेकर जाने की घोषणा करने वाले डा. महंत ने दावा किया कि टीआरपी के चक्कर में उन्हें भूपेश से अलग बताया जाता रहा है। पूरी पार्टी एकजुटता से संघर्ष करेगी।

प्रदेश बदलाव के दौर से गुजर रहा है। वर्ष 2023 के चुनाव से पहले प्रदेश ने पहली बार मतदाताओं को जातीय आधार पर बांटने का प्रयास देखा। भूपेश बघेल के नेतृत्व में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) को वोट बैंक के रूप में विकसित करने की रणनीति देखी। आरक्षण की बढ़ती सीमा देखी। सांप्रदायिक तनाव देखा। परंतु परिणाम उलटा हो गया। ओबीसी वर्ग में ही कुर्मी से ढाई गुना होते हुए भी उपेक्षित रहे साहू साथ छोड़ गए। कवर्धा-बेमेतरा में दंगों के बाद भाजपा महासचिव विजय शर्मा पहली बार ही चुनाव मैदान में उतरे और उप मुख्यमंत्री बन गए। देश को द्रौपदी मुर्मु के रूप में आदिवासी राष्ट्रपति के बाद विष्णु देव साय के रूप में मुख्यमंत्री मिल गए।

इधर कांग्रेस के समक्ष चुनौतियां बढ़ती ही जा रही हैं। भूपेश बघेल का विकल्प नहीं है। कोयला परिवहन घोटाला, शराब घोटाला, महादेव सट्टा एप घोटाला से लेकर पीएससी भर्ती घोटाले तक में चौतरफा घिरे भूपेश बघेल वर्तमान समय में भी प्रदेश के कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। प्रभारी महासचिव सचिन पायलट की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष डा. चरणदास महंत को निशाने पर लेने वाले बघेल के साथ खड़ा होना ज्ञात-अज्ञात कारणों से इन नेताओं की बाध्यता भी बनी हुई है। इन सबके बीच सिर्फ टीएस सिंहदेव ही अपने मुद्दे पर खड़े हैं और अड़े हैं। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उनसे किया वादा नहीं निभाया। वह अभी भी मान रहे हैं कि उन्हें ढाई साल मिल गए होते तो प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार होती और पार्टी सत्ता से बाहर भी नहीं होती।

प्रदेश को भ्रष्टाचार के अंधकार से विकास के 'अंजोर' की ओर ले जाने के लिए तैयार दस्तावेज को आम लोगों तक पहुंचाना बड़ी चुनौती है। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम से बड़े ही सरल शब्दों में कहा है कि 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ का सपना तभी साकार होगा जब प्रदेश के लगभग 60 लाख घरों तक यह दृष्टिपत्र पहुंच जाए। लगभग एक लाख लोगों के सुझावों से तैयार विजन डाक्यूमेंट को वह सरकारी से अधिक जनता का सुझाव पत्र मानते हैं जिसकी सफलता भी जनभागीदारी में ही सुनिश्चित है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय स्पष्ट हैं कि प्रदेश की पूरी जनता एकसाथ है। सनातनी व्यवस्था सब लोगों के सुखी होने और शांति की कामना करता है। उनके लिए दूसरी तरफ जाति और धर्म के आधार पर समाज के बंटे होने की दावा करने वाली राजनीतिक शक्तियां हैं। चर्चा चारों तरफ तैर रही है कि जब चैतन्य भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं तो भूपेश बघेल कब तक बचे रह पाएंगे। कहा जा सकता है कि प्रदेश की जनता चाहती है कि भ्रष्टाचार हुआ है तो भ्रष्टाचारियों को तुरंत सजा भी मिले। अंजोर और अंधेरे का संघर्ष जारी है।

21 hindi page6-lc_page 02.qxd 20-07-2025 19:27 Page 1

न्यायिक सुधार
चुनौतियां बरकरार

भारतीय न्यायपालिका को बॉलीवुड के एक मुहावरे में बयां किया जा सकता है - तारीख पे तारीख। अदालत में आप जीतें या हारें, सच्चाई यही है कि न्यायिक प्रक्रिया मुकदमों पर भारी पड़ती है। मुकदमे सालों-साल खिंचते रहते हैं, इस दौरान पैसा और ऊर्जा दोनों खत्म हो जाते हैं, जिससे मुकदमा लड़ना भी बेहद कष्टदायक हो जाता है। विडंबना यह है कि सरकार सबसे बड़ी मुकदमों में से एक है, जिससे अदालतों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। हालाँकि, कुछ राहत की उम्मीद है। भारत के कानूनी परिदृश्य में एक बड़े सुधार का संकेत देने वाली एक ऐतिहासिक पहल के तहत, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने एक व्यापक सुधार लागू किया है जिसका उद्देश्य भारतीय न्यायपालिका की सबसे पुरानी समस्याओं में से एक - देश में सबसे बड़ी मुकदमाकर्ता होने के नाते सरकार के अपने अतिक्रमण के कारण होने वाली देरी - से निपटना है। भारत सरकार द्वारा मुकदमों के कुशल और प्रभावी प्रबंधन के लिए निर्देश शीर्षक से जारी की गई यह नई मानक संचालन प्रक्रिया एक प्रशासनिक समायोजन से कहीं बढ़कर है। वर्षों से, भारत की न्यायपालिका भारी लंबित मामलों के बोझ तले दबी रही है, जहाँ अदालतों में 4.7 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं।

ये कानूनी विवाद अक्सर सेवा-संबंधी शिकायतों, नीतिगत अस्पष्टताओं, अनावश्यक अपीलों और खराब अंतर-विभागीय समन्वय का परिणाम होते हैं। नया निर्देश इस वास्तविकता को स्वीकार करता है और मंत्रालयों के लिए न्यायिक प्रक्रिया में सुधार हेतु एक विस्तृत, व्यवस्थित रोडमैप तैयार करके इसका सीधा समाधान करता है। इस निर्देश की नवीनता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अदालती मामलों को उनकी तात्कालिकता और प्रभाव के आधार पर वर्गीकृत करने का आह्वान है। कानूनी मामलों को अब अत्यधिक संवेदनशील, संवेदनशील या नियमित के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रमुख वित्तीय निहितार्थ या सार्वजनिक नीति से जुड़े मामलों को शीघ्र ही चिह्नित किया जाए और उच्चतम प्रशासनिक स्तरों पर निपटाया जाए।

साथ ही, यह निर्देश सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिकाएँ दायर करने को हतोत्साहित करता है - दुर्लभ और असाधारण मामलों को छोड़कर। इस सुधार का केंद्रबिंदु प्रत्येक मंत्रालय के भीतर कानूनी विशेषज्ञता का संस्थागतकरण है। प्रत्येक विभाग को अब एक कानूनी प्रकोष्ठ स्थापित करना होगा, जिसका नेतृत्व कानूनी प्रशिक्षण प्राप्त एक वरिष्ठ अधिकारी करेगा, और जिसे अनुबंध के आधार पर नियुक्त युवा पेशेवरों और विषय विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त होगा।

यह संरचना सरकार के कानूनी संचालन को पेशेवर बनाने के लिए डिजाइन की गई है, जो वर्तमान तदर्थ और प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण के स्थान पर एक अधिक सुविचारित और सूचित प्रक्रिया को अपनाएगी। यह निर्देश मध्यस्थता और पंचनिर्णय जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों को बढ़ावा देकर मुकदमेबाजी की प्रवृत्ति को रोकने का भी प्रयास करता है। अनुबंधों में मध्यस्थता की धाराओं को शामिल करके और एक केंद्रीकृत पंचनिर्णय पोर्टल बनाकर, सरकार विवादों को अधिक तेजी से और कुशलता से हल करने के लिए ठोस कदम उठा रही है।

यह सुधार पूरी तरह से तकनीक-आधारित है। सभी कानूनी मामलों पर अब कानूनी सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस) के माध्यम से नजर रखी जानी चाहिए, जो एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो मंत्रालयों को मुकदमेबाजी की निगरानी, वकीलों को भुगतान की प्रक्रिया, केस इतिहास पर नजर रखने और उभरते कानूनी रुझानों का पता लगाने में मदद करेगा।

यह प्रणाली पारदर्शिता और वास्तविक समय की जवाबदेही का वादा करती है, जिससे सरकार को अपने कानूनी परिदृश्य का एक स्पष्ट दृष्टिकोण मिलता है और वह जोखिमों का अधिक सक्रिय रूप से प्रबंधन करने में सक्षम होती है। यदि इसे पूर्णतः कार्यान्वित किया जाए तो यह भारतीय न्यायिक प्रणाली को एक बाधा से निकालकर समयबद्ध न्याय और उत्तरदायी शासन के प्रकाश स्तंभ में परिवर्तित करने में सहायक हो सकता है।

सुधार की दिशा में सराहनीय कदम

मुकदमों की संख्या कम करने की केंद्र सरकार की मंशा का हार्दिक स्वागत किया जाना चाहिए। देश की अदालतों में 70 प्रतिशत मामले सरकारों से जुड़े होते हैं, चाहे वह केंद्र में हो या राज्य में। दूसरी ओर, मुकदमों की सुनवाई और फैसले सुनाने में भी तेजी लाने की जरूरत है।

प्रफुल्ल गोराड़िया
लेखक, पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं।

अदालती मुकदमों की संख्या कम करने की केंद्र सरकार की मंशा का हार्दिक स्वागत किया जाना चाहिए। आखिरकार, देश की अदालतों में 70 प्रतिशत मामले सरकारों से जुड़े होते हैं, चाहे वह केंद्र में हो या राज्य में। दूसरी ओर, मुकदमों की सुनवाई और फैसले सुनाने में भी तेजी लाने की जरूरत है। प्रत्येक मामले पर खर्च किए गए समय का भी रिकॉर्ड होना जरूरी है।

शायद ऐसा नहीं किया जा रहा है, और अगर ऐसा है, तो इसे प्रकाशित तो बिल्कुल नहीं किया जाता, क्योंकि इससे कुछ न्यायाधीशों के साथ-साथ वकीलों को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। स्थगन देरी का मुख्य कारण है, और देरी न्याय के लिए अभिशाप है। इनका इस्तेमाल अक्सर सुनवाई की गति को धीमा करने या उसे रोकने के लिए किया जाता है। कई बार, इनका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि एक या दूसरे पक्ष का प्रमुख वकील किसी दूसरी अदालत में किसी दूसरे मामले में व्यस्त होता है - शायद किसी दूसरे शहर में भी।

अदालत के समय की बर्बादी के लिए, स्थगन चाहने वाले पक्ष से, मान लीजिए, प्रारंभिक राशि का 50 प्रतिशत, एक बार फिर से अदालती शुल्क लिया जाना चाहिए। जब मुवक्किल से यह शुल्क लिया जाएगा, तो उसे यह सबक मिलेगा कि वह ऐसे वकील को नियुक्त न करे जो इतना व्यस्त हो कि कई अन्य मामलों में उलझ जाए। बार-बार ऊपर की ओर अपील करने की स्वतंत्रता कम होनी चाहिए। कुछ मामले, मान लीजिए, मुंबई की किसी छोटी अदालत में शुरू हुए, सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँच गए हैं। सामान्यतः, प्रत्येक पक्ष को एक अपील की अनुमति दी जा सकती है। विशेष परिस्थितियों में, शायद दो पर विचार किया जा सकता है।

किसी मामले की सुनवाई शुरू होने से पहले, न्यायाधीश को दोनों वकीलों से परामर्श करके यह तय करना चाहिए कि उनमें से प्रत्येक को कितना समय दिया जाएगा। यदि कोई भी पक्ष अपनी सीमा से अधिक समय लेता है, तो उसे अतिरिक्त शुल्क देना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे टैक्सी से यात्रा करने पर होता है। अदालत को केवल इसलिए अपना समय क्यों बर्बाद करना चाहिए क्योंकि कोई वकील सोचने या अपनी बात कहने में धीमा है, या बार-बार अपनी बात दोहराता रहता है? एक आम आदमी के रूप में, मुझे आश्चर्य होता है कि वादी को आमतौर पर एक लंबा हलफनामा प्रस्तुत करके शुरुआत करनी पड़ती है।

किसी मामले की सुनवाई शुरू होने से पहले, न्यायाधीश को दोनों वकीलों से परामर्श करके यह तय करना चाहिए कि उनमें से प्रत्येक को कितना समय दिया जाएगा। यदि कोई भी पक्ष अपनी सीमा से अधिक समय लेता है, तो उसे अतिरिक्त शुल्क देना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे टैक्सी से यात्रा करने पर होता है। अदालत को केवल इसलिए अपना समय क्यों बर्बाद करना चाहिए क्योंकि कोई वकील सोचने या अपनी बात कहने में धीमा है, या बार-बार अपनी बात दोहराता रहता है?

पहली सुनवाई से एक रात पहले, जज हलफनामे में लिखी सारी बातें पढ़ते और समझते हैं। सुनवाई के दौरान, वकील जज और विरोधी वकील को मौखिक रूप से समझाता है कि हलफनामे में क्या लिखा है। क्या यह एक दोहराव वाली प्रक्रिया नहीं है? निश्चित रूप से, इसे कम किया जा सकता है? एक बार, मुझे कोलकाता के एक वकील और लंदन के एक वकील की एक मामले पर राय पढ़ने का मौका मिला। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ब्रिटेन का मसौदा लगभग 300 शब्दों में लिखा गया था, जबकि भारतीय मसौदा एक हजार से भी ज्यादा शब्दों का था। हम भारतीयों के लिए, अंग्रेजी में लिखना बुद्धिमता का आधार नहीं रहा है। चूंकि कानूनी काम का एक बड़ा हिस्सा लिखित रूप में लिखा जाता है, इसलिए यह जाँच का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाता है। संयोग से, फैसले या आदेश हमेशा संक्षिप्त या संक्षिप्त नहीं होते।

और अदालतों के काम के घंटों का क्या? या यूँ कहें कि अदालती तंत्र की अवधि का क्या? हालांकि कोई भी निष्ठुर नहीं होना चाहता, लेकिन देश भर की अदालतों के माननीय न्यायाधीशों का छुट्टियों पर जाना चर्चा का विषय बन गया है।

एक ऐसे देश में जहाँ न्याय व्यवस्था करोड़ों में लंबित मुकदमों से अटी पड़ी है, ऐसे न्यायिक अवकाशों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि न्यायाधीशों और वरिष्ठ वकीलों के लिए ये लंबी और नियमित छुट्टियाँ ब्रिटिश काल से चली आ रही हैं–एक ऐसा दौर जब एयर-कंडीशनिंग नहीं थी। भारत के मैदानी इलाकों की गर्मियाँ ज्यादातर न्यायाधीशों के लिए असहनीय होती थीं, और शिमला, दार्जिलिंग, ऊटी या कश्मीर की ठंडी घाटी जैसे पहाड़ी इलाकों में लंबी छुट्टियाँ बिताना समझ में आता था–लेकिन आज के जमाने में, जब तकनीक ने प्रकृति की कई चुनौतियों से पार पाना संभव बना दिया है, यह बात समझ से परे है।

देश की अदालतों में काम के वर्तमान घंटे भी, समय और श्रमशक्ति, दोनों के उपयोग के लिहाज से उत्साहजनक नहीं हैं। ज्यादातर अदालतें अपनी कार्यवाही सुबह 10:30 बजे या उसके आसपास शुरू करती हैं और शाम 4:30 बजे समाप्त होती हैं - यानी छह घंटे काम करती हैं, लेकिन प्रभावी रूप से पाँच घंटे, क्योंकि दोपहर के भोजन के लिए एक घंटे का अवकाश होता है। यहाँ शनिवार और रविवार की गिनती नहीं की जाती। न्यायाधीशों पर अत्यधिक बोझ और दिन-प्रतिदिन बढ़ते मुकदमों के ढेर को देखते हुए, न्यायपालिका में शिफ्ट प्रणाली लागू करने का समय आ गया है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि अदालतें शिफ्ट में काम न करें, जिससे न्यायाधीशों और वकीलों पर काम का बोझ कम हो, साथ ही कई बेरोजगार वकीलों और अन्य संबंधित कर्मचारियों के लिए रोजगार के अधिक अवसर सुनिश्चित हों।

देश में ऐसे कई वकील हैं जिन्हें इस तरह के कदम से लाभ होगा, क्योंकि इससे कानून बनाने और इस तरह देश की न्याय व्यवस्था को समाज के निचले तबके के लिए सुलभ बनाने में मदद मिलेगी।

बाद वाला बिंदु इतना स्पष्ट है कि यहाँ इस पर दोबारा चर्चा करना उचित नहीं है। भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश वाई के सभरवाल ने 2006 में कार्यभार कम करने के लिए अदालतों को दोहरी शिफ्ट में काम करने की आवश्यकता के विचार पर विचार नहीं किया था। देश के आम लोगों तक न्याय की पहुँच सुनिश्चित करना देश में न्यायिक सुधारों की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

केरल का प्राकृतिक सौंदर्य

शर्मिला वैद्य
लेखिका, शिक्षाविद हैं।

अलेप्पी के शांत बैकवाटर्स, जिसे अक्सर पूर्व का वेनिस कहा जाता है, क्योंकि यहां नारियल के पेड़ों से घिरी नहरों और लैगूनों का जटिल जाल बिछा है।

जब मेरे ट्रैवल एजेंट ने पुष्टि की कि केरल की हमारी यात्रा के लिए सब कुछ तैयार है, तो हम बहुत खुश हुए। बड़े उत्साह के साथ, हमने अपने सूटकेस पैक किए और कोच्चि के लिए अपनी उड़ान में सवार हो गए। हमारे ड्राइवर ने हवाई अड्डे पर हमारा गर्मजोशी से स्वागत किया, और इस तरह कोच्चि, मुन्नार, थेक्कडी और अल्लेप्पी से होकर हमारी अविस्मरणीय यात्रा शुरू हुई।

मुझे पहले से यह पता था कि केरल भारत के दक्षिण-पश्चिमी तट पर 3,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह कॉफी, चाय, मसाले, नारियल और रबर के निर्यात के लिए जाना जाता है। इसकी लंबी तटरेखा एक फलते-फूलते समुद्री भोजन उद्योग का समर्थन करती है। उत्कृष्ट व्यापार के अलावा, केरल में भारत में साक्षरता दर और जीवन प्रत्याशा भी सबसे अधिक है।

हालांकि, मुझे यह एहसास नहीं था कि केरल की सुंदरता को आंकड़ों और तस्वीरों में कैद नहीं किया जा सकता। कोई भी तस्वीर मुझे इसकी असीम भव्यता और अद्भुतता के लिए तैयार नहीं कर सकती थी।

परिदृश्य और ग्रामीण इलाके इतने प्राचीन और मंत्रमुग्ध कर देने वाले थे - कुछ ऐसा जो मुझे केवल प्रत्यक्ष अनुभव से ही समझ आया।

मुन्नार की हमारी यात्रा बिल्कुल लुभावनी थी। हरे-भरे चाय के बागानों से ढकी धुंधली, लहराती पहाड़ियां किसी तस्वीर वाले पोस्टकार्ड जैसी लग रही थीं। हम सचमुच बादलों के बीच से गुजर रहे थे। झरनों की कलकल ध्वनि हवा में गूंज रही थी, उत्साहित पर्यटक तस्वीरें ले रहे थे, और विक्रेता ताजा नारियल पानी बेच रहे थे–दुकानों में बिकने वाले किसी भी ऑर्गेनिक नारियल पानी से कहीं ज्यादा ताजगी देने वाला।

सबसे बढ़कर, बंदर सड़क किनारे बेफिक्री से बैठे थे, मानो पहाड़ियाँ उनकी हों, और वे शांत परिदृश्य में सहजता से घुल-मिल गए थे। आखिरकार हम मुन्नार पहुँच गए, एक मनमोहक हिल स्टेशन।

हम टॉल ट्रीज नामक जगह पर रुके, जहाँ कई तरह के ऊँचे फूलों वाले कैक्टस, पेड़, खूबसूरत लताएँ और जंगली फूल थे। हवा मीठी खुशबू, झरनों की आवाज और पक्षियों के चहचहाने से भरी हुई थी। वहाँ इतना सुकून और शांति थी–मानो समय थम सा गया हो। अपने दो दिनों के प्रवास के दौरान, हमने प्रसिद्ध कथकली नृत्य प्रदर्शन देखा। नर्तकों की वेशभूषा, भाव-भंगिमाएँ और सुंदर चालें मेरी उम्मीदों से कहीं बढ़कर थीं। हमने एक पारंपरिक मार्शल आर्ट प्रदर्शन भी देखा। मैं उनकी शक्ति और कौशल के अद्भुत ऊर्जावान प्रदर्शन से दंग रह गयी। मुन्नार की धुंधली, हरी-भरी पहाड़ियों से हम थेक्कडी और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य की ओर बढ़े।

नाव की सवारी हमें जंगल के भीतर ले गई। हालाँकि हमें ज्यादा जानवर नजर नहीं आए, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य से घिरे होने का अनुभव अद्भुत था। हमारा अगला पड़ाव एक मसाला बागान था।

यह जानना दिलचस्प था कि मसाले इतने सामंजस्य से कैसे उगते हैं। उनकी छाल, बीज, पत्ते, फलियां और जड़ें, सभी मसालों के रूप में इस्तेमाल की जाती थीं। उनकी सुगंध हवा में घुली रहती थी। इसके बाद, हम अलेप्पी के शांत बैकवाटर्स गए, जिसे अक्सर पूर्व का वेनिस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ नारियल के पेड़ों से घिरी नहरों और लैगूनों का जटिल जाल बिछा है। हमारी यात्रा का एक मुख्य आकर्षण बैकवाटर्स में हाउसबोट की सवारी थी। जैसे ही हम हरे-भरे धान के खेतों और लहराते ताड़ के पेड़ों के बीच से गुजरे, हमने ग्रामीणों को मछली पकड़ते, कुछ को छोटी डोंगियां चलाते और बच्चों को किनारे से खुशी से हाथ हिलाते देखा। जहाज पर हमें ताजा पकड़ा हुआ समुद्री भोजन परोसा गया, जिसे केरल के खास मसालों में पकाया गया था और केले के पत्तों पर परोसा गया था। हर भोजन असली और स्वाद से भरपूर था।

अलेप्पी ने हमें न सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता दिखाई, बल्कि स्थानीय जीवनशैली की भी झलक दिखाई। अंततः हम कोच्चि लौट आए, जहाँ मैंने पुर्तगाली प्रभाव वाली वास्तुकला की प्रशंसा की। शहर की समृद्ध विरासत इसके उत्कृष्ट मंदिरों, ऐतिहासिक सेंट फ्रांसिस चर्च और अलंकृत यहूदी आराधनालय में झलकती थी। मैं संस्कृति, परिदृश्य, संसाधनों और सरल, मेहमाननवाज लोगों के इस खूबसूरत मिश्रण को देखकर अभिभूत होकर घर लौटी।

जैसा कि किसी ने कहा था, कुछ जगहें न सिर्फ अपनी खूबसूरती से, बल्कि अपने एहसास से भी आपको मंत्रमुग्ध कर देती हैं। मेरे लिए, वह जगह केरल था।

आप की बात

कड़ी सजा के हकदार

हाल में ही बेंगलुरु, मुंबई एवं दिल्ली के सैंकड़ों स्कूलों और कॉलेजों को बम की झूठी धमकी बड़े ईमेल मिलना ना केवल बेहूदा एवं गैर कानूनी शरारत है बल्कि निर्दोष आमजन खासकर छात्रों के लिए मानसिक परेशानी पैदा करने वाला अनुचित कदम है धमकियाँ मिलने के उपरान्त पुलिस बल, बम निरोधक दस्तों, डॉग स्क्वॉड टीम एवं अग्निशमन विभाग सहित सुरक्षा में लगे लोगों ने सक्रियता दिखाते हुए तत्परता से जांच की और कहावत चरितार्थ हुई कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। ईमेल से मिली धमकियों से छात्रों के अभिभावकों को मानसिक आघात के लम्हों से गुजरना पड़ा एवं विद्या के मंदिरों की स्वच्छः छवि पर भी ग्रहण लगे बिना नहीं रह सका। इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियों को लगाम लगाने के लिए आईपीसीमें कई धाराओं जैसे कि 176, 353, 124, 281 आदि के तहत अपराध करने वालों से निपटने के लिए कानूनी प्रावधान हैं। यह तो भगवान का लाख शुक्र है कि ईमेल से आयी धमकी गीदड़ भभकी ही निकली हालांकि पुलिस ने स्कूल प्रबंधन के साथ तालमेल बिठाते हुए सुरक्षा संबंधी व्यवस्था की है, किन्तु इस तरह शासन, सरकार एवं स्कूल प्रबंधन के साथ छात्रों एवं उनके परिजनों को तनाव में लाने वाले घटिया सोच का बेहूदा प्रदर्शन करने वाले, किरदार कड़े कानूनों के दायरे में सजा के हकदार हैं।

- **युगल किशोर शर्मा**, फरीदाबाद

सराहनीय प्रदर्शन

अपने डेढ़ दशक के सड़क परिवहन मंत्री के कार्यकाल में कोई एक पैसे का भी दामन पर दाग नही लगने देने वाले करोडो की लागत की रोज सड़के बनाने वाले और जो बोला उसे करके दिखाने का दम भरने वाले नितिन गडकरी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में जब से सड़क परिवहन मंत्रालय का जिम्मा संभाला हे तब से देश के राष्ट्रीय राजमार्गों की सीरत और सूरत दोनों बदल गई है ! मसलन आज देश के किसी भी राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर कीजिये पेरिस और लन्दन से भी बेहतर आराम दायक सड़के मिलेंगी ! नितिन गडकरी और उनका मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों को बेहतर सुरक्षित और दुर्घटना रहित बनाने की दिशा में सतत प्रयासरत हैं ! हाल ही में देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा हेतू उच्च तकनीक वाले सीसीटीवी कैमरे लगाये जाने का निर्णय लिया है जो सड़क सुरक्षा के साथ साथ यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने और राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय साबित होगा ! राष्ट्रीय राजमार्गों को सीसीटीवी से लेंस कर दिया जायेगा तो बेलगाम तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वालो और गलत लेन में गाड़ी ड्राइव करने वाले लोगो की पहचान की में मदद मिलेगी साथ ही सड़क हादसों में भी कमी आएगी और राजमार्गों पर आये दिन सफर करने वाले लोगो के साथ चोरी डकेती लूटपाट और वाहनों में तोड़फोड़ करने वालो को आसानी से पहचाना जा सकेगा।

- **अरविंद रावल**, झाबुआ, मप्र

नैतिक मूल्यों का अभाव

आज हम समाज में नैतिक मूल्यों का नितान्त अभाव देखते हैं इसके लिए हम निःसंकोच आज की शिक्षा नीति और परिवार को दोषी ठहराते हैं यह कुछ सीमा तक सही भी है। किन्तु एक यक्ष प्रश्न यह भी है कि जब कभी विद्यालयों में भूले से भी कोई छात्र किसी सेवा कार्य में लगा दिख गया तो मीडिया उस समाचार को ब्रेकिंग न्यूज बना कर अपनी स्क्रीन पर ऐसे प्रदर्शित करता है जैसे कोई भूकम्प का समाचार हो। निःसंदेह आज बिखरते परिवारों में संस्कार मिलना असम्भव ही नहीं बल्कि संस्कार देना या लेना हीन समझा जाने लगा है। जब शिक्षाविद् या शिक्षानीति निर्धारक बच्चों में संस्कारों या महापुरुषों के चरित्र के पठन- पाठन की बात करते हैं तो वे ये क्यों भूल जाते हैं कि किसी भी महापुरुष का जीवन बिना गुरुसेवा , बिना समाजसेवा और बिना त्याग और संघर्ष के अधूरा है। भगवान राम से लेकर स्वामी विवेकानन्द तक कोई ऐसा महापुरुष नहीं हुआ जिसने गुरुचरणों में रहकर कठोर शारीरिक श्रम न किया हो। किन्तु आज यदि किसी छात्र के हाथ में झाड़ू, फावड़ा यहां तक कि शिक्षक को पानी पिलाते हुए या हैंडपंप भी चलाते हुए देख लिया तो उसे घोर अपराध की श्रेणी में मानकर तुरन्त वायरल करने में मीडिया देर नहीं लगाता। यही नहीं शिक्षा विभाग तो सम्बन्धित शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई करने में और भी अधिक स्फूर्ति दिखा अपनी पीठ थपथपाते हैं।

- **डॉ नरेंद्र टोंक**, मेरठ

भ्रष्टाचार की दीमक

बिहार में मतदाता सूची की स्थिति बेहद चिंताजनक है। 12 लाख मृत लोगों के नाम अब तक मतदाता सूची से नहीं हटाए गए, जबकि 17 लाख लोगों के पते बिना अद्यतन किए पुराने रिकॉर्ड में दर्ज हैं। लोकतंत्र के लिए यह अत्यंत चिंताजनक स्थिति मानी जा सकती है। निश्चित रूप से यह समस्या लंबे समय से चली आ रही है और इसका निवारण आवश्यक है। इससे भी अधिक गंभीर है 6 लाख दोहरे पंजीकरण वाले मतदाता, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुचिता पर सीधा प्रश्नचिन्ह लगाते हैं। कुल मिलाकर 35 लाख मतदाताओं के मामले में लापरवाही सामने आ रही है, जो निर्वाचन आयोग और राज्य प्रशासन की निष्क्रियता को उजागर करती है। आश्चर्य की बात है कि 8 बार मुख्यमंत्री रह चुके नीतीश कुमार ने भी मंइस मसले को अब तक गंभीरता से नहीं लिया है। एक ओर वह सुशासन बाबू कहलाने का दावा करते हैं, दूसरी ओर राज्य की बुनियादी लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही गड़बड़झाले में फंसी हुई है। मतदाता सूची में इस तरह की अनियमितताएं चुनाव की निष्पक्षता को संदिग्ध बना सकती हैं। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि वह चुनाव आयोग और संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह बनाएं ताकि लोकतंत्र की बुनियादी नींव मजबूत बनी रहे।

- **अमृत लाल मारू**, इंदौर